खतरनाक होती चारधाम यात्रा | बीमा कंपनियां हो जाएंगी बेलगाम | मील का पत्थर बनेगी नयी खेल नीति

नेशनल फ्रंटियर

RNI No.UTTHIN/2013/50587

वर्ष : 13, अंक : 04, जुलाई 2025 देहरादून

पृष्ठ : 52 मूल्य ₹10/-

डिजिटल इंडिया से क्रांतिकारी बदलाव

05 भारत को बड़ी सफलता

12 विमान हादसा और भाग्य का खेल!

43 कोहली की चमक से अलग रजत

47 रोमांटिक और कॉमेडी का तड़का

ORGANIC INDIA®
BOOST YOUR METABOLISM
with the delicate flavours of spices.
CERTIFIED ORGANIC
NATURALLY DETOXIFYING
NATURALLY DELICIOUS
#SavourTheFlavoursofHealth
with GREEN TEA, Ginger & Cinnamon
ORGANIC INDIA®
MADE WITH ORGANIC INGREDIENTS
TULSI DETOX KAHWA
Helps Improve Digestion & Detoxification
EARTH SEER
CONTAINS CAFFEINE
25N INFUSION BAGS
HEALTHY CONSCIOUS LIVING

'डिजिटल इंडिया' का लक्ष्य और दृष्टिकोण हो रहा साकार

'सबका साथ, सबका विकास' के संकल्प के अलावा, 'डिजिटल इंडिया' का लक्ष्य और दृष्टिकोण अब साकार होने लगा है क्योंकि यह वर्तमान सरकार के शासन का मूल बन गया है।

गरीबों, वंचितों और हाशिए पर पड़े वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई विस्तृत योजनाएं। 11 साल पहले देश में शुरू हुई डिजिटल क्रांति, लगभग हर नीति-निर्माण और जन कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन में शामिल हो गई है, जिसमें गरीबों, वंचितों और हाशिए पर पड़े वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए विस्तृत योजनाएं बनाई गई हैं।

सेवा वितरण और पारदर्शिता को काफी बढ़ावा मिला है। तकनीक सबसे गरीब लोगों के जीवन को सशक्त बनाने का एक साधन बन गई है। डिजिटल इंडिया मिशन ने किस तरह लाखों लोगों के लिए अवसर खोले हैं।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने पहले कार्यकाल में शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल ने पिछले दशक में देश के विकास और प्रगति के तरीके को नया आकार दिया है। शासन व्यवस्था पारदर्शी और हर नागरिक के लिए सुलभ हो गई है, जबकि इसने आम नागरिक के लिए बड़े पैमाने पर अवसर भी खोले हैं।

दस साल पहले, डिजिटल इंडिया की शुरुआत देश को डिजिटल रूप से सशक्त और तकनीकी रूप से उन्नत समाज में बदलने की पहल के रूप में हुई थी। एक दशक बाद, हम एक ऐसी यात्रा के साक्षी हैं जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की है। भारत ने 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक संकल्प से प्रेरित होकर डिजिटल भुगतान में कई प्रगति की है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को भी इस पहल से लाभ हुआ है। डिजिटल इंडिया ने भारत को तकनीकी रूप से सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में अभूतपूर्व योगदान दिया है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) मोदी सरकार की सबसे बड़ी पहचान है क्योंकि इसने करोड़ों गरीब परिवारों तक जन कल्याण निधि और योजनाओं की निर्बाध और रिसाव-मुक्त डिलीवरी सुनिश्चित की है। आज, गांवों में इंटरनेट सेवाओं की पहुंच है, जबकि डिजिटल भुगतान प्रणाली भी ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही है।

आज, डीबीटी के तहत 56 मंत्रालयों में 322 से अधिक योजनाएं शामिल हैं। लाभार्थियों के खातों में सीधे 44 लाख करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित किए जा चुके हैं, जबकि रिसाव को कम करके और बिचौलियों को रोककर 3.48 लाख करोड़ रुपये बचाए गए हैं। वहीं पिछले दस वर्षों में, डीबीटी हस्तांतरण में 90 गुना वृद्धि हुई है, जो गति और पारदर्शिता से युक्त जन कल्याण वितरण के एक नए युग को चिह्नित करता है। वहीं आधार - प्रत्येक नागरिक की एक विशिष्ट पहचान देश की डिजिटल पहचान क्रांति को शक्ति प्रदान कर रही है। आज, 140 करोड़ की आबादी के प्रत्येक नागरिक के पास एक विशिष्ट 12-अंकीय आधार संख्या है। आधार प्रमाणीकरण लेनदेन 150 बिलियन का आंकड़ा पार कर गया है।

जबकि डिजिलॉकर, एक ऐसा एप्लिकेशन जो दस्तावेजों को ऑनलाइन संग्रहीत करने की सुविधा देता है, ने कागज रहित शासन को मजबूत प्रोत्साहन दिया है। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, देश में 52 करोड़ से अधिक पंजीकृत डिजिलॉकर उपयोगकर्ता हैं, जिनके पास 852 करोड़ से अधिक दस्तावेज जारी किए गए हैं।

दस साल पहले, डिजिटल इंडिया की शुरुआत देश को डिजिटल रूप से सशक्त और तकनीकी रूप से उन्नत समाज में बदलने की पहल के रूप में हुई थी। एक दशक बाद, हम एक ऐसी यात्रा के साक्षी हैं जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की है। भारत ने 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक संकल्प से प्रेरित होकर डिजिटल भुगतान में कई प्रगति की है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को भी इस पहल से लाभ हुआ है। डिजिटल इंडिया ने भारत को तकनीकी रूप से सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। यह पहल न केवल डिजिटल अवसंरचना का विस्तार कर रही है, बल्कि डिजिटल नवाचार, वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और अन्य उन्नत तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका और मजबूत होगी, जिससे देश वैश्विक डिजिटल महाशक्ति के रूप में उभरेगा।

हेमंतराव बी खानविलकर
मुख्य संपादक

नेशनल फ्रंटियर

वर्ष : 13 अंक 04 जुलाई 2025

RNI NoÐ UTTHIN/2013/50587 ISSN 2324-2861

मुख्य संपादक	हेमंतराव बी खानविलकर
कार्यकारी संपादक	अंजन साबत
प्रबंध संपादक	उमा शंकर तिवारी
कानूनी सलाहकार	विजयेश नवानी
सह संपादक	रिद्धिका अग्रवाल
बिहार राज्य प्रमुख	पीयूष प्रसाद
फीचर संपादक	वसुंधरा पाण्डेय

विशेष संवाददाता

●दिल्ली से दुर्गेश तिवारी, मो. तारिक अवि, प्रदीप कुमार, ●भोपाल से कुलदीप तिवारी, ●रायपुर से जितेंद्र कुमार साहू ●लखनऊ से राजरतन सिंह ●पटना से राजेश कुमार ●चंडीगढ़ से सज्जन सिंह ●शिमला से राजीव रानावत, ●श्रीनगर से संजय काले ●कलकत्ता से वैभव वत्स ●जयपुर से प्रियेश हजानिया ●अहमदाबाद से मयंक जोशी, ●मुंबई से जया अग्रवाल ●नागपुर सरस खेलकर।

देहरादून कार्यालय

एस-17, दून विहार काम्पलेक्स राजपुर रोड, जाखन, देहरादून, उत्तराखंड, 248001

भुवनेश्वर कार्यालय

105, लोमिनी विला, ब्लाक 01, गोथापटना, भुवनेश्वर, उड़ीसा

इंदौर कार्यालय

178, पंचवटी कालोनी, एरोड्रम रोड, इंदौर, मध्यप्रदेश, 452002

मुंबई कार्यालय

407, जय अंबे सोसायटी, सी विंग, नियर मेगा माल, आनंद नगर जोगेश्वरी, वेस्ट मुंबई 400102

हैदराबाद कार्यालय

203 वीजीसी इंटरनेशनल, अपोजिट वेस्ट साइड माल, हिमायतानगर हैदराबाद 500020

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक हेमंतराव बी खानविलकर द्वारा एस-17, दून विहार काम्पलेक्स, राजपुर रोड, जाखन , देहरादून (उत्तराखंड) से प्रकाशित एवं शब्द संस्कृति प्रिंटर्स, चकराता रोड, देहरादून (उत्तराखंड) से मुद्रित।
संपादक : **हेमंतराव बी खानविलकर।**

RNI NO : UTTHIN/2013/50587

email : nationalfrontier@gmailÐcom,
संपर्क सूत्र (मो।) : +91 9897130210
+91 7065102037

नोट :मुद्रित सामग्री के लिए संपादक-प्रकाशक एवं प्रेस की सहमति अनिवार्य नहीं। सभी विवादों का न्यायक्षेत्र देहरादून होगा।

डिजिटल इंडिया से क्रांतिकारी बदलाव

06

10 मोदी युग में सांस्कृतिक पुनर्जागरण

विमान हादसा और भाग्य का खेल! 10

16 **भाषा, जाति, धर्म पर गुंडागर्दी का गौरवगान**

बीमा कंपनियां हो जाएंगी बेलगाम 26

32

सफल होगा 2028 का उज्जैन महाकुंभ!

36 मंदिरों में 'मुस्लिम घुसपैठ'

अलग चमकने वाला कप्तान 43

48

रोमांच और कॉमेडी का धमाल

भारत को बड़ी सफलता	05
डिजिटल इंडिया के स्वर्णिम 10 साल	08
मोदी युग में सांस्कृतिक पुनर्जागरण	10
खतरनाक होती चारधाम यात्रा	14
चरमराता जा रहा भारत का विमानन उद्योग	15
भारत बनेगा शस्त्र बाजार का नया खिलाड़ी	18
भविष्य के युद्धों के लिए तैयार होती भारतीय सेना	19
ईरान-इजराइल संघर्ष का वैश्विक प्रभाव	20
दलाई लामा के चयन में चीन का दखल नामंजूर	22
भारत के नए अंतरिक्ष युग की शुरुआत	23
चिराग का 'शक्ति प्रदर्शन' चुनौती	24
बीमा कंपनियां हो जाएंगी बेलगाम	26
भारत में पुराने वाहनों का मसला अलग है!	28
नीतीश सरकार देगी हथियार लाइसेंस	29
भारतीय गिग वर्कर्स के लिए नीति जरूरी	30
कथावाचक की आड़ में सनातन पर हमला	31
कैसे सफल होगा 2028 का उज्जैन महाकुंभ!	32
अपनी पहचान जाहिर करने में कैसी शर्म!	34
तिरुपति से शनि शिंगणापुर तक 'मुस्लिम घुसपैठ'	36
हम जो रंग पहनते हैं, वही जिंदगी जीते हैं	38
'विकास' के नाम पर मंदिर की कमाई पर लूट	39
झारखण्ड का अनोखा जंगली मशरूम पुटू	40
अपराध की दुनिया क्यों लगती है इतनी रोमांचक	42
कोहली की चमक से अलग चमकने वाला कप्तान	43
मील का पत्थर बनेगी नयी खेल नीति	44
जान पर भारी जवानी!	46
मिस वर्ल्ड रही हीरोइनों का फिल्मी करियर?	47
एक्शन, रोमांच और कॉमेडी का का तड़का	48
भगवान शंकर की पूजा का खास महीना	50

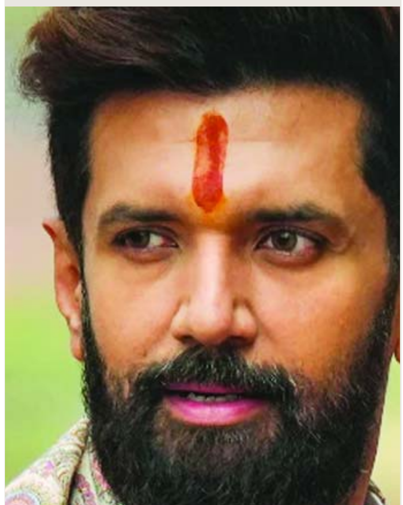

चिराग का 'शक्ति प्रदर्शन' चुनौती 24

विशेष आलेख

संजय विनायक जोशी

भारत ने यूएई से कच्चा तेल खरीदकर उसे भारतीय मुद्रा में भुगतान किया है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था और आम आदमी के लिए काफी राहत भरी खबर है। इसके साथ ही भारत ने अपनी मुद्रा को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिया है।

भारत को बड़ी सफलता

भारत को ग्लोबल मार्केट में बड़ी सफलता मिल गई है। लंबे समय से जारी कोशिश ने आखिर रंग दिखाना शुरू कर दिया और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) रुपये में लेनदेन करने वाला पहला देश बन गया है। भारत ने यूएई से कच्चा तेल खरीदकर उसे भारतीय मुद्रा में भुगतान किया है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था और आम आदमी के लिए काफी राहत भरी खबर है। इसके साथ ही भारत ने अपनी मुद्रा को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिया है।

मामले से जुड़े अधिकारियों ने कहा है कि भारत अन्य तेल आपूर्तिकर्ता देशों के साथ भी इसी तरह के रुपया भुगतान सौदों की कोशिश में लगा हुआ है लेकिन इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू करना एक प्रक्रिया है और इसके लिए कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है।फिलहाल हमें एक शुरुआत मिल गई है और यह काफी बेहतर है। हम यूएई से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदते हैं और रुपये में उसे भुगतान करने से बड़ी बचत होगी।

गौरतलब है कि अपनी 85 प्रतिशत से अधिक तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत आयात पर निर्भर है। इसके लिए उसे बड़े पैमाने पर डॉलर में भुगतान करना होता है लेकिन, पिछले साल से भारत ने तेल की खरीद का भुगतान डॉलर के बजाय रुपये में करने की व्यवस्था शुरू की है और इस दिशा में रिजर्व बैंक ने भी जरूरी कदम उठाए हैं। डॉलर में भुगतान करने पर भारत को मुद्रा विनिमय शुल्क यानी फॉरेक्स फीस चुकानी पड़ती है, जिससे यह सौदा काफी महंगा पड़ता है।

इस दिशा में भारत ने जुलाई में यूएई के साथ रुपये में भुगतान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) से 10 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद का भुगतान भारतीय रुपये में किया है। यह हजारों करोड़ रुपये की डील मानी जाती है।

इसके अलावा रूस से आयात किए गए कच्चे तेल के कुछ हिस्से का भी भुगतान रुपये में किया गया है। एक अधिकारी ने कहा, 'हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तेल खरीद का भुगतान रुपये में करने से लागत न बढ़े और इसका व्यापार पर किसी भी तरह से नुकसान न पड़े।' 'जहां रकम अधिक नहीं है, वहां रुपये में सौदा निपटान में ज्यादा समस्या नहीं होती है लेकिन, जब कच्चे तेल का जहाज लाखों डॉलर की कीमत का हो तो समस्याएं होती हैं। भारत व्यापक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए स्थिति से निपट रहा है।

अधिकारी ने कहा कि रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण से डॉलर की मांग कम करने में मदद मिलेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मौद्रिक झटकों का कम असर होगा। इसका फायदा आम आदमी को भी मिलेगा। जब देश का आयात सस्ता पड़ेगा तो यहां बिकने वाली आयातित वस्तुओं की कीमतों में भी कमी आएगी और उनके दाम सस्ते होंगे। अगर भारत कच्चे तेल की खरीद रुपये में करता है तो यह सस्ता पड़ेगा और इसका फायदा आम आदमी को भी होगा। फ्रं

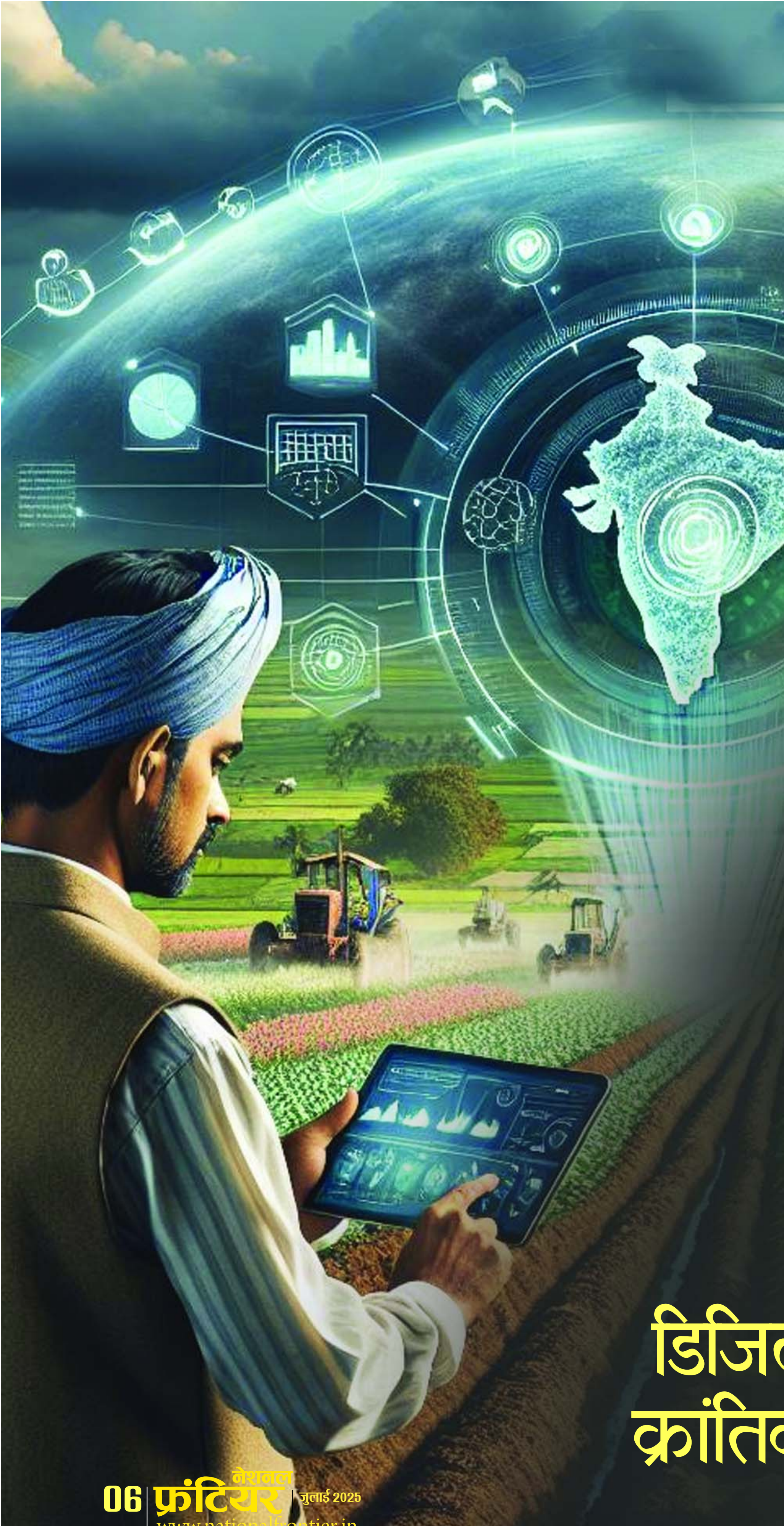

अंजन एस साबत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 साल पहले, 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया पहल की शुरुआत की थी। इसका मकसद भारत को डिजिटल रूप से सशक्त, समावेशी और तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्र बनाना था। इस पहल ने देश के हर कोने में तकनीक की पहुंच बढ़ाई और लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया। डिजिटल इंडिया ने भारत को विश्व की डिजिटल राजधानी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब 2014 में देश की सत्ता संभाली थी, तब उन्होंने एक सपना देखा था- भारत को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने का। उनका मानना था कि अगर तकनीक का सही इस्तेमाल हो, तो देश के हर नागरिक की जिंदगी आसान हो सकती है। इसी सोच से शुरू हुआ 'डिजिटल इंडिया' अभियान। आज, 11 साल बाद, गांव से लेकर शहर तक, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, हर किसी की जिंदगी में डिजिटल इंडिया ने क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। इस डिजिटल क्रांति ने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई है और देश को तकनीकी रूप से सशक्त, पारदर्शी और समावेशी बनाया है। आइए, जानते हैं कि पिछले 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया से हुए 11 बदलाव कैसे-कैसे हुए हैं।

डिजिटल इंडिया से क्रांतिकारी बदलाव

1. पैसे का लेन-देन- मोबाइल से मिनटों में

पहले पैसे भेजने के लिए बैंक जाना पड़ता था, चेक भरना पड़ता था या एटीएम के बाहर लाइन लगानी पड़ती थी। अब मोबाइल में यूपीआई, गूगल पे, फोनपे, पेटीएम जैसे ऐप्स आ गए हैं। गांव के किराना दुकानदार से लेकर शहर के बड़े मॉल तक, सब जगह क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट हो जाता है। गांव के पानवाले से लेकर ठेलेवाले तक, सब डिजिटल पेमेंट लेने लगे हैं। सरकार ने करोड़ों गरीबों के जनधन बैंक खाते खुलवाए, जिससे हर किसी के पास अपना बैंक अकाउंट है। इससे अब गैस सब्सिडी, पेंशन, छात्रवृत्ति, सरकारी मदद सीधा खाते में आती है। नकदी की झंझट खत्म होने से छुट्टे पैसे की टेंशन नहीं रहती और चोरी-डकैती का डर भी कम हो गया है।

2. सरकारी कामकाज - अब घर बैठे

पहले सरकारी दफ्तरों में लंबी लाइनें, बाबुओं के चक्कर, फाइलों का अंबार और घूस की समस्या आम थी। अब बहुत सी सरकारी सेवाएं मोबाइल या कंप्यूटर पर मिल जाती हैं। अब आप एक ही एप उमंग एप में पेंशन, पीएफ, बिजली-पानी का बिल, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार सहित 1200 से ज्यादा सरकारी सेवाएं पा सकते हैं। अब तो राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस - सब कुछ ऑनलाइन बनता है। कोई दिक्कत हो तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसे ट्रैक भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं अब जन्म प्रमाणपत्र, मार्कशीट, आधार, लाइसेंस जैसे अपने डॉक्यूमेंट्स डिजीलॉकर में ऑनलाइन रख सकते हैं, इसे जरूरत पड़ने पर कहीं भी दिखा सकते हैं।

3. शिक्षा- मोबाइल और टीवी पर पढ़ाई

कोरोना के समय स्कूल-कॉलेज बंद हो गए थे, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकी। मोबाइल, लैपटॉप या टीवी पर स्कूल-कॉलेज की ऑनलाइन क्लास होने लगी। ऐप्स पर हर क्लास का सिलेबस, वीडियो लेक्चर, नोट्स, क्विज सबकुछ फ्री में मिलता है। इससे गांव के बच्चों को भी फायदा हुआ है। पहले गांव के बच्चों को अच्छे टीचर नहीं मिलते थे, अब देश के टॉप टीचर्स के वीडियो गांव-गांव में देखे जा सकते हैं। शिक्षकों को भी डिजिटल तरीके से ट्रेनिंग मिल रही है, जिससे इनके पढ़ाई का तरीका बदला है। इतना ही नहीं डिजिटल लाइब्रेरी से किताबें, रिसर्च पेपर, मैगजीन सब ऑनलाइन पढ़ सकते हैं।

4. स्वास्थ्य सेवाएं- अब डॉक्टर मोबाइल पर

पहले गांव में डॉक्टर मिलना मुश्किल था, इलाज के लिए शहर जाना पड़ता था। अब ई-संजीवनी से मोबाइल या कंप्यूटर पर डॉक्टर से वीडियो कॉल पर सलाह मिल जाती है। टेलीमेडिसिन के कारण अब छोटे गांवों में रहने वाली लोग भी बड़े शहरों के डॉक्टर से बात कर सकते हैं। साथ ही अब दवाएं भी ऑनलाइन ऑर्डर करके घर मंगवा सकते हैं। डिजिटल हेल्थ कार्ड के जरिए अब हर मरीज का इलाज, दवा, रिपोर्ट- सबका रिकॉर्ड ऑनलाइन बन रहा है, जिससे इलाज में पारदर्शिता आई है। आपको याद होगा कि कोरोना के समय आरोग्य सेतु एप ने बीमारी की जानकारी, वैक्सीन अपडेट और आसपास के कोविड केस की जानकारी देकर आपकी कितनी मदद की थी। CoWIN ऐप ने देशभर में टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक संचालित किया। इस ऐप के माध्यम से नागरिकों को टीकाकरण की जानकारी, स्लॉट बुकिंग और प्रमाणपत्र प्राप्त करने की सुविधा मिली।

5. इंटरनेट- गांव-गांव तक पहुंचा

पहले गांव में इंटरनेट मिलना मुश्किल था, अब भारत नेट जैसी योजनाओं से गांव-गांव में ब्रॉडबैंड पहुंच गया है। बीएसएनएल के साथ जियो, एयरटेल जैसी कंपनियों ने डेटा बहुत सस्ता कर दिया है, जिससे अब हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। 5जी की शुरुआत के साथ ही अब इंटरनेट और तेज हो गया है, वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन गेमिंग, पढ़ाई, सब आसान हो गया। अब गांव के लोग भी ऑनलाइन किसान मंडी के दाम देख सकते हैं, महिलाएं घर बैठे सामान बेच सकती हैं और बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं।

6. किसानों के लिए डिजिटल क्रांति

किसानों के लिए भी डिजिटल इंडिया वरदान साबित हुआ है। किसान अब मोबाइल पर e-NAM से मंडी के दाम देख सकते हैं, अपनी फसल ऑनलाइन बेच सकते हैं। मोबाइल पर ही मौसम का हाल, बारिश की संभावना, फसल की सलाह सबकुछ मिल जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा, सब्सिडी जैसी सरकारी योजनाओं का का स्टेटस मोबाइल पर देख सकते हैं। इससे उन्हें बिचौलियों से मुक्ति मिली है। अब किसान सीधे खरीदार से जुड़ सकते हैं, जिससे उन्हें सही दाम मिलता है।

7. रोजगार और स्टार्टअप- नए मौके

डिजिटल इंडिया ने रोजगार और बिजनेस के नए रास्ते खोले हैं। अब कोई भी घर बैठे ऑनलाइन सामान बेच सकता है। स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू होने के बाद लाखों युवाओं ने नए-नए स्टार्टअप शुरू किए हैं। वे फूड डिलीवरी से लेकर एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस, ट्रैवल, गेमिंग आदि में कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। कंटेंट राइटिंग, डिजाइनिंग, ट्यूटरिंग, ट्रांसलेशन जैसे क्षेत्र में फ्रीलांसिंग कर अब लोग घर बैठे भी काम कर रहे हैं। इससे महिलाओं और दिव्यांगों को फायदा हुआ है, जो बाहर जाकर काम नहीं कर सकते। अब वे ऑनलाइन काम करके पैसे कमा रहे हैं। अब तो सरकारी और प्राइवेट नौकरियों के लिए आवेदन भी ऑनलाइन हो गया है।

8. सोशल मीडिया- हर किसी की आवाज

अब हर कोई फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर अपनी बात रख सकता है। अब कोई भी खबर मिनटों में देशभर में पहुंच जाती है। सरकार से सीधा संवाद करना आसान हो गया है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री तक सभी लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। अब आप उनसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। डिजिटल इंडिया के कारण सरकार, एनजीओ, आम लोग सभी सोशल मीडिया से जागरूकता फैला रहे हैं। स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ, कोविड वैक्सीनेशन जैसे अभियान इसके कारण सफल हो रहे हैं।

9. यात्रा और नागरिक सुविधाएं- पहले से आसान

अब यात्रा और रोजमर्रा की सुविधाएं भी डिजिटल हो गई हैं। ऑनलाइन टिकटिंग के कारण ट्रेन, बस, फ्लाइट की टिकट मोबाइल से बुक हो जाती है। डिजी यात्रा एप के कारण अब एयरपोर्ट पर फेस स्कैनिंग से एंट्री मिलती है, टिकट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिजली-पानी-गैस का बिल अब मोबाइल से भर सकते हैं। अब बिल भरने के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं रह गई है। अब ट्रैफिक, सफाई, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग सब कुछ स्मार्ट तरीके से मैनेज हो रहा है। कोई दिक्कत हो तो मोबाइल से शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसका स्टेटस देख भी सकते हैं।

10. भ्रष्टाचार पर लगाम और पारदर्शिता

डिजिटल इंडिया ने सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई है। डीबीटी- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण सरकारी पैसे सीधे लोगों के बैंक खाते में पहुंचते हैं, बीच में कोई घोटाला नहीं होता है। अब सरकारी खरीददारी, टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट सब ऑनलाइन होते हैं, जिससे घूसखोरी कम हुई है। पब्लिक फंड ट्रैकिंग सुविधा के कारण लोग देख सकते हैं कि उनके इलाके में सरकार ने कितना पैसा खर्च किया और कहां खर्च किया है। कोई दिक्कत हो या कोई भी सरकारी गड़बड़ी की शिकायत हो तो उसे ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं, और उसका हल भी देख सकते हैं।

11. भारत की दुनिया में नई पहचान

डिजिटल इंडिया की वजह से भारत अब दुनिया के टॉप डिजिटल देशों में गिना जाता है। भारत अब सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला देश बन गया है। बड़ी-बड़ी विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं, जिससे रोजगार और टेक्नोलॉजी दोनों बढ़ रहे हैं। यूपीआई, आधार जैसे डिजिटल पब्लिक गुड्स की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई टेक्नोलॉजी अब भारत में भी तेजी से आ रही हैं।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया ने देश की तस्वीर एकदम से बदल कर रख दी है। अब गांव-शहर, अमीर-गरीब, महिला-पुरुष, सबको तकनीक का फायदा मिल रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी पहले से आसान हो गई है। कुल मिलाकर, मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान ने देश के हर नागरिक को तकनीकी रूप से सशक्त किया है और भारत को 21वीं सदी का डिजिटल सुपरपावर बनाने की ओर मजबूती से बढ़ाया है।

नरेंद्र मोदी

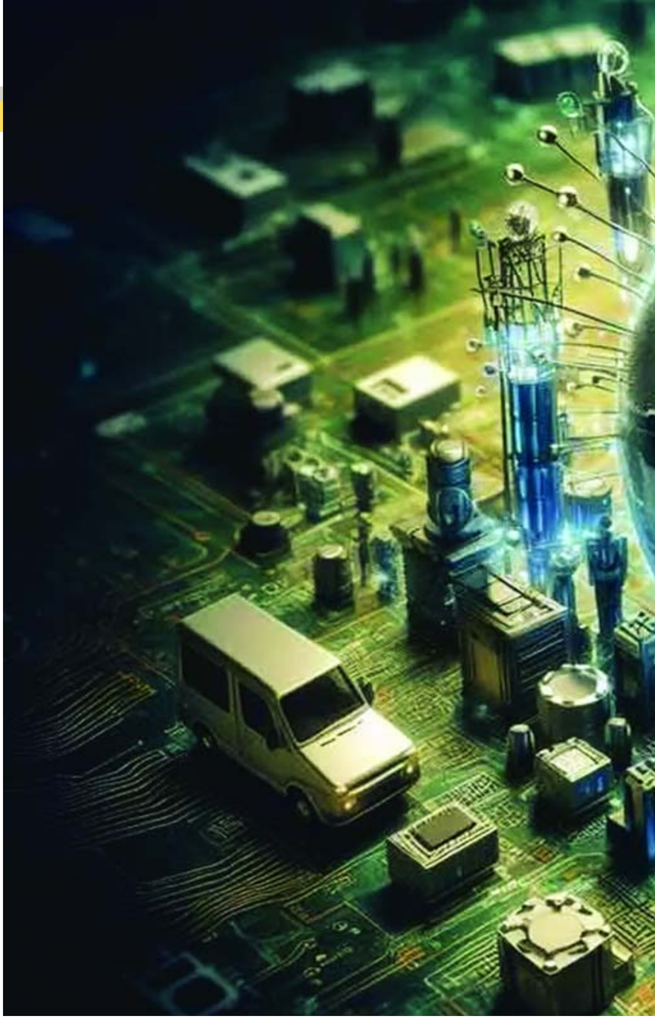

वर्ष 2014 में भारत में लगभग 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। आज यह संख्या बढ़कर 97 करोड़ से अधिक हो चुकी है। बयालीस लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का 11 गुना है, अब दूरस्थ गांवों को भी जोड़ रही है।

डिजिटल इंडिया के स्वर्णिम 10 साल

दस साल पहले हमने एक ऐसे क्षेत्र में पूर्ण विश्वास के साथ ऐसी यात्रा शुरू की थी, जहां पहले कोई नहीं गया था। जहां दशकों तक यह संदेह किया गया कि भारतीय तकनीक का उपयोग कर पायेंगे या नहीं, हमने उस सोच को बदला और भारतीयों की तकनीक का उपयोग करने की क्षमता पर विश्वास किया। जहां दशकों तक सिर्फ यह सोचा गया कि तकनीक का उपयोग अमीर और गरीब के बीच की खाई को और गहरा करेगा, हमने उस मानसिकता को बदला और तकनीक के माध्यम से उस खाई को खत्म किया। जब नीयत सही होती है, तो नवाचार वंचितों को सशक्त करता है। जब दृष्टिकोण समावेशी होता है, तो तकनीक हाशिये पर खड़े लोगों के जीवन में परिवर्तन लाती है।

यही विश्वास डिजिटल इंडिया की नींव बना

एक ऐसा मिशन, जो सभी के लिए पहुंच को लोकतांत्रिक (आसान) बनाने, समावेशी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए शुरू हुआ। वर्ष 2014 में इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, डिजिटल साक्षरता कम थी और सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन पहुंच बेहद सीमित थी।

कई लोगों को संदेह था कि भारत जैसा विशाल और विविध देश वास्तव में डिजिटल बन सकता है या नहीं। आज इस प्रश्न का उत्तर डाटा और डैशबोर्ड में नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के जीवन के माध्यम से दिया जा चुका है। शासन से लेकर शिक्षा, लेन-देन और निर्माण तक डिजिटल इंडिया हर जगह है।

डिजिटल डिवाइड को पाटते हुए

वर्ष 2014 में भारत में लगभग 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। आज यह संख्या बढ़कर 97 करोड़ से अधिक हो चुकी है। बयालीस लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का 11 गुना है, अब दूरस्थ गांवों को भी जोड़ रही है।

भारत का 5जी रोलआउट विश्व में सबसे तेज रोलआउट्स में से एक है, और मात्र दो वर्षों में 4.81 लाख बेस स्टेशन स्थापित किये गये हैं। हाई-स्पीड इंटरनेट अब शहरी केंद्रों से लेकर अग्रिम सैन्य चौकियों तक जैसे गलवान, सियाचिन और लद्दाख पहुंच चुका है। इंडिया स्टैक ने, जो हमारा डिजिटल बैकबोन है, यूपीआइ जैसे प्लेटफार्म को सक्षम बनाया है, जो अब सालाना 100 अरब से अधिक लेन-देन करता है।

विश्व में होने वाले कुल रियल-टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन में से लगभग आधे भारत में होते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 44 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे नागरिकों को हस्तांतरित की गयी है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई और 3.48 लाख करोड़ रुपये की लीकेज रोकी गयी है। स्वामित्व जैसी योजनाओं ने 2.4 करोड़ से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड्स जारी किये हैं और 6.47 लाख गांवों को मैप किया है, जिससे वर्षों से चली आ रही भूमि संबंधी अनिश्चितता का अंत हुआ है।

सभी के लिए अवसरों का लोकतंत्रीकरण

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था अब पहले से कहीं अधिक एमएसएमइ और छोटे उद्यमियों को सशक्त बना रही है। ओएनडीसी (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स) एक क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म है, जो विक्रेताओं और खरीदारों के विशाल बाजार से सीधा संपर्क स्थापित कर नये अवसरों की खिड़की खोलता है। जीइएम (गवर्नमेंट इ-मार्केटप्लेस) आम आदमी को सरकार के सभी विभागों को सामान और सेवाएं बेचने की सुविधा देता है। इससे न केवल आम नागरिक को एक विशाल बाजार मिलता है, बल्कि सरकार की बचत भी होती है।

कल्पना कीजिए कि आप मुद्रा लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं। आपकी क्रेडिट योग्यता को अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के माध्यम से आंका जाता है। आपको लोन मिलता है, आप अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। आप जीइएम पर पंजीकृत होते हैं, स्कूलों और अस्पतालों को सप्लाई करते हैं और फिर ओएनडीसी के माध्यम से इसे और बड़ा बनाते हैं। ओएनडीसी ने हाल ही में 20 करोड़ लेन-देन का आंकड़ा पार किया है, जिसमें पिछले 10 करोड़ सिर्फ छह महीनों में हुए हैं।

बनारसी बुनकरों से लेकर नगालैंड के बांस

डिजिटल इंडिया से आत्मनिर्भर भारत

पिछले एक दशक में 'डिजिटल इंडिया' पहल ने देशवासियों के जीवन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत, जो अत्यंत विविधतापूर्ण देश है, में इस पहल को बहुत संदेह की दृष्टि से देखा गया था। कुछ 'बुद्धिजीवी' तो यह दावा करते थे कि लोगों के पास अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए संसाधन नहीं हैं, लिहाजा वे डिजिटल तौर-तरीकों से दूर ही रहेंगे। हालांकि देशवासियों ने उन्हें पूरी तरह गलत साबित कर दिया। आज डिजिटल सेवाओं का बहुत विस्तार हो चुका है। एक दशक पहले लोगों को अपनी कई जरूरतों के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। 'डिजिटल इंडिया' ने उनकी जटिलताओं को दूर किया है। याद करें, वर्ष 2014 और उससे पहले बिजली का बिल चुकाने के लिए कितनी लंबी कतारें लगती थीं? बैंक से संबंधित किसी काम के लिए जाते थे तो कितना समय लगता था? रसोई गैस सिलेंडर लेने जाते तो कितने समय बाद बारी आती थी? सिनेमा, बस और ट्रेन की टिकटें लेने का अनुभव कैसा होता था? कई बार तो उन कतारों में धक्का-मुक्की, बहस आदि की वजह से झगड़े तक हो जाते थे।

अब डिजिटल इंडिया की वजह से विभिन्न सेवाएं तथा सुविधाएं मोबाइल फोन पर कुछ ही सेकंडों में आसानी से मिल जाती हैं। यह तो एक शुरुआत है। देश में डिजिटलीकरण का जिस तरह विस्तार होता जा रहा है, वह अगले दशक में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा। उस समय किशोरों और नौजवानों को आश्चर्य होगा कि उनके माता-पिता और घर के बड़े सदस्यों को कभी कतारों में लगना होता था,

दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे! मोदी सरकार को इस बात का श्रेय मिलना चाहिए, जिसने तमाम आलोचनाओं के बावजूद डिजिटलीकरण के जरिए सेवाओं तथा सुविधाओं का सरलीकरण जारी रखा। 'डिजिटल इंडिया' पहल की वजह से समय, संसाधन और ऊर्जा की बचत हुई है। पहले, बैंकिंग सेवाएं एक खास वर्ग तक सीमित थीं। ग्रामीण आबादी इससे वंचित थी। खाता खुलवाने से लेकर छोटी-छोटी सेवाओं के लिए लंबी कागजी प्रक्रिया होती थी। उस व्यवस्था ने कई बिचौलियों को जन्म दिया, जो जरूरतमंद लोगों से धन ऐंठते थे। सरकारें कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाती थीं, उनका बहुत बड़ा हिस्सा बिचौलिए और भ्रष्टाचारी खा जाते थे।

एक पूर्व प्रधानमंत्री ने तो स्वीकार किया था कि सरकार 100 पैसे भेजती थी तो उसमें से 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। अगर आज सरकार दूर-दराज के इलाके में रहने वाले किसी किसान के खाते में रुपए भेजती है तो उसे पूरी रकम मिलती है। एक पैसा भी कम नहीं होता। क्या यह देश की उपलब्धि नहीं है? क्या इससे भ्रष्टाचारियों पर लगाम नहीं लगी है? वास्तव में 'डिजिटल इंडिया' पहल किसी जन-आंदोलन से कम नहीं है। इसने परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। इसने मोबाइल फोन को कई जरूरतों का एक ठिकाना बना दिया है। भारत ने सबसे बड़ा कीर्तिमान तो डिजिटल लेनदेन के क्षेत्र में बनाया है।

यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म की सफलता से अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान जैसे देश हैरान हैं। एक वर्ष में 100 अरब से ज्यादा लेनदेन को संभालना कोई मामूली बात नहीं है। आधे 'रियल टाइम' डिजिटल लेनदेन का भारत में होना हमारे लिए गर्व का विषय है। जो देश तकनीक और संसाधनों के मामले में बहुत संपन्न माने जाते हैं, वे हमारे आस-पास भी नहीं हैं। आधार, डिजिलॉकर, कोविन और फास्टैग को दुनियाभर से सराहना मिल रही है। इंटरनेट ने हुनरमंद लोगों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। आज वे गांवों में रहकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। 'डिजिटल इंडिया' देशवासियों के सपनों को हकीकत में बदलने का संकल्प साबित हो रहा है।

शिल्पियों तक अब विक्रेता बिना बिचौलियों के पूरे देश में ग्राहक तक पहुंच रहे हैं। जीइएम ने 50 दिनों में एक लाख करोड़ रुपये का जीएमवी पार किया है, जिसमें 22 लाख विक्रेता शामिल हैं, जिनमें 1.8 लाख से अधिक महिला संचालित एमएसएमइ हैं, जिन्होंने 46,000 करोड़ रुपये की आपूर्ति की है।

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर : भारत का वैश्विक योगदान

भारत के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआइ)- जैसे आधार, कोविन, डिजिलॉकर, फास्टैग, पीएम-वाणी, और 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन'- को अब वैश्विक स्तर पर पढ़ा और अपनाया जा रहा है। कोविन ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सक्षम किया, जिससे 220 करोड़ क्यूआर सत्यापित सर्टिफिकेट जारी हुए। डिजिलॉकर, जिसके 54 करोड़ उपयोगकर्ता हैं, 775 करोड़ से अधिक दस्तावेजों को सुरक्षित और निर्बाध तरीके से होस्ट कर रहा है। भारत ने अपनी जी-20 अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल डीपीआइ रिपॉजिटरी और 2.5 करोड़ डॉलर का सोशल इम्पैक्ट फंड लॉन्च किया, जिससे कि अफ्रीका और दक्षिण एशिया के देश समावेशी डिजिटल इकोसिस्टम अपना सकें।

स्टार्टअप पावर और आत्मनिर्भर भारत

भारत अब विश्व के शीर्ष तीन स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल है, जिसमें 1.8 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। लेकिन यह सिर्फ एक स्टार्टअप आंदोलन नहीं है, यह एक टेक्नोलॉजी पुनर्जागरण है। भारत में युवाओं के बीच एआइ स्किल्स और एआइ टैलेंट के मामले में बड़ी प्रगति हो रही है, 1.2 अरब डॉलर इंडिया एआइ मिशन के तहत भारत ने 34,000 जीपीयू की पहुंच ऐसे मूल्य पर सुनिश्चित की है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम है- एक डॉलर से भी कम प्रति जीपीयू आवर। इससे भारत न केवल सबसे सस्ती इंटरनेट इकोनॉमी, बल्कि सबसे किफायती कंप्यूटिंग हब बन गया है। भारत ने मानवता-पहले एआइ की वकालत की है। नयी दिल्ली डिक्लरेशन ऑन एआइ जिम्मेदारी के साथ नवाचार को बढ़ावा देता है। देशभर में एआइ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किये जा रहे हैं।

आगे का रास्ता

अगला दशक और भी अधिक परिवर्तनकारी होगा। हम डिजिटल गवर्नेंस से आगे बढ़कर वैश्विक डिजिटल नेतृत्व की ओर बढ़ रहे हैं- इंडिया फर्स्ट से इंडिया फॉर द वर्ल्ड तक। डिजिटल इंडिया अब केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, यह जन आंदोलन बन चुका है। यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का केंद्र है, और भारत को दुनिया का विश्वसनीय नवाचार साझेदार बना रहा है।

सभी इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, और ड्रीमर्स से

दुनिया अगली डिजिटल क्रांति के लिए भारत की ओर देख रही है। आइए, हम वह बनायें, जो सशक्त बनाता है। आइए, हम ऐसे हल निकालें, जो वास्तव में मायने रखता है। हम उस तकनीक के साथ नेतृत्व करें, जो यूनाइट, इनक्लूड और अपलिफ्ट करती है। फ्रं

मोदी युग में सांस्कृतिक पुनर्जागरण

गजेन्द्र सिंह शेखावत

2014 में शुरू से ही यह स्पष्ट था कि मोदी सरकार के तहत संस्कृति अब सजावटी नहीं रहेगी, बल्कि यह मूलभूत होगी। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया था। अब दुनिया भर में लाखों लोगों को एक प्राचीन भारतीय परंपरा का जश्न मनाते देखा जा रहा है, जो शरीर, मन और आत्मा को आपस में जोड़ता है।

जनवरी 2024 में, जब पावन नगरी अयोध्या में सूर्योदय हुआ। सदियों से लुप्त हो चुकी प्रार्थना अब आखिरकार गुंजायमान होने लगी थी। श्री राम की अपने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महज एक धार्मिक उपलब्धि नहीं थी। यह सभ्यता के उद्धार का क्षण था। सदियों के आक्रमण, औपनिवेशिक विकृति और राजनीतिक देरी के बाद, मंत्रों से गूंजता हुआ और इतिहास के स्पंदन सहित, बलुआ पत्थर में उकेरा गया यह मंदिर शान से खड़ा था। यह सिर्फ वास्तुकला के बारे में नहीं था, यह एक घायल आत्मा के उपचार के बारे में था। श्री राम की अपनी जन्मभूमि पर वापसी ने उस राष्ट्र की आस्था को फिर से जागृत कर दिया, जिसने लंबे समय तक अपने दिल में निर्वासन की खामोशी को समेटे रखा था।

कुछ महीने पहले, भारत की प्राचीन आस्था का एक और प्रतीक चुपचाप अपने सही स्थान पर लौट आया। नई संसद के उद्घाटन के दौरान, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेंगोल को स्थापित किया। यह एक पवित्र राजदंड है, जिसे 1947 में तमिल अधीनमों ने सत्ता के धार्मिक हस्तांतरण को चिह्नित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू को भेंट किया था।

दशकों से, इसे भुला दिया गया था, समुचित स्थान से वंचित किया गया, और एक प्रचलित राजदंड के तौर पर खारिज कर दिया गया था। इसकी स्थापना केवल स्मरण का कार्य नहीं था - यह एक शक्तिशाली घोषणा थी कि भारत अब खुद को उधार की आंखों से नहीं देखेगा। सेंगोल ने साम्राज्य के अवशेषों का नहीं, बल्कि धार्मिकता पर आधारित शासन का प्रतिनिधित्व किया। यह भारत की अपनी राज्य कला और आध्यात्मिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण आलिंगन था, जिसे उपनिवेशवाद के बाद के क्रम में लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया था। इतना ही नहीं, इन क्षणों ने एक गहरे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संकेत दिया। यह एक सभ्यतागत गतिविधि के तौर पर ग्यारह परिवर्तनकारी वर्षों में सामने आएगी।

2014 में शुरू से ही यह स्पष्ट था कि मोदी सरकार के तहत संस्कृति अब सजावटी नहीं रहेगी, बल्कि यह मूलभूत होगी। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया था। अब दुनिया भर में लाखों लोगों को एक प्राचीन भारतीय परंपरा का जश्न मनाते देखा जा रहा है, जो शरीर, मन और आत्मा को आपस में जोड़ता है। योग केवल एक स्वास्थ्य संबंधी दिनचर्या भर नहीं है, बल्कि यह पिछले कुछ वर्षों में भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक निर्यात भी बन गया है।

आयुष मंत्रालय के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के पुनरुद्धार को संस्थागत बल दिया गया। इसके परिणामस्वरूप आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को राष्ट्रीय और वैश्विक मंचों पर पहुंचने में मदद मिली। समानांतर रूप से, सरकार ने संस्कृत, तमिल, पाली और प्राकृत जैसी शास्त्रीय भाषाओं को संरक्षित करने, पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और उस्ताद एवं हमारी धरोहर जैसी योजनाओं के तहत लुप्तप्राय लोक कलाओं और शिल्पों का समर्थन करने के लिए मिशन शुरू किए।

भारत की ऐतिहासिकों इमारतों में भी नई जान आ गई। 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण केवल व्यापकता के बारे में नहीं था, बल्कि एक गाथा को पुनः प्रतिष्ठित करने जैसा था। सरदार वल्लभभाई पटेल लंबे समय से ओझल हो रहे थे। उनको राष्ट्रीय स्मृति में सबसे आगे रखा गया। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक था। यह औपनिवेशिक प्रतीकवाद से देशी जवाबदेही की ओर बदलाव का भी प्रतीक था।

तमिलनाडु के महाबलीपुरम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग के बीच 2019 की अनौपचारिक शिखर वार्ता की तुलना में शायद कोई भी कूटनीतिक वार्ता इस बदलाव को बेहतर तरीके से नहीं दर्शाती है। दिल्ली के गलियारों से दूर, प्राचीन बंदरगाह का नगर, जो कभी पल्लव राजवंश और भारत-चीनी समुद्री संबंधों का एक संपन्न केंद्र होने के साथ-साथ दो सभ्यताओं के बीच वार्ता की पृष्ठभूमि बन गया। जब नेता चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों और पत्थर के रथों के बीच चले, तो भारत ने न केवल भूगोल, बल्कि इतिहास और न केवल प्रोटोकॉल, बल्कि विरासत को भी प्रस्तुत किया। यह अपने सबसे सूक्ष्म और सबसे मजबूत रूप में सॉफ्ट पावर था।

यह सांस्कृतिक लोकाचार अन्य तरीकों से भी भारत की वैश्विक कूटनीति में प्रवाहित हुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विश्व के नेताओं को राजकीय उपहार के

तौर पर पट्टचित्र पेंटिंग से लेकर बच्चों के लिए लाख के खिलौने भेंट किए गए, जो अपने साथ भारत के कारीगरों, कालातीत परंपराओं के संदेश लेकर गए।

2023 में जी-20 की अध्यक्षता एक और सांस्कृतिक उपलब्धि साबित हुई। दिल्ली के डिप्लोमेटिक हॉल तक सीमित न रहकर, यह शिखर सम्मेलन सांस्कृतिक पहचान का अखिल भारतीय उत्सव बन गया। आदिवासी कला प्रदर्शनों से लेकर शास्त्रीय प्रदर्शनों तक, भारत ने न केवल अपनी नीतिगत गहराई, बल्कि अपनी आत्मा का भी प्रदर्शन किया। हर प्रतिनिधिमंडल भारत के रंगों, व्यंजनों, शिल्प और चेतना में डूबा हुआ था। संदेश स्पष्ट था-भारत भूतकाल की सभ्यता नहीं है- यह जीवंत, सशक्त और आत्मविश्वास से परिपूर्ण वैश्विक सभ्यता है।

इन वर्षों के दौरान, 600 से अधिक चोरी की गई कलाकृतियां विदेशी संग्रहालयों और संग्रहकर्ताओं से वापस लाई गई, जिनमें मूर्तियां, शिलालेख और पांडुलिपियां शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक की वापसी न केवल कला की बल्कि सम्मान की बहाली थी। इसी तरह, गुरु गोविंद सिंह के वीर शहजादों की शहादत को याद करने के लिए वीर बाल दिवस की स्थापना की गई, जबकि जनजातीय गौरव दिवस ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को राष्ट्रीय केन्द्र में लाया।

महामारी भी सांस्कृतिक लौ को मद्धिम नहीं कर पाई। वर्चुअल कॉन्सर्ट, डिजिटल म्यूजियम टूर और 'मन की बात' के माध्यम से, प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया कि कला, कहानियां और सांस्कृतिक गौरव लॉकडाउन के एकांत में भी पुष्पित-पल्लवित होते रहें।

'विकास भी, विरासत भी' के नारे जैसे अभियान में ये सभी समाहित हो गए। यह एक आह्वान है जो आर्थिक विकास को सांस्कृतिक गौरव के साथ-साथ चलने पर जोर देता है। मोदी सरकार के तहत, यह नारा केवल बयानबाजी नहीं था। इसने एक नई दृष्टि को परिभाषित किया। एक दृष्टि, जिसमें जीडीपी वृद्धि, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा आधुनिकीकरण, मंदिर जीर्णोद्धार, आदिवासी गौरव और सभ्यता की गाथा समाहित थे।

भारत आज अपनी पहचान के इर्द-गिर्द नहीं घूमता। बिना किसी पछतावें और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर यह आगे बढ़ता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद प्रगति की बाध्यकारी शक्ति के रूप में उभरा है, जिसे कभी प्रतिगामी के रूप में खारिज कर दिया गया था। भाजपा के वैचारिक कम्पास में, संस्कृति केवल एक सहायक भर नहीं है, बल्कि धुरी है।

इन ग्यारह सालों में मोदी युग ने केवल सांस्कृतिक नीति को ही ध्यान में नहीं रखा है, बल्कि इसने सांस्कृतिक चेतना को भी जागृत किया है। जो पुनर्स्थापना के तौर पर शुरू हुआ था, वह पुनरुत्थान बन गया। जिन्हें कभी अतीत की स्मृतियों के तौर पर उपेक्षित किया जाता था, वे सभी अब राष्ट्रीय पहचान के केंद्र बन गए हैं।

राम मंदिर और सेंगोल हमेशा सांकेतिक प्रतीक बने रहेंगे, लेकिन विरासत की गहराई सामूहिक अहसास में निहित है। भारत का भविष्य तब सबसे उज्ज्वल होगा, जब वह याद रखेगा कि वह कहां से आया है। हम सिर्फ एक लंबा इतिहास वाला देश नहीं हैं, बल्कि हम एक लंबी स्मृति वाली जीवित सभ्यता हैं। और उस स्मृति में, धर्म की निगरानी में, भारत ने फिर से अपनी आवाज पाई है। फ्रं

टीके वैमानिकी विशेषज्ञ, के अनुसार विमान दुर्घटना में जीवित रहने की संभावना सीट की स्थिति, दुर्घटना का प्रकार और त्वरित निर्णय लेने पर निर्भर करती है। विश्वास की सीट आपातकालीन निकास के पास थी, जो कि बिना किसी बड़े नुकसान के ज़मीन पर जा गिरी और उन्हें बाहर निकलने का मौका मिला। इसके अलावा, उनकी त्वरित प्रतिक्रिया और भाग्य ने भी उनकी जान बचाई।

विनीत नारायण

विमान हादसा और भाग्य का खेल!

अहमदाबाद में हुई भयानक विमान दुर्घटना के बाद भारत सरकार ने इस दुर्घटना की जाँच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की है और विमान निर्माण कंपनी बोइंग ने भी सहयोग की पेशकश की है। अन्य विदेशी जांच एजेंसियां भी इस जांच में जुट गई हैं। हवाई जहाज़ के निर्माण में बोइंग एक रसूखदार कंपनी है। बावजूद इसके बोइंग की कार्यक्षमता पर सवाल उठते रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक फ़िल्म वायरल हो रही है कि बोइंग कंपनी के ही एक इंजीनियर जॉन बार्नेट, जिसने बोइंग की अंदरूनी क्षमताओं पर महत्वपूर्ण सवाल उठाए थे, उसे 2024 में रहस्यमय परिस्थितियों में बोइंग कंपनी की ही कार पार्किंग में मृत पाया गया।

जब किसी विमान दुर्घटना में पायलट भी मारे जाते हैं तो एक आम चलन है कि पावरफुल लॉबी साँठ-गाँठ करके जाँच का रूख इस तरह मोड़ देती हैं कि दुर्घटना के लिए पायलट को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्योंकि वो अपना पक्ष रखने के लिए अब जीवित नहीं होता। इसलिए ज़रूरी है कि सभी जाँच एजेंसियां इस दुर्घटना की पूरी ईमानदारी से जाँच करें। दुनिया भर में लाखों लोग बोइंग कंपनी के हवाई जहाज़ों में रोज़ उड़ रहे हैं। उन सबकी सुरक्षा के हित में भी यह ज़रूरी है कि बोइंग कंपनी उसके विरुद्ध अक्सर लगाए जाने वाले सभी आरोपों का स्पष्ट जवाब दे और यदि उसकी निर्माण प्रक्रिया में ख़ामियाँ हैं तो उन्हें अविलंब सुधारे।

12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुई भयानक विमान दुर्घटना में जीवित बचे विश्वास कुमार रमेश ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। एयर इंडिया की फ्लाइट ढ्ढ 171 के इस दुखद हादसे में 242 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में से 241 की मौत हो गई और केवल एक यात्री, विश्वास कुमार रमेश जीवित बचा। यह घटना विमान दुर्घटनाओं में एकमात्र बचे लोगों की उन असाधारण कहानियों में से एक है, जो न केवल चमत्कार को दर्शाती हैं, बल्कि मानव की जीवटता और भाग्य की अनिश्चितता को भी उजागर करती हैं।

विश्वास कुमार रमेश, 40 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक हैं, जो भारतीय मूल के हैं। उस दिन सीट नंबर 11 ए पर बैठे थे, जो एक आपातकालीन निकास द्वार के पास थी। हादसे के तुरंत बाद विश्वास ने भारतीय मीडिया को बताया कि, ÷मैं यह नहीं समझ पा रहा कि मैं कैसे बच गया। सब कुछ मेरी आँखों के सामने हुआ। मैंने सोचा कि मैं भी मर जाऊँगा, लेकिन जब मैंने आँखें खोलीं, तो मैंने खुद को जिंदा पाया।÷ उन्होंने बताया कि उनकी सीट के पास का हिस्सा जमीन पर गिरा और आपातकालीन निकास द्वार टूट गया था, जिसके कारण वे बाहर निकल पाए। विमान का दूसरा हिस्सा इमारत की दीवार से टकराया था, जिसके कारण वहाँ से निकलना असंभव था।

विमान दुर्घटनाओं में एकमात्र बचे लोगों की कहानियाँ बेहद दुर्लभ हैं, लेकिन ये मानव की जीवटता और कभी-कभी भाग्य के खेल को दर्शाती हैं। इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएँ दर्ज हैं, जिनमें एकमात्र व्यक्ति ही जीवित बचा। जूलियन कोएपके 17 साल की एक जर्मन लड़की थी जो 1971 में पेरू के अमेज़न जंगल में हुई लांसा फ्लाइट 508 की दुर्घटना में एकमात्र जीवित बची थी।

विमान 10,000 फीट की ऊँचाई से गिरा और जूलियन अपनी सीट से बंधी हुई जंगल में जा गिरी। गंभीर चोटों के बावजूद वह 11 दिनों तक जंगल में भटकती रही और अंततः मदद मिलने पर बच गई। उसकी कहानी साहस और जीवित रहने की इच्छाशक्ति का प्रतीक बन गई। वेस्ना वुलोविच, एक सर्बियाई फ्लाइट अटेंडेंट थी जो 1972 में छ्ठ्ठ फ्लाइट 367 के मध्य हवा में हुए विस्फोट के बाद एकमात्र ज़िंदा बची थी। वह 33,000 फीट की ऊँचाई से गिरने के बावजूद जीवित रही, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। वेस्ना को गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन वह ठीक हो गई और बाद में अपनी कहानी साझा की।

चार साल की सेसिलिया सिचन 1987 में नॉर्थवेस्ट एयरलाइंस फ्लाइट 255 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एकमात्र ज़िंदा बची थी। यह विमान मिशिगन में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 154 यात्री और चालक दल के सदस्य मारे गए। सेसिलिया को मलबे में दबा हुआ

पाया गया और उनकी जान बचाने के लिए व्यापक उपचार किया गया। 12 साल की बाहिया बकारी 2009 में येमेनिया एयरवेज की उड़ान के कोमोरो द्वीप समूह के पास दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एकमात्र ज़िंदा बची थी। वह समुद्र में तैरती रही और बाद में बचाव दल द्वारा बचा ली गई। उसकी कहानी भी दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी।

विमान दुर्घटनाओं के अलावा, अन्य दुखद हादसों में भी एकमात्र बचे लोगों की कहानियाँ सामने आई हैं। 1912 में टाइटैनिक के डूबने में कई लोगों की जान गई। लेकिन कुछ लोग, जैसे कि मिल्विना डीन, जो उस समय केवल दो महीने की थी, जीवित बची। वह उन अंतिम लोगों में से थी जो इस त्रासदी से बची थीं। 2004, हिंद महासागर सुनामी की प्राकृतिक आपदा में लाखों लोग मारे गए, लेकिन कुछ लोग, जैसे कि एक इंडोनेशियाई व्यक्ति जिसे लहरों ने समुद्र में बहा दिया था, चमत्कारिक रूप से जीवित बच गए।

विमान दुर्घटना या अन्य त्रासदियों में एकमात्र बचे लोग अक्सर 'सर्वाइवर्स गिल्ट' (जीवित रहने का अपराधबोध) से गुजरते हैं। विश्वास कुमार रमेश ने भी बताया कि वह अपनी जान बचने के बावजूद अपने भाई को खोने के दुख से जूझ रहे हैं। जॉर्ज लैमसन जूनियर, जो 1985 में गैलेक्सी एयरलाइंस की दुर्घटना में एकमात्र बचे थे, ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह विश्वास की स्थिति को समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएँ जीवित बचे लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे लोग अक्सर पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (क्क्षस्ठ) से पीड़ित हो सकते हैं। विश्वास के मामले में, डॉ. रजनीश पटेल ने बताया कि वह 'पोस्ट-ट्रॉमेटिक अम्नेसिया' से प्रभावित हो सकते हैं, जिसके कारण उन्हें दुर्घटना की पूरी तस्वीर याद नहीं है।

विश्वास कुमार रमेश का जीवित रहना कई कारकों का परिणाम हो सकता है। प्रोफेसर जॉन हंसमैन, एम आई टी के वैमानिकी विशेषज्ञ, के अनुसार विमान दुर्घटना में जीवित रहने की संभावना सीट की स्थिति, दुर्घटना का प्रकार और त्वरित निर्णय लेने पर निर्भर करती है। विश्वास की सीट आपातकालीन निकास के पास थी, जो कि बिना किसी बड़े नुकसान के ज़मीन पर जा गिरी और उन्हें बाहर निकलने का मौका मिला। इसके अलावा, उनकी त्वरित प्रतिक्रिया और भाग्य ने भी उनकी जान बचाई।

विश्वास कुमार रमेश की कहानी, अन्य एकमात्र बचे लोगों की तरह, हमें जीवन की नाजुकता और चमत्कारों की संभावना की याद दिलाती है। ये कहानियाँ न केवल प्रेरणादायक हैं, बल्कि विमानन सुरक्षा में सुधार की आवश्यकता को भी उजागर करती हैं।

देश जहां सबसे अधिक हुए विमान हादसे

भारत में बीते 10 साल में यह सबसे बड़ा विमान हादसा है. हालांकि अगर सबसे ज्यादा प्लेन क्रैश की बात करें तो लिस्ट में भारत बहुत पीछे। इस सूची में सबसे आगे अमेरिका है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश होने की घटना से पहले बीते 10 साल में सबसे बड़ा विमान हादसा 2020 में हुआ था जब दुबई से लौट रही फ्लाइट केरल में बारिश के बीच रनवे में फिसलकर दो टुकड़ों में बंट गई थीं। हादसे में 21 लोगों की मौत हुई थी। उस विमान में 190 यात्री सवार थे, जबकि अहमदाबाद में जो विमान हादसे का शिकार हुआ उसमें क्रू समेत 242 यात्री थे।

विमान हादसों की बात करें तो सबसे ज्यादा विमान हादसे अमेरिका में होते हैं। इस बारे में Statista ने पिछले साल एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें 1945 से लेकर 2022 तक के आंकड़े शामिल किए गए थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में बीते 77 साल में कुल 864 विमान हादसे हुए हैं, यानी हर साल तकरीबन 11-12 हादसे अमेरिका में होते हैं, जबकि 539 हादसों के साथ रूस दूसरे नंबर पर है। इसके बाद 191 हादसे कनाडा में, 190 विमान हादसे ब्राजील में हुए हैं। इस मामले में पांचवें नंबर पर कोलंबिया है जिसमें 184 विमान हादसे हुए, जबकि यूके में 110 हादसे हुए हैं। इंडोनेशिया में 106, फ्रांस में 105, मैक्सिको में 102 विमान हादसे पिछले 77 साल में हुए हैं।

10वें नंबर पर है भारत, फिर चीन

Statista की रिपोर्ट के मुताबिक विमान हादसों के मामलों में भारत 10 वें नंबर पर है, यहां 77 साल में महज 95 विमान हादसे हुए हैं, जबकि भारत के ठीक बाद चीन का नंबर है, चीन में 76 प्लेन क्रैश हुए हैं। इसके बाद 68 विमान हादसों के साथ इटली है। 1945 से 2022 तक की इस रिपोर्ट में सबसे कम हादसे अर्जेंटीना में बताए गए हैं, जहां 77 साल में महज 43 प्लेन क्रैश हुए हैं।

स्टेटिस्टा की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 77 साल में सबसे कम विमान 2020 में उड़े, मगर सबसे ज्यादा हवाई हादसे और इनसे मरने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में उड़ानों की कुल संख्या 57 प्रतिशत घटी थी, मगर हर साल हवाई दुर्घटना में होने वाली मौतों के लिहाज से आधी से ज्यादा मौतें जनवरी में ही हो गई थीं, जब यूक्रेन का एक विमान ईरानी हवाई क्षेत्र में हादसे का शिकार हुआ था। हादसे में 176 यात्रियों की जान गई थी। इसके बाद दूसरा बड़ा हादसा मई माह में पाकिस्तान में हुआ था, जहां हादसे में 97 लोगों की मौत हो गई थी।

अगर एशिया में विमान हादसों से होने वाली मौतों की बात करें तो इंडोनेशिया सबसे आगे है।रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 25 साल में इंडोनेशिया में 20 से ज्यादा बड़े विमान हादसे हुए हैं, इनमें तकरीबन 2 हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके बाद नंबर है रूस का, जहां 30 से ज्यादा हवाई हादसे हुए हैं और एक हजार से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। भारत में 15 से ज्यादा और पाकिस्तान में 8 से ज्यादा विमान हादसे हुए हैं, इनमें 500 से ज्यादा यात्रियों की जान गई है।

15 जून की सुबह 5.18 पर केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए 407 हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, जो कि आमतौर से 10 मिनट की यात्रा है। चंद मिनट बाद ही यह हेलिकॉप्टर गुप्तकाशी के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया इसमें 7 लोगों की मौत हुई।

विजय कपूर

खतरनाक होती चारधाम यात्रा

आर्यन एविएशन द्वारा चलाए जाने वाले बेल 407 हेलिकॉप्टर ने 15 जून की सुबह 5.18 पर केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरी, जो कि आमतौर से 10 मिनट की यात्रा है। चंद मिनट बाद ही यह हेलिकॉप्टर गुप्तकाशी के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें सवार सभी 7 व्यक्तियों की मौत हो गई, जिनमें पांच तीर्थयात्री थे। मृतकों में जयपुर के रहने वाले 37-वर्षीय पायलट कैप्टन राजवीर सिंह चौहान भी हैं, जिन्होंने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर होने के बाद अक्टूबर 2024 में आर्यन एविएशन ज्वाइन की थी। उन्हें 2,000 से अधिक उड़ान घंटों का अनुभव था।

वह अपने पीछे अपनी पत्नी (जो सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं) और चार माह के जुड़वा बच्चे छोड़ गए हैं। मृतकों में महाराष्ट्र के यवतमाल निवासी जायसवाल दंपति व उनका 23 माह का बच्चा भी शामिल था। प्रारंभिक जांच से मालूम होता है कि घने बादलों के कारण पायलट को कुछ दिखाई नहीं दिया और वह पहाड़ से टकरा गए। वैसे इस दुर्घटना के सही कारणों की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इंवेस्टीगेशन ब्यूरो करेगा। रुद्रप्रयाग पुलिस ने आर्यन एविएशन के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।

इस वर्ष की चारधाम यात्रा के दौरान यह दूसरी भयावह हेलिकॉप्टर दुर्घटना है। इससे पहले 9 मई को गंगोत्री जा रहा हेलिकॉप्टर गंगनानी के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। इस तरह मृतकों की संख्या 13 हो गई है। चारधाम यात्रा के दौरान पिछले 39 दिनों के दौरान कुल पांच हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं।

12 मई को हेलिकॉप्टर तीर्थयात्रियों को सरसी से लेकर बद्रीनाथ लौट रहा था कि उसे उखीमठ के एक स्कूल के खेल के मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। 17 मई को एम्स ऋषिकेश की हेली-एम्बुलेंस केदारनाथ हेलीपैड के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गई, क्योंकि उसका पिछला हिस्सा खराब हो गया था। 7 जून को केदारनाथ जा रहे हेलिकॉप्टर को सड़क पर ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, क्योंकि टेक-ऑफ करते ही उसमें तकनीकी खराबी आ गई और पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटनाएं चीख-चीखकर कह रही हैं कि चारधाम के तीर्थयात्रियों के लिए हेलिकॉप्टर का सफर सुरक्षित बनाया जाए।

न एयर ट्रैफिक कंट्रोल न ही राडार

सवाल यह है कि चारधाम यात्रा के दौरान हेलिकॉप्टर इतनी निरंतरता के साथ दुर्घटनाग्रस्त क्यों हो रहे हैं? इसके अनेक कारण हैं। केदारनाथ में न एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, न राडार कवरेज है और न ही रियल टाइम में मौसम की मॉनिटरिंग होती है, इसके बावजूद यात्रा के दौरान रोजाना ही हेलिकॉप्टर अंदर व बाहर उड़ान भरते हैं, दृश्य संकेत व रेडियो कॉल्स के भरोसे पर और वह भी भारत के सबसे खतरनाक वायु गलियारों में।

दरअसल, उचित व सुरक्षित प्रबंध किए बिना ही तीर्थयात्रा को कमर्शियल कर दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक आर्थिक लाभ कमाया जा सके। चारधाम की यात्रा कठिन है। इसलिए पहले बहुत कम लोग जाया करते थे और वह भी पैदल, टट्टू गाइडों के कंधों पर सवार होकर। हेलिकॉप्टर सेवा शुरू होने के बाद लाखों लोग दर्शन के लिए जाने लगे हैं। इसलिए उनके लिए व्यवस्था तो अच्छी, स्तरीय व सुरक्षित होनी चाहिए, लेकिन इसी में ही लापरवाही बरती जा रही है।

प्रतिदिन 250 से 300 उड़ानें

इस अव्यवस्था में केदारनाथ के आसमान में हेलिकॉप्टर की रोजाना 250-300 उड़ानें भरी जा रही थीं। इस मंडराते खतरे को मद्देनजर रखते हुए पिछले सप्ताह डीजीसीए ने हस्तक्षेप किया और हेलिकॉप्टर उड़ानें 9 प्रति घंटा तक सीमित कर दीं। अब रोजाना 152 उड़ानें भरी जा रही हैं और हालिया दुर्घटना को देखते हुए यह भी ज्यादा ही प्रतीत हो रही हैं। गौरतलब है कि जब ऐसी ही एक दुर्घटना 2022 में हुई थी तो सरकार द्वारा अनेक सुरक्षात्मक कदम उठाने की घोषणा की गई थी।

तीन कैमरा लगाए गए, एक केदारनाथ प्रवेश पॉइंट पर, दूसरा रूद्र पॉइंट पर और तीसरा बेस कैंप पर, ताकि उड़ान भरने से पहले पायलट स्थितियों का मूल्यांकन कर लें। जब तक केदारनाथ को उचित एविएशन सिस्टम और सख्त एसओपी (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम) नहीं मिलेगा, तब तक पायलट अंधेरे में ही उड़ान भरते रहेंगे। पायलट को अपनी आंखों व अंदाजे से उड़ान भरनी पड़ती है। नतीजतन दुर्घटना की आशंका निरंतर बनी रहती है।

आधुनिक धनकुबेरों ने एविएशन इंड्रस्ट्री के लिए ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि वह संभल नहीं पा रही है। इन यात्राओं में होने वाली भीड़ को देखकर कभी-कभी सड़कों पर दौड़ लगाती प्राइवेट बसों की याद आ जाती है।

मनोज वार्ष्णेय

चरमराता जा रहा भारत का विमानन उद्योग

वर्तमान में एविएशन इंड्रस्ट्री हर तरफ से दबाव में है। साधनों की कमी से जूझ रही यह इंड्रस्ट्री एक तरफ हवाई दुर्घटनाओं से परेशान है, साथ ही सोशल स्टेटस के लिए की जा रही यात्राओं के कारण भी यात्रियों की भीड़ को संभाल नहीं पा रही है। यात्रियों के आपसी झगड़े, सहयात्री पर टायलेट कर देना या फिर एयर क्रू से बदतमीजी करना इतना आम हो गया है। कि फेसबुक जैसे प्लेटफार्म पर इनकी रील खूब प्रचार पा रही हैं। जो यात्राएं कल तक जरूरत की श्रेणी में आती थीं, वह अब एक-दूसरे को दिखाने के लिए सोशल स्टेटस बन रही हैं। दो देशों के बीच में युद्ध हो तो, मौसम बिगड़े तो, कोई दुर्घटना हो जाए, तो सबसे पहले एविएशन उद्योग पर असर आता है।

आधुनिक धनकुबेरों ने एविएशन इंड्रस्ट्री के लिए ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि वह संभल नहीं पा रही है। इन यात्राओं में होने वाली भीड़ को देखकर कभी-कभी सड़कों पर दौड़ लगाती प्राइवेट बसों की याद आ जाती है। देश का हर कोना आज लगभग हवाई मार्ग से जुड़ चुका है। जहां पर हवाई पट्टी नहीं हैं, वहां पर हेलीकॉप्टर की सेवाएं उपलब्ध हैं। कुछ समय पहले तक हवाई यात्राएं सीमित दायरे में थीं, फिर जैसे ही यह विस्तार पाने लगीं तो यह आम जरूरत हो गई। व्यापार, चिकित्सा, इमरजेंसी के लिए इनका उपयोग एक तरह से संस्कारित दायरे में होता था, पर अब यह सेवाएं इतनी अधिक आम हो गई हैं कि मध्यम वर्गीय ही नहीं, जिसे हम विकसित होती जनता कहते हैं, वह भी सोशल स्टेटस के लिए हवाई मार्ग अपनाने लगी।

एलीट वर्ग को छोड़कर आज भी आम आदमी के लिए हवाई यात्रा करना काफी महंगा है, फिर भी बढ़ती भीड़ ने आवश्यकता को फैशन- लग्जरी बनाने में अपना पूरा योगदान दिया है। एविएशन की दुनिया में बढ़ती भीड़ के कारण रख-रखाव प्रभावित हो रहा है। और स्टाफ की कमी के कारण जब-तब पायलटों का उड़ान को बीच में ही छोड़ देना अब बड़ी बात नहीं रह गई है। भीड़ की हालत यह है कि वह हर हाल में हवा में सफर करना चाहती है, चाहे सफर के लिए मौसम अनुकूल हो या न हो।

तीर्थों का हेलीकाप्टर प्रवास

सबसे अधिक भीड़ ग्रीष्म ऋतु में तब देखी जाती है, जब तीर्थयात्राएं होती हैं और पर्यटन का पूरे देश में सीजन माना जाता है। उत्तराखंड के चार धाम, अमरनाथ यात्रा, कुंभ जैसी पर्व विशेष यात्राएं, पहाड़ी स्थानों पर जाने की जल्दी उन बातों में शुमार है, जिसमें कहा जाता है कि हवाई यात्रा काफी सुगम होती हैं। पर कुछ वर्षों से यह यात्राएं साइबर स्कैमरों के लिए मौका बन चुकी हैं, साथ ही होने वाली दुर्घटनाएं सरकार संचालन फर्म के लिए मुसीबत बन रही हैं।

केदारनाथ यात्रा जब 2 मई को आरंभ हुई तो उसके बाद से 50 दिन में आठ हेली कंपनियों के माध्यम से 56 हजार से अधिक यात्रियों ने बाबा के दर्शन किए। भीड़ का अंदाज इसी से लग सकता है कि 15 जून को गौरीकुंड के पास हुई हेली दुर्घटना के बाद सात दिनों में 7,000 से अधिक टिकट कैंसिल हुए। यहां पर भीड़ ने यह ध्यान नहीं रखा कि यात्रा मार्ग में उड़ान के लिए क्या मौसम सही होगा? इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि हेली सेवा देने वाली कंपनियों ने अधिक यात्रियों के लिए अपनी उड़ानों को उन नियमों से परे रखा जो सुरक्षा के लिए जरूरी थीं।

यह बात भी कम नहीं है कि भीड़ हेली बुकिंग के नाम पर ठगी जा रही है। सरकार ने 2023 में 64 से अधिक फर्जी वेबसाइट बंद कराई तथा इस वर्ष अभी तक 51 बेबसाइट तथा 111 नंबर ब्लाक करवाए हैं। व्हाटसअप नंबरों के साथ ही बैंक एकाउंट भी सरकार ने बंद कराए हैं, लेकिन इस पर भी ठगी जारी है। अब होने वाली अमरनाथ यात्रा में सरकार ने हेली सेवा रोक दी है। तथा केदारनाथ जैसी यात्रा के लिए भी बारिश बंद होने तक हेली सेवाएं स्थगित हैं। लोग धर्म के लिए यात्रा करते समय भी सुविधा भोगी हो गए हैं, इसलिए हेली सेवाओं की गुणवत्ता कम होती जा रही है।

यात्रियों द्वारा डाले गए सोशल मीडिया पर रील आदि में साफ नजर आता है कि हेलीकॉप्टर में किस आपाधापी में यात्री बैठाए जा रहे हैं और हेलीकॉप्टर इस तरह से दौड़ रहे हैं जैसे सड़क पर सार्वजनिक वाहन। जहां तक हवाई जहाजों की बात है तो वह भी यात्रियों की भीड़ के कारण सुरक्षा मानक पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इन स्थितियों में कहा जा सकता है कि हवाई यात्राएं अब जरूरत नहीं बल्कि सोशल स्टेट्स बनती जा रही हैं। फ्रं

देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने 'मराठी विजय रैली' की। इस रैली पर पूरे देश की नजर थी क्योंकि इससे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बदलाव का संकेत मिल रहा था।

भाषा, जाति, धर्म पर गुंडागर्दी का गौरवगान

कम से कम मुंबई की राजनीति तो निश्चित रूप से बदलती दिख रही है। इस राजनीतिक बदलाव के केंद्र में भाषा का विवाद है। यह बहुत पुराना विवाद है। कम से कम 75 साल पहले जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाषा के नाम पर राज्यों के विभाजन की मांग ठुकरा दी थी और मराठी नेताओं ने इसके खिलाफ एक संगठन बना कर लड़ाई शुरू करने का ऐलान किया था। शिव सेना के संस्थापक बाल ठाकरे के पिता प्रबोधंकर ठाकुर उस संगठन के नेताओं में से एक थे। बाद में इन लोगों को कामयाबी मिली और भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन हुआ। अब ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी मराठी भाषा की लड़ाई लड़ रही है।

किसी जमाने में यह लड़ाई सैद्धांतिक और अस्मिता से जुड़ी हुई थी। लेकिन अब इसमें से वो सारे तत्व गायब हो गए हैं। अब भाषा की लड़ाई राजनीतिक प्रासंगिकता बचाने की लड़ाई बन गई है। पिछले दो दशक में महाराष्ट्र की राजनीति में हाशिए से भी बाहर धकेल दिए गए राज ठाकरे को पार्टी और परिवार की राजनीति बचानी है तो शिव सेना के विभाजन और विधानसभा चुनाव में लगे झटके से उबरने के लिए उद्धव ठाकरे को भी ऐसे किसी भावनात्मक मुद्दे की जरुरत है। दोनों को यह मौका दिया महाराष्ट्र की देवेंद्र फड़नवीस की सरकार ने, जिन्होंने हिंदी को पहली से पांचवीं कक्षा तक अनिवार्य करने का फैसला किया। हालांकि बाद में उनकी सरकार ने फैसला रद्द कर दिया लेकिन तब तक ठाकरे बंधुओं को अपने पूर्वजों की लड़ाई की याद आ गई थी और उन्होंने भाषा का मुद्दा उठा दिया था।

यह हैरान करने वाली बात है कि फड़नवीस सरकार ने हिंदी की अनिवार्यता का फैसला क्यों किया? क्या संघ का दबाव था या दिल्ली को अपनी ताकत दिखानी थी? ध्यान रहे भाषा के आधार पर विभाजन नहीं करने के नेहरू और पटेल के फैसले को आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख माधव सदाशिवराव गोलवलकर का भी समर्थन हासिल था। हालांकि बाद में संघ और दिल्ली की सत्ता दोनों को भाषायी आधार पर विभाजन की मांग करने वालों को सामने झुकना पड़ा था। बहरहाल, चाहे जिसके कहने पर फड़नवीस ने फैसला किया और बदला हो लेकिन उससे राजनीति के नए दौर की शुरुआत हो गई। इसे शिव सेना के एक

होने और भाजपा की ओर लौटने की शुरुआत भी मान सकते हैं।

बहरहाल, उद्धव और राज ठाकरे की 'मराठी विजय रैली' में भाषा के आधार पर गुंदागर्दी का गौरवगान हुआ। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर मराठी भाषा के लिए सम्मान की बात करना गुंडागर्दी है तो वे गुंडा हैं। इसी बात को थोड़ा ज्यादा विस्तार देकर राज ठाकरे ने अपनी बात कही। उन्होंने अपने समर्थकों को भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करने की सलाह देते हुए कहा कि अगर वे किसी को कान के नीचे बजाएं यानी उसको मारें तो उसकी वीडियो नहीं बनाएं। इसका मतलब है कि मारपीट करने और गुंडागर्दी करने में कोई समस्या नहीं है, समस्या उसकी वीडियो से है क्योंकि वीडियो वायरल होने पर देश भर में इस पर प्रतिक्रिया होती है। कुछ दिन पहले ही राज ठाकरे के गुंडों ने गुजरात के एक दुकानदार के मराठी नहीं बोल पाने के कारण उसके साथ मारपीट की थी। उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक नेता का भी ऐसा ही एक वीडियो सामने आया था। इसके बाद उद्धव और राज ठाकरे का भाषण हुआ है। दोनों ने गुंडागर्दी को सांस्थायिक रूप दिया है। उन्होंने भाषा के सम्मान के नाम पर गुंडागर्दी को जायज ठहराया।

इसे लेकर देश के अलग अलग राज्यों के कई व्यक्तियों और समूहों की ओर से सलाह दी जा रही है कि भाषा के नाम पर यह गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प सलाह भाजपा के नेता और फड़नवीस सरकार के मंत्री नीलेश राणे ने दी। उन्होंने कहा कि अगर ठाकरे बंधुओं में हिम्मत है तो मोहम्मद अली रोड पर जाकर मुसलमानों पर गुंडागर्दी दिखाएं क्योंकि वे भी मराठी नहीं बोलते हैं। यह भाषा के आधार पर होने वाली गुंडागर्दी के ऊपर धर्म के आधार पर होने वाली गुंडागर्दी को ज्यादा महान बताने की सोच का प्रतीक है। नीलेश राणे को लग रहा है कि मराठी नहीं बोलने वाले हिंदुओं की बजाय अगर मराठी नहीं बोलने वाले मुसलमानों के साथ मारपीट हो तो वह न्यायसंगत है।

ध्यान रहे इस नए भाषा विवाद से पहले या उससे ज्यादा पूरे देश में धर्म के आधार पर गुंडागर्दी हो रही है और उस पर गर्व किया जा रहा है। सावन का महीना शुरू होने वाला है और दिल्ली, एनसीआर से होकर कांवड़ यात्रा गुजरने वाली है। उससे पहले कांवड़ के रास्ते में दुकानदारों के खिलाफ गुंडागर्दी शुरू हो गई है। सरकार की चेकिंग चल रही है लेकिन उससे अलग बिना किसी कानूनी अधिकार के गुंडों का गिरोह दुकानदारों से नाम पूछ रहा है, उनकी आईडी चेक कर रहा है, उनके यूपीआई लिंक पर पेमेंट के जरिए असली नाम चेक किया जा रहा है और दुकानें बंद करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

यह धर्म के आधार पर होने वाली गुंडागर्दी का एक नमूना है। पिछले ही महीने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में गोमांस के शक में एक भीड़ ने चार लोगों को बुरी तरह से पीटा। उनकी गाड़ी पलट दी और उसमें आग लगा दी। बाद में पता चला कि वे गोमांस लेकर नहीं जा रहे थे। इस सिलसिले में तीन लोग गिरफ्तार किए गए। लेकिन व्यापक हिंदू समाज उनको अपराधी या गुंडा नहीं मानता है। वे छूटेंगे तो नायक की तरह उनका स्वागत होगा। ठीक वैसे ही जैसे भाषा के आधार पर मारपीट करने वाले गुंडों का सम्मान मुंबई में किया जाता है।

भाषा और धर्म की तरह जाति के आधार पर गुंडागर्दी का भी गौरवगान इन दिनों खूब हो रहा है। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथा बांचने वाले दो लोगों के साथ इसलिए मारपीट हुई क्योंकि वे गैर ब्राह्मण थे। बाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनका सम्मान किया क्योंकि वे यादव थे। इस घटना के बाद बिहार के एक गांव के बाहर कुछ लोगों ने बोर्ड लगा दिया कि इस गांव में ब्राह्मणों का पूजा पाठ कराना सख्त मना है। सोचें, क्या ब्राह्मण खुद से घर घर घूम कर पूजा पाठ कराते हैं, जो उनको रोकने का बोर्ड लगाया गया? अनेक वस्तुएं और सेवाएं हैं, जो घर घर घूम कर पहुंचाई या बेची जाती हैं लेकिन पूजा पाठ उनमें से नहीं है।

यजमान के बुलावे पर ही पंडित उनके यहां पूजा पाठ कराने जाते हैं। फिर भी जाति के आधार पर गुंडागर्दी इसलिए क्योंकि उससे राजनीति सधती है। जैसे भाषा और धर्म से सधती है वैसे ही जाति से भी सधती है। एक पार्टी की महिला प्रवक्ता ने मीडिया के सामने 'मनुस्मृति' के पन्ने फाड़े क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी अपनी पार्टी के नेताओं की नजरों में चढ़ना है, अपनी आक्रामकता से पिछड़ा पहचान को बुलंद करना है और कोई पद या चुनाव में टिकट आदि हासिल करना है। बहरहाल, जाति के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले तमाम लोग अपनी अपनी जातियों के नायक हैं।

धर्म, जाति और भाषा के आधार पर गुंडागर्दी करने वालों को इन दिनों फायर ब्रांड नेता का नाम दिया जाता है। हर पार्टी के अपने अपने फायर ब्रांड नेता हैं, जो जाति, भाषा या धर्म के नाम पर भड़काऊ भाषण देते हैं, हिंसा के लिए लोगों को उकसाते हैं, खुद भी मारपीट करते हैं और समाज को बांटते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। अपनी हिंसा का गौरवगान करते हैं और दूसरी ओर जनता उनको अपनी भाषा का रहनुमा, अपनी जाति का मसीहा और अपने धर्म का रक्षक मान कर उनकी जय जयकार करती है। फ्रं

अमेरिकी धमकी की वजह से तमाम नाटो देशों का रक्षा बजट दोगुना-तिगुना होगा, तो भारत के हथियार, सैन्य प्रणाली तथा उपकरण खूब बिकेंगे। हम और हमारी कंपनियां इस बाजार में बड़े खिलाड़ी के बतौर स्थापित होंगे।

संजय श्रीवास्तव

भारत बनेगा शस्त्र बाजार का नया खिलाड़ी

डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के चलते कि वह नाटो से अलग हो जाएगा, इस संधि के 31 देशों में से स्पेन को छोड़कर सभी ट्रंप के आगे नतमस्तक हो अपना रक्षा बजट 2032 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद के 5 फीसदी तक करने पर राजी हो गए हैं। अमेरिकी धमकी की वजह से तमाम नाटो देशों का रक्षा बजट दोगुना-तिगुना होगा, तो भारत के हथियार, सैन्य प्रणाली तथा उपकरण खूब बिकेंगे। हम और हमारी कंपनियां इस बाजार में बड़े खिलाड़ी के बतौर स्थापित होंगे।

फ्रांस, अमेरिका के अलावा एशिया और अफ्रीका के साथ कई विकासशील देश भारतीय हथियारों में रुचि ले रहे हैं। फिलीपींस ब्रह्मोस खरीद रहा है, तो वियतनाम नौसैनिक उपकरण, मॉरीशस, सेशेल्स, श्रीलंका वगैरह तटरक्षक पोत, लैटिन अमेरिका के कुछ देश भारतीय रडार और हल्के हथियारों में रुचि दिखा रहे हैं, तो हम नेपाल, म्यांमार, भूटान के अलावा इंडोनेशिया, ब्राजील और कुछ यूरोपीय देशों को भी हथियार बेचने जा रहे हैं। ऐसे में गैर नाटो देशों के अलावा कम से कम दो दर्जन नए नाटो ग्राहक मिलेंगे तो हम अरबों रुपए कमाएंगे।

नाटो देश रक्षा बजट बढ़ाएंगे

भारत अब बेहद उन्नत और सक्षम हथियार तथा सैन्य तकनीकी से संपन्न उपकरणों का निर्माण करता है। विश्व बाजार में उसकी साख बन रही है। वह हथियारों को बेचना भी अवश्य चाहेगा। क्या यह मौका देश के हथियार बाजार को वैश्विक मंच दिलाएगा? क्या यह लाभ वाकई इतना बड़ा है, जितना प्रचारित किया जा रहा है? नाटो के कोष में 66 फीसद हिस्सेदारी निभाने वाले अमेरिका के हाथ खींचने की घुड़की से उसके कुछ देश अपना रक्षा व्यय जीडीपी के पांच फीसद तक ले जाने का प्रयास करेंगे।

ज्यादातर नाटो देश सैनिकों, हथियारों पर जीडीपी का साढ़े तीन प्रतिशत का रक्षा व्यय पूरा नहीं कर पाएंगे। सड़कों, पुलों, बंदरगाहों, हवाई क्षेत्रों, सैन्य वाहनों, साइबर सुरक्षा और ऊर्जा पाइपलाइनों की सुरक्षा सहित बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के मद में जीडीपी का डेढ़ प्रतिशत का हिस्सा वे गोलमाल से पूरा करेंगे। कुछ देशों की स्थिति ऐसी है कि सत्ता में उनके साझीदार रक्षा को शिक्षा, स्वास्थ्य पर तरजीह देने के खिलाफ हैं।

नाटो के सभी देश रक्षा पर स्वास्थ्य या शिक्षा से कम खर्चते हैं। रक्षा व्यय को जीडीपी के पांच फीसदी तक पहुंचने के लिए तकरीबन दो दर्जन देशों को मौजूदा खर्चों की तुलना में हर वर्ष सैकड़ों अरब डॉलर ज्यादा खर्चने होंगे, नाटो सदस्यों को खुद तय करना होगा कि रक्षा व्यय आवंटन हेतु अतिरिक्त नकदी कहां से लाएं?

फिलहाल 4 प्रमुख हथियार सप्लायर देश

नाटो देशों के हथियार और सैन्य सामग्री तथा उपकरणों के मुख्य आपूर्तिकर्ता अभी भी अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ही हैं। बोइंग, एयरबस और लॉकहीड मार्टिन जैसी अमेरिकी कंपनियों ने नाटो देशों का हथियार बाजार पहले से ही कब्जाया हुआ है। वे इस अवसर को भुनाने के लिए और आक्रामक प्रयास करेंगी।

इनके अलावा दक्षिण कोरिया इन देशों को उन्नत मिसाइल और नौसेना प्रणाली बेचने के करीब है, तो इजराइल और तुर्की इन्हें सस्ते ड्रोन्स, साइबर सुरक्षा, इंटेलिजेंस उपकरण तथा ब्राजील सस्ते में हल्के मिलिट्री विमान देने जा रहा है। ऐसे में उनके सैन्य खरीद का कितना हिस्सा हमें मिलेगा कहना मुश्किल है।

भारत बनेगा दूसरा सप्लायर

भारत नाटो देशों के लिए एक आकर्षक द्वितीय सप्लायर बन जाएगा। आज 85 से अधिक देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात करने के बावजूद भारत वैश्विक रक्षा निर्यात बाजार में एक प्रतिशत से कम की हिस्सेदारी रखता है। विगत एक दशक में सरकार ने जो कोशिशें रक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के नाम पर की हैं, उसके शानदार परिणाम अब दिखने लगे हैं और तय हो चुका है कि भारत रक्षा बाजार में भविष्य का बड़ा खिलाड़ी है।

ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस, अर्जुन टैंक, स्वदेशी रडार, आर्टिलरी गन, डोर्नियर-228 विमान, आकाश वायु रक्षा प्रणाली, पिनाका रॉकेट जैसे तमाम निर्यात योग्य शानदार उत्पाद हैं। डेटा पैटर्न इंडिया, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, डीआरडीओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स, आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी, एचएएल, टाटा एडवांस सिस्टम, जैसी कई कंपनियां अपने उत्पादों और डिलीवरी के लिए वैश्विक स्तर पर जानी जा रही हैं। एमआरओ यानी मेंटीनेंस, रिपेयर, ओवरऑल सेक्टर में भी हम बेहतर हैं। फ्रं

वर्तमान समय में कुछ ही राष्ट्रों के पास बंकर ब्लस्टर जैसी सुविधा उपलब्ध है और जब भारत भी उस श्रेणी में आ जाएगा। जब भारत का यह स्वदेशी बंकर ब्लस्टर बम बनकर तैयार हो जाएगा तब हमारी अग्नि-5 मिसाइल दुश्मन के मजबूत ठिकानों और तहखानों को मिनटों में ध्वस्त करक वापस चली आएगी।

मृत्युंजय दीक्षित

भविष्य के युद्धों के लिए तैयार होती भारतीय सेना

वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से ही भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर, स्वदेशी तकनीक से समृद्ध, सुदृढ़ व सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। भारतीय सेना को भविष्य की रक्षा चुनौतियों लिए इस प्रकार तैयार किया जा रहा है कि भूमि से लेकर वायु और समुद्र की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाईयों तक अपनी सुरक्षा के लिए किसी अन्य पर निर्भर न रहना पड़े। आज अति आधुनिक ड्रोन से लेकर अविश्वसनीय मारक क्षमता वाली मिसाइलों तक का निर्माण भारत में किया जा रहा है।

विगत दिनों ईरान-इजराइल के मध्य संघर्ष के बीच ईरान के शक्तिशाली व मजबूत परमाणु संयंत्रों को नष्ट करने की क्षमता न होने के कारण इजराइल को भी अमेरिका की शरण में जाना पड़ा था। ऐसी ही परिस्थितियों से बचने के लिए भारत अब बंकर ब्लस्टर बम बनाने की दिशा में भी अग्रसर है। वर्तमान समय में कुछ ही राष्ट्रों के पास बंकर ब्लस्टर जैसी सुविधा उपलब्ध है और जब भारत भी उस श्रेणी में आ जाएगा। जब भारत का यह स्वदेशी बंकर ब्लस्टर बम बनकर तैयार हो जाएगा तब हमारी अग्नि-5 मिसाइल दुश्मन के मजबूत ठिकानों और तहखानों को मिनटों में ध्वस्त करक वापस चली आएगी।

भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं संगठन अग्नि 5 मिसाइल के दो नये एडवांस प्रारूप विकसित कर रहा है जिसमें प्रथम प्रारूप बंकर ब्लस्टर वॉरहेड या विस्फोटक ले जाने वाला होगा जो जमीन के भीतर 80 से 100 मीटर तक जाकर दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करेगा जबकि दूसरा प्रारूप विस्फोटक ले जाने वाला होगा। ये दोनों ही प्रारूप दुश्मन के डिफेंस सिस्टम, न्यूक्लियर सिस्टम, रडार सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और हथियार डिपो को ध्वस्त करके वापस लौट आएंगे। अग्नि -5 बंकर ब्लस्टर मिसाइल जमीन, सड़क और मोबाइल लांचर से दागी जाएगी। अग्नि-5 भारत की एक ऐसी मिसाइल है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक निशाना लगा सकती है। इसकी रेंज 5 से 7 हजार किमी तक हैं ये परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। भारत का बंकर ब्लस्टर बम अमेरिकी बम से भी अधिक क्षमतावान बनाया जा रहा है। भारत की बंकर ब्लस्टर मिसाइल अमेरिकी बम से अधिक गहराई तक निशाना लगा सकती है। भारत को चीन और पाकिस्तान से पैदा हुए खतरे को देखते हुए ही इस प्रकार की मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है।

भारतीय नौसेना को मिला तमाल- इसी प्रकार ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस अब तक का सबसे घातक आधुनिक स्टील्थ युद्धपोत आईएनएस तमाल अब भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है जिसके कारण अब समुद्र में भी भारत की ताकत बढ़ गई है। इस बहुददेशीय अतिआधुनिक युद्धपोत का जलावतरण रूस के केलिनिनग्राद में हुआ। नौसेना के पश्चिमी बेड़े में शामिल यह युद्धपोत हिंद सागर में तैनात होगा और पाकिस्तान से लगती सीमा पर निगरानी में भारत की सबसे बड़ी ताकत बन जायेगा। तमाल युद्धपोत विगत दो दशकों में रूस से प्राप्त क्रियाक श्रेणी के युद्धपोतों की श्रृंखला में आठवां युद्धपोत है। यह पूर्ववर्ती संस्करणों की तुलना में अधिक उन्नत है। इसमें लंबवत प्रक्षेपित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें उन्नत 100 मिलीमी की तोप, मानक 30 मिलीमीटर गन क्लोज -इन हथियार प्रणाली के अलावा आधुनिक समय की प्रणाली अत्यधिक भार वाले टारपीडो तत्काल हमला करने वाले पनडुब्बी रोधी, रॉकेट और अनेक निगरानी एवं अग्नि नियंत्रण रडार तथा अन्य प्रणालियां शामिल हैं।

युद्धपोत का नाम तमाल देवताओं के राजा इंद्र की पौराणिक तलवार से लिया गया है। इसकी मारक क्षमता भी उसी तरह तेज, आक्रामक और निर्णायक है। इसका शुभंकर भारतीय पौराणिक कथाओं के अमर भालू जाम्बवंत और रूसी राष्ट्रीय पशु यूरेशियन भूरे भालू की समानता से प्रेरित है। तमाल युद्धपोत का निर्माण रूस के कैलिनिनग्राद स्थित यांतर शिपयार्ड में हुआ है और इसमें 26 प्रतिशत स्वदेशी उपकरण हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह आखिरी युद्धपोत है जो विदेश में बना है अब ऐसा कोई भी युद्धपोत भारत में ही बनेगा जिसके बाद भारत की नौसेना की शक्ति और बढ़ जाएगी। इस युद्धपोत के कुशल संचालन व रखरखाव के लिए 250 नौसेना कर्मियों ने रूस में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। बहु मिशन युद्धपोत भारत के समुद्री हितों के क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरह के खतरों से निपटने में सक्षम है।

भारत की नोसेना को एक और स्वदेशी युद्धपोत उदयगिरि का उपहार भी मिला है। इस युद्धपोत में सुपरसोनिक सतह से सतह से मार करने वाली प्रणाली लगी है। इसमें 76 मिमी गन, 30 मिमी और 12.7 मिमी की रैपिड फायर गन सहित डीजल इंजन और गैस टर्बाइन युक्त सीओडीजी प्रणाली है। इस 3900 टन वजनी और 125 मीटर लंबे युद्धपोत में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लैस हैं। यह देनों ही युद्धपोत भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा में प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं।

सिंदूर अभियान और उसके बाद अब तक की सारी सफलता उत्कृष्ट रक्षा तकनीक और उसके इस्तेमाल के कौशल का कमाल है।इस अभियान के तहत सेना ने सीमा पार के आतंकी ठिकानों को बिना बॉर्डर पार किए नेस्तनाबूद किया और बौखलाए पाकिस्तान ने जब हमारे सैन्य ठिकानों और इलाकों पर पचासों ड्रोन, मिसाइलों, बम वगैरह से हमले किए, तो उन सभी को हमने अपनी तकनीक क्षमता, दक्षता से नाकाम कर दिया। भारतीय सेना ने पहली बार किसी रक्षा अभियान में इतने बड़े पैमाने पर तकनीक संचालित हथियारों, अति उन्नत तकनीक वाली रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल किया।

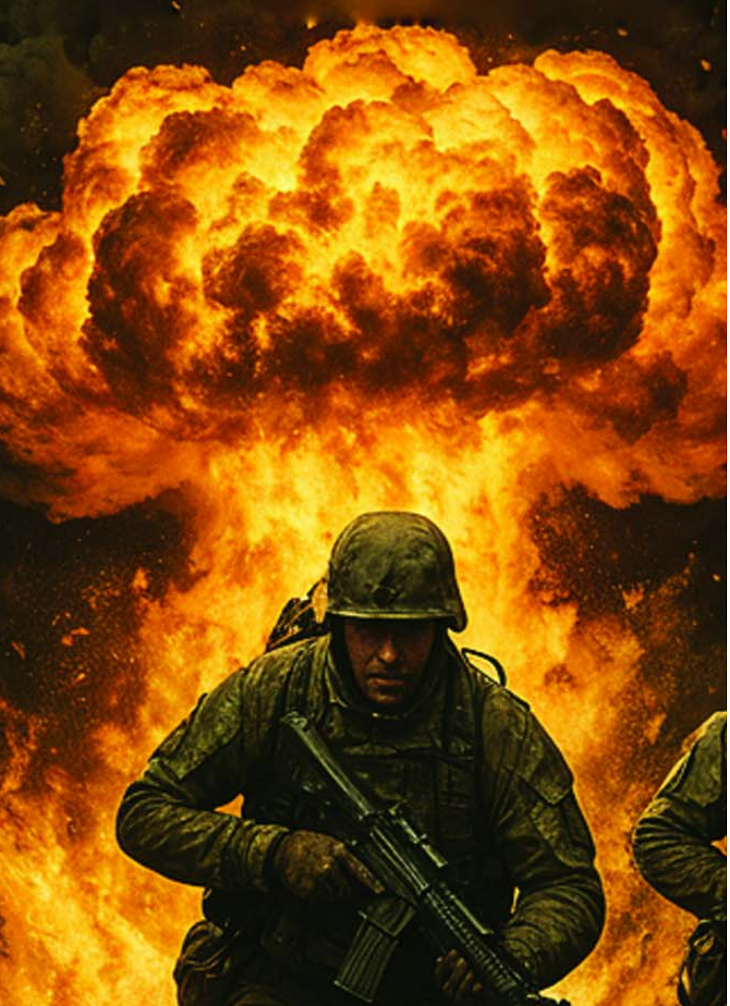

ईरान-इजराइल संघर्ष का वैश्विक प्रभाव

दीपिका पाल

22 जून 2025 को इजराइल और ईरान के बीच चल रहे सैन्य संघर्ष के बीच अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर बंकर बस्टर बम गिराना एक ऐसी प्रक्रिया का समापन था, जो 1979 में शुरू हुई थी। उस समय ईरान के शाह के शासन में ईरान के अमेरिका और इजराइल दोनों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे।

फरवरी 1979 में ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी की अमेरिका समर्थक संवैधानिक राजशाही को एक क्रांति में उखाड़ फेंका गया और शिया मुस्लिम नेताओं के नेतृत्व में एक नई सरकार ने सत्ता संभाली। एक ओर ईरान और दूसरी ओर इजराइल और अमेरिका के बीच संबंध तब से बद से बदतर होते चले गए हैं। इनमें आपसी अविश्वास और नफरत चरम पर रही। इसके कई कारण हैं। और इसमें वैचारिक के साथ-साथ भू-राजनीतिक और रणनीतिक भी शामिल हैं।

तेहरान में अंतिम संस्कार समारोह के दौरान इजराइली हमलों में मारे गए ईरानी सेना के जनरलों, परमाणु वैज्ञानिकों और उनके परिवार के सदस्यों के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शोक संतप्त लोग इस्लामिक क्रांति चौक (एंघेलाब स्क्वायर) में एकत्र हुए।

ईरान फिलिस्तीनियों को उनके मातृभूमि की तलाश में लगातार समर्थन देता रहा है, जिसे अब तक इजराइल ने नकार दिया है। इजराइल संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित दो-राज्य समाधान को स्वीकार करने से इनकार करता है। फिलिस्तीनी के समर्थन में ईरान ने गाजा में हमास, लेबनान में हिज्बुल्लाह और यमन में हूती जैसे सशस्त्र समूहों को इजराइल और अमेरिका को निशाना बनाने के लिए अपने प्रॉक्सी के रूप में तैयार किया है।

ईरान का परमाणु कार्यक्रम विवाद का एक और मुद्दा है। ईरान का दावा है कि एनपीटी पर हस्ताक्षर करने के कारण उसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी विकसित करने का अधिकार है। हालांकि, अमेरिका और उसके सहयोगी, विशेष रूप से यूरोपीय, हमेशा से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का उद्देश्य अंततः परमाणु बम विकसित करना है और ईरान अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के बहुत करीब है। इजराइल का कहना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। विडंबना यह है कि इजराइल से उसके अनुमानित 90 परमाणु हथियारों को छोड़ने की कोई मांग नहीं की गई है।

यह याद रखना उचित होगा कि ईरान का परमाणु मुद्दा अप्रैल 2015 में कमोबेश सुलझ गया था, जब राष्ट्रपति बराक ओबामा के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका और 5 अन्य विश्व शक्तियों (यू.के., फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी) ने संयुक्त व्यापक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में सबसे पहले जेसीपीओए से बाहर निकलना था। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में भी यही किया। क्या वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भविष्य में किसी समय उसके परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने और शासन परिवर्तन को लागू करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे थे। ठीक उसी तरह जैसे अमेरिकी प्रशासन ने इराक पर हमला करने और सद्दाम हुसैन को बेअसर करने के लिए ÷सामूहिक विनाश के हथियारों÷ का इस्तेमाल किया था?

बीते कई सालों से ईरान और इजराइल अमेरिका से मजबूत नैतिक, राजनीतिक और भौतिक समर्थन के साथ छद्म और छाया युद्धों में लगे हुए हैं। यकीनन, सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया और इजराइल ने इसे ईरान के तीन प्रॉक्सी (हमास, हिजबुल्लाह, हूती) को कमजोर करने के अवसर के रूप में लिया और फिर 13 जून 2025 को ईरान पर सीधा हमला किया। ईरान ने इस हमले का जोरदार तरीके से जवाब दिया। यह सब 22 जून 2025 को ईरान के तीन परमाणु स्थलों पर बम गिराने के माध्यम से अमेरिका के सीधे प्रवेश के साथ समाप्त हुआ। इस तरह से ये ऐसा कुछ था, जो इजराइल की सैन्य क्षमताओं से दूर था। इस हमले का घोषित उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के हित में ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को तबाह करना था।

अमेरिका 12 दिनों के संघर्ष के बाद ईरान और इजराइल दोनों पर एक नाजुक युद्ध विराम लागू करने में कामयाब रहा। हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बात को लेकर निश्चित नहीं हैं कि यह कब तक चलेगा। इसके अलावा ईरान की परमाणु सुविधाओं को हुए वास्तविक नुकसान पर अभी तक कोई विश्वसनीय आकलन उपलब्ध नहीं है। और इसलिए कोई निश्चितता नहीं है कि अमेरिका/इजराइल ने ईरान की परमाणु सुविधाओं को पूरी तरह से 'नष्ट' करने का उद्देश्य हासिल कर लिया है। जैसा कि ट्रंप

युद्ध समाप्त या नई शुरुआत?

इजराइल-ईरान भिड़ंत के बीच अमेरिका के हस्तक्षेप से युद्ध की आग और ज्यादा भड़कने की आशंका है। अब तक इजराइल अकेला जूझ रहा था। अमेरिका के आने से उसकी हिम्मत बढ़ेगी। वहीं, ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। अगर वे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बड़े सैन्य कदम उठाएंगे तो जवाबी हमला कहीं ज्यादा घातक हो सकता है। उससे ईरान में जान-माल के भारी नुकसान की आशंका होगी। अगर खामेनेई शिकस्त कबूल कर लेंगे और कोई बड़ा पलटवार नहीं करेंगे तो ईरान में आक्रोश भड़क सकता है। वहां सर्वोच्च नेता के विरोधियों की कमी नहीं है। जब लोगों को यह महसूस होगा कि खामेनेई के जंगी जुनून की वजह से उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा है और सर्वोच्च नेता देश के गौरव की रक्षा करने में विफल रहे हैं तो एक बार फिर उनके खिलाफ नारे गूंज सकते हैं।

ऐसे में खामेनेई के सामने बड़ी चुनौती होगी। उन पर भारी दबाव होगा कि वे खुद को ऐसे नेता की तरह दिखाएं, जिसे ताकतवर दुश्मन झुका नहीं सका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध में इजराइल का साथ देने के बारे में दो सप्ताह में फैसला लेने की बात कहकर ईरान को भ्रमित करने की कोशिश की थी। हालांकि यह देश उनके ऐसे बयानों को संदेह की दृष्टि से ही देखता है। ट्रंप के आदेश पर ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर जोरदार बमवर्षा की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति इसे 'अत्यंत सफल हमला' बता रहे हैं, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टों में किया गया यह दावा संपूर्ण कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाता है कि बंकर-बस्टर्स बमों की रेंज 65 मीटर थी, जबकि परमाणु ठिकाने उससे भी काफी नीचे थे! अभी ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अगर भविष्य में खुफिया रिपोर्टों में इस बात की पुष्टि हुई कि अमेरिकी हमले के बावजूद ईरान का परमाणु कार्यक्रम सुरक्षित रहा, तो ट्रंप क्या करेंगे? क्या उस सूरत में अमेरिका एक बार फिर धावा बोलेगा?

जब ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी विमान कहर बरपा रहे थे, तब 'सिचुएशन रूम' में बैठे ट्रंप अपने समर्थकों को खास संदेश दे रहे थे। उनकी टोपी पर लिखे पसंदीदा वाक्य 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' को पढ़कर उन्हें महसूस होगा कि हमारे नेता देश को महान बनाने के लिए सच में ही कुछ कर रहे हैं। ईरान पर अमेरिका के हमले की आशंका के मद्देनजर वहां कई जगह विरोध-प्रदर्शन हो रहे थे। अब चूंकि हमला हो चुका है, इसलिए ट्रंप अपने विरोधियों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं।

ने दावा किया है और ईरान के अलावा अमेरिकी समाज के एक हिस्से ने इसका खंडन किया है। तो, क्या परमाणु मुद्दा सुलझ गया है? इसके अलावा, फिलिस्तीन का मुद्दा अब भी चर्चा में है। हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही हार गए हैं, लेकिन खत्म नहीं हुए हैं। ऐसे में निकट भविष्य में मध्य पूर्व पर अनिश्चितता के बादल मंडराते रहने की आशंका है।

क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव : इजराइल-ईरान, इजराइल-फिलिस्तीन मुद्दे मूलतः क्षेत्रीय हैं, लेकिन इनके वैश्विक निहितार्थ हैं। साथ ही सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक भी।

खास बात यह है कि ईरान पर अमेरिकी हमले ने यह मजबूत संकेत दिया है कि अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने एक बार फिर भू-राजनीति में मौजूदा प्रवृत्ति को मजबूत किया है कि शक्तिशाली देश राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छानुसार बल का उपयोग कर सकते हैं; यह एक 'नया सामान्य' बनता दिख रहा है। इस संदर्भ में अन्य हालिया उदाहरणों में नागोर्नो-कराबाख के आसपास अपने कब्जे वाले क्षेत्रों को मुक्त करने के लिए अजरबैजान की सैन्य कार्रवाई, यूक्रेन के नाटो में प्रवेश को रोकने के लिए यूक्रेन में रूस का 'विशेष सैन्य अभियान', हमास का इजराइल पर हमला आदि शामिल हैं। 'नया सामान्य' एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक शासन के अन्य संस्थानों की प्रभावकारिता और प्रासंगिकता के बारे में वैध प्रश्न उठा रहा है।

मध्य पूर्व में सैन्य संघर्षों का आर्थिक नतीजा विनाशकारी हो सकता है। सबसे पहले और सबसे खास बात यह है कि यह क्षेत्र तेल और गैस की महत्वपूर्ण वैश्विक आपूर्ति का स्रोत है। और इसलिए भारत सहित कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। तेल की ऊंची कीमतों का व्यापक प्रभाव पड़ेगा और मुद्रास्फीति बढ़ेगी। आपूर्ति श्रृंखला बाधित होगी, जिससे वैश्विक व्यापार को नुकसान होगा। क्षेत्र में हवाई क्षेत्र बंद होने से विमानन उद्योग और पर्यटन को झटका लगेगा और अर्थव्यवस्था के अन्य संबंधित क्षेत्रों को भी नुकसान होगा।

ऊर्जा क्षेत्र के अलावा, भारत एक से अधिक अर्थों में प्रभावित होगा। चाबहार बंदरगाह, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे जैसी भारत की व्यापार और संपर्क परियोजनाएं प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगी। इसके अलावा मध्य पूर्व में रहने और काम करने वाले लाखों भारतीयों को निकालना और भारत में सालाना 125 बिलियन डॉलर की राशि भेजना एक बहुत बड़ा काम होगा।

संक्षेप में, वैश्विक निहितार्थों के साथ मध्य पूर्व में क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्राथमिकता इजराइल और फिलिस्तीन के लिए दो-राज्य समाधान और ईरान परमाणु मुद्दे के समाधान जैसे मुख्य मुद्दों के समाधान की तलाश करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए कि राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए न तो राज्यों द्वारा और न ही गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा बल का एकतरफा उपयोग किया जाए।

संयुक्त राष्ट्र में सुधार और मजबूती के लिए सामूहिक प्रयासों और इरादों की आवश्यकता है, ताकि यह पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी निर्धारित भूमिका को प्रभावी ढंग से निभा सके। यह एक कठिन काम लगता है? या इन प्रवृत्तियों को उलटने के लिए बहुत देर हो चुकी है? लेकिन 'विश्व व्यवस्था' को 'विश्व अव्यवस्था' में और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए यह आवश्यक है। फ्रं

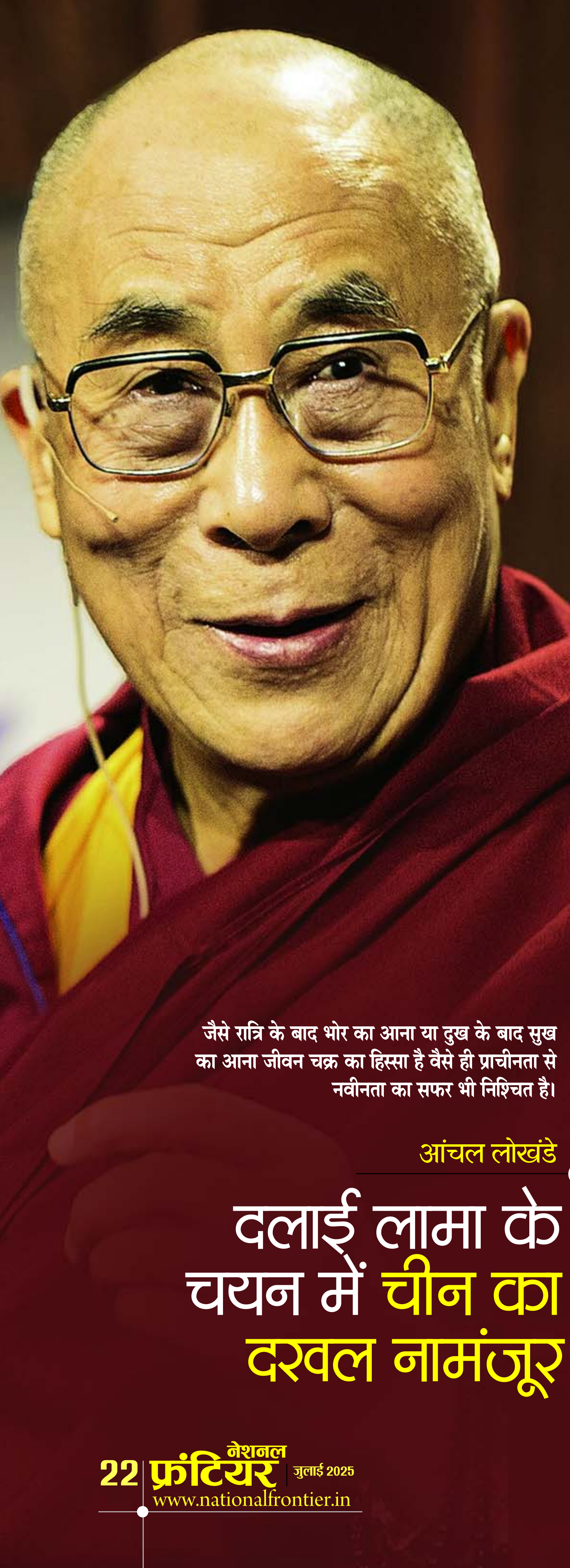

दलाई लामा के चयन में चीन का दखल नामंजूर

आंचल लोखंडे

जैसे रात्रि के बाद भोर का आना या दुख के बाद सुख का आना जीवन चक्र का हिस्सा है वैसे ही प्राचीनता से नवीनता का सफर भी निश्चित है।

भारत ने सख्ती के साथ चीन के इस दावे को ठुकरा दिया है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन करने में उसे निर्णायक अधिकार है। भारत ने इस बात पर बल दिया है कि इस मुद्दे पर फैसला केवल तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु की इच्छाओं और स्थापित बौद्ध परम्पराओं के अनुसार ही हो सकता है। दलाई लामा ने घोषणा की थी कि अपने उत्तराधिकारी पर निर्णय लेने का उन्हें 'विशिष्ट प्राधिकरण' है। संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजीजू के अनुसार, 'न केवल तिब्बतियों के लिए बल्कि दुनियाभर में उनके लाखों अनुयायियों के लिए भी दलाई लामा का पद अति महत्व का है। सदियों पुरानी बौद्ध परम्परा के अनुसार अपने उत्तराधिकारी का चयन करने का अधिकार केवल उनका है।

तिब्बती बौद्धों के 90-वर्षीय आध्यात्मिक गुरु, जो 1959 से भारत में निर्वासन में रह रहे हैं। ने हाल ही में कहा था कि दलाई लामा की संस्था उनकी मृत्यु के बाद भी जारी रहेगी और उनके उत्तराधिकारी का वक्त उनके द्वारा स्थापित गैर-मुनाफे वाली गादेन फोडरंग ट्रस्ट करेगी। इससे पहले दलाई लामा ने कहा था कि उनका उत्तराधिकारी चीन के बाहर रहने वाले उनके समर्थकों में से होगा। दलाई लामा की यह बात चीन को पसंद नहीं है क्योंकि यह तिब्बत में से अपने किसी 'वफादार' को अगला दलाई लामा बनाना चाहता है। चीन का कहना है। 'दलाई लामा के पुनर्जन्म को घरेलू पहचान 'गोल्डन अर्न' प्रक्रिया के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। दलाई लामा के 90वें जन्मदिन का सप्ताह (30 जून से 6 जुलाई 2025) जोर शोर से धर्मशाला सहित दुनियाभर में मनाया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं और अगले दलाई लामा के चयन की चर्चा आम हो गई है।

बीजिंग इस महत्वपूर्ण तिब्बती संस्था पर कब्जा करने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। उसे वर्तमान दलाई लामा के निधन का इंतजार है। बीजिंग को यह अवसर अपने आप मिल जायेगा अगर पुनर्जन्म के सिद्धांतों के अनुसार चयन के परम्परागत तरीके का पालन किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार जब दलाई लामा का पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति-जो आमतौर से कम उम्र का लड़का होता है की पहचान कर ली जाती है तो उसे इस जिम्मेदार पद के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें तकरीबन 20 साल का समय लगता है। निश्चितरूप से चीन इतने समय तक इंतजार करने वाला नहीं है और वह ल्हासा के पोटाला पैलेस पर अपना दलाई लामा थोप देगा।

लेकिन वर्तमान दलाई लामा के तरकश में एक महत्वपूर्ण तीर है वैधता। वैसे दलाई लामा इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि उनका उत्तराधिकारी चीन के बाहर मुक्त संसार में पैदा होगा। यह संभव है कि अगले दलाई लामा की पहचान भारत के तवांग में हो, जहां छठे दलाई लामा का जन्म हुआ था। लेकिन इससे भारत-चीन संबंधों में टकराव का एक और बिंदु उत्पन्न हो जाएगा- दोनों देशों में एक-एक दलाई लामा। दलाई लामा पर राजनीतिक टकराव शी जिनपिंग को पसंद आएगा, चूंकि चीन का तिब्बत पर कब्जा है, इसलिए वह मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन यहां अमेरिका भी खिलाड़ी है। अमेरिकी कांग्रेस ने हाल ही में एक द्विदलीय प्रस्ताव पारित किया जो बीजिंग के किसी भी हस्तक्षेप को ठुकराते हुए इस बात की पुष्टि करता है कि केवल दलाई लामा को ही अपना उत्तराधिकरी चुनने का हक़ है। समय आने पर भारत व अमेरिका मिलकर दलाई लामा के चयन में सहयोग भी कर सकते हैं।

इसका अर्थ है कि भू-राजनीतिक शतरंज के खेल के केंद्र में तिब्बत की वापसी हो जाएगी। यह सही है कि नैतिक दृष्टि से भारत को उत्तराधिकारी के प्रश्न पर वर्तमान दलाई लामा के दृष्टिकोण का समर्थन करना चाहिए, जो वह कर भी रहा है, जैसा कि किरण रिजीजू के बयान से जाहिर है और चीन के चयन का विरोध करना चाहिए, लेकिन रणनीति के नजरिये से यह काफी महंगा सौदा होगा। भारत ने दलाई लामा को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की है कि वह लोगों की भीड़ जमा करें, धर्मशाला में अपने विदेशी अनुयायियों को आमंत्रित करें और विदेशी अधिकारियों से भी मिलें। भारत ने तिब्बत पर चीनी समप्रभुता को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उत्तराधिकारी के प्रश्न पर यह बात लागू नहीं होती है। इसलिए भारत दलाई लामा को धार्मिक व राजनीतिक आजादी देना जारी रख सकता है। फ्रं

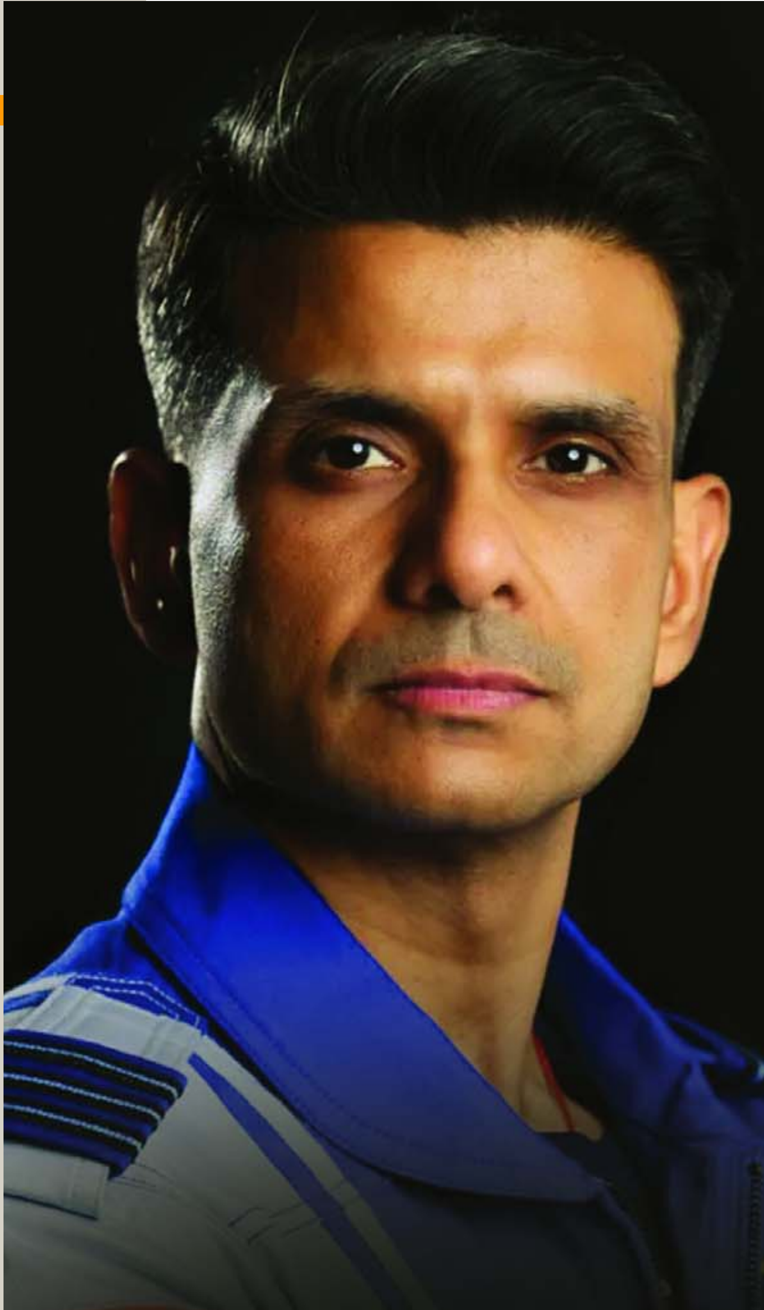

भारत के नए अंतरिक्ष युग की शुरुआत

शाहिद ए चौधरी

जैसे ही भारतीय समय के अनुसार दोपहर के 12.01 बजे पर फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 राकेट लिफ्ट-ऑफ हुआ, तो ऑडिटोरियम उल्लास के शोर से गूंज उठा। भारतीय स्पेस इतिहास में नई सुबह का सूरज निकला।

25 जून 2025 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के लिए सबसे बड़ा दिन था। लखनऊ के सीएमएस ऑडिटोरियम में उनके पिता शंभू दयाल व माता आशा शुक्ला पहली पंक्ति में अपनी नजरें स्क्रीन पर गड़ाए बैठे थे।जैसे ही भारतीय समय के अनुसार दोपहर के 12.01 बजे पर फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 राकेट लिफ्ट-ऑफ हुआ, तो ऑडिटोरियम उल्लास के शोर से गूंज उठा। भारतीय स्पेस इतिहास में एक नई सुबह का सूरज निकल आया था।

ऑडिटोरियम में 'हिप हिप हुर्रे' के नारे लगाते हुए दर्शक भांगड़ा करने लगे। शंभू दयाल ने एक पल में गर्व।खुशी व आंसुओं का अनुभव किया और बोले शुभांशु हमेशा से फोकस्ड, अनुशासित व देशभक्त रहा।शुभांशु के कंधे पर तिरंगा भी बता रहा था कि वह अपनी यात्रा में अकेले नहीं थे, बल्कि हम सभी को साथ लेकर चल रहे थे।

शुभांशु 'ड्रैगन' एक्सिओम-4 स्पेस कैप्सूल की पायलट सीट में थे। जो उन सहित चार सदस्यों की क्रू को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) लेकर पहुंचा, स्पेस में प्रवेश करने के कुछ मिनट बाद ही शुभांशु ने पृथ्वी को रेडियो संदेश भेजा, 'नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। क्या राइड है।

हम पृथ्वी की कक्ष में 7.5 किमी प्रति सेकंड के वेग (27,000 किमी प्रति घंटा) से चल रहे हैं।' 39-वर्षीय शुभांशु के साथ मिशन विशेषज्ञ हंगरी के 33 वर्षीय टिबोर कापू, अमेरिका की 65-वर्षीय कमांडर पेगी विटसन और पोलैंड के मिशन विशेषज्ञ 41-वर्षीय स्लावोस्ज उज्नांसकी हैं। इस 14 दिनों के मिशन में शुभांशु, विटसन के बाद सेकंड-इन-कमांड हैं। उनकी जिम्मेदारी निगरानी की है और अगर ऑटोमेशन फेल होता है, तो वह हस्तक्षेप करेंगे। लांच, डॉकिंग, पुनः प्रवेश व लैंडिंग के दौरान वह स्पेसक्राफ्ट ऑपरेशन, नेविगेशन व नियंत्रण में मदद करेंगे। आईएसएस में डॉकिंग के बाद वह प्रयोगों, टेक डेमो आदि में हिस्सा लेंगे।

41 वर्ष पहले राकेश शर्मा गए थे

3 अप्रैल 1984 को विंग कमांडर राकेश शर्मा सोवियत सोयूज टी-11 पर स्पेस में गए थे और वहां से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इस सवाल पर कि स्पेस से भारत कैसा दिखाई देता है, उन्होंने जवाब दिया था, 'सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।' अब लगभग 41 वर्ष बाद एक दूसरे भारतीय शुभांशु ने कार्मन रेखा पार की है।

शर्मा की स्पेस उड़ान से मानवों का स्पेस में जाने का कार्यक्रम आरंभ नहीं हुआ था, लेकिन इस बार गगनयान का काम चालू है और इसमें शुभांशु का अनुभव काम आएगा।शुभांशु ने स्पेस से संदेश दिया, 'यह आईएसएस को मेरी यात्रा का आरंभ नहीं है, बल्कि भारत के मानव स्पेस उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत है।' भारत 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करना चाहता है और चांद व उससे आगे तक क्रू मिशन ले जाना चाहता है।

पिछले चार दशक के दौरान दुनिया बदल गई है और भारत की स्पेस महत्वाकांक्षा भी।हालांकि शुभांशु प्राइवेट अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट पर गए हैं, लेकिन इससे भारत का मानव स्पेसफ्लाइट युग आरंभ होगा। शुभांशु के स्पेस में जाने के प्रतीकों को अनदेखा नहीं किया जा सकता।वह भारतीय वायु सेना के अधिकारी हैं और अब ऑर्बिट में अपने ग्लोबल समकालीनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं।

यह सही है कि गगनयान- इसरो का मानव स्पेसफ्लाइट प्रोजेक्ट, को अभी अपना पहला क्रू मिशन लांच करना शेष है, लेकिन शुभांशु की उड़ान प्रक्रिया टेस्ट करने, स्पेस के अनुकूलन होने, माइक्रोग्रेविटी को समझने के लिए और वह भी भारत के झंडे तले उड़ान भरते हुए एक तरह का पूर्व परीक्षण है।राकेश शर्मा जब 1984 में स्पेस में गए थे, तब भारत के पास मानव स्पेस कार्यक्रम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था। आज गगनयान अगले कुछ वर्षों में क्रू लांच की तैयारी कर रहा है।

भारत के पास अब ठोस स्पेस नीति है। शुभांशु का मिशन भूमिका है- भारतीयों की स्पेस में निरंतर मौजूदगी की। शुभांशु की उड़ान इसरो के लिए डाटा एकत्र करने का अवसर है। भारत को क्रू ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स, कक्षा में मेडिकल निगरानी और बंद स्थितियों के तहत व्यवहार विज्ञान के सिलसिले में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी।

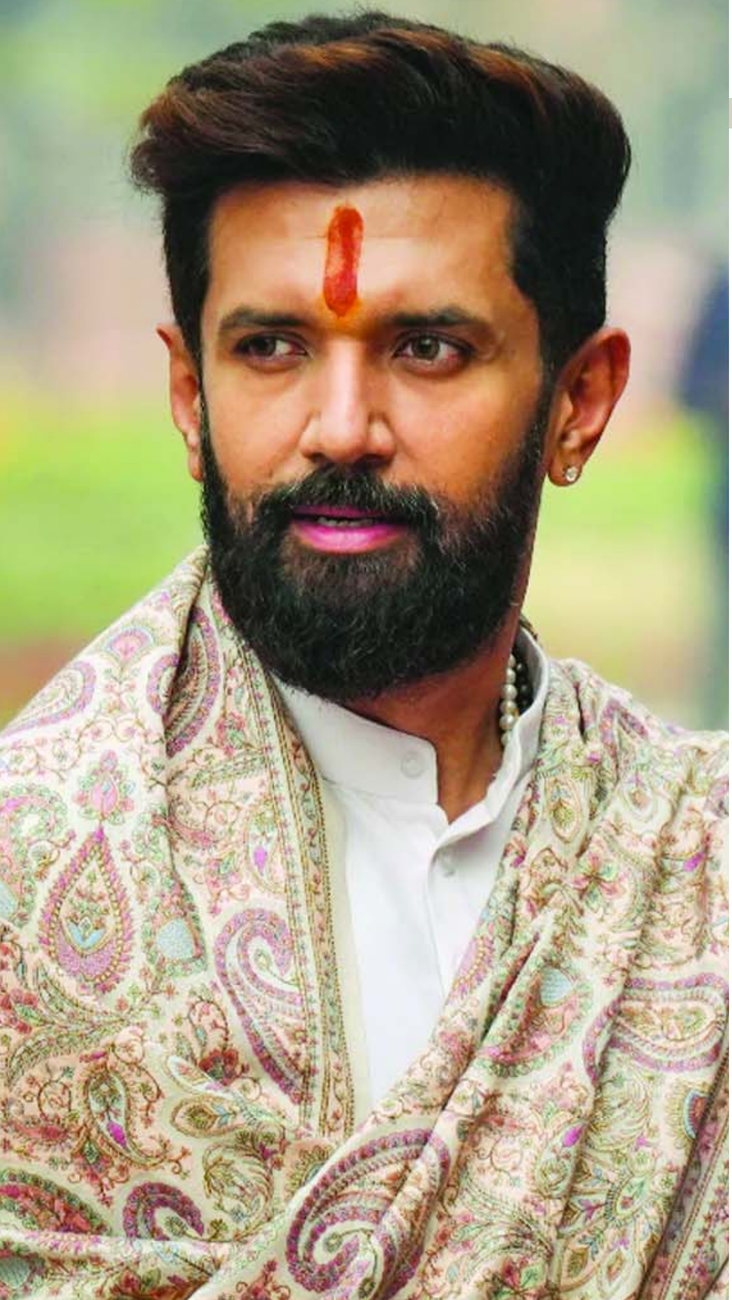

चिराग का 'शक्ति प्रदर्शन' चुनौती

संयम श्रीवास्तव

चिराग की रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ उल्लेखनीय है। नालंदा रैली के दौरान भीड़ के बेकाबू होने की खबरें भी सामने आई हैं। चिराग पासवान अपनी गाड़ी के ऊपर बैठकर समर्थकों का अभिवादन कर रहे थे, उत्साहित कार्यकर्ता उनकी गाड़ी पर चढ़ गए।

लगता है कि चिराग पासवान की लौ एक बार फिर बिहार चुनावों में लोजपा (आर) को रोशनी दिखाने से ज्यादा किसी के घर में आग लगाने में काम आने वाली है। नालंदा में आयोजित 'बहुजन भीम संकल्प समागम' में उनका हालिया शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। उनकी सक्रियता बिहार की राजनीति में हलचल मचा रखी है। उनके बयानों में सस्पेंस ऐसा है कि समझ नहीं आ रहा है कि वे महागठबंधन पर हमला कर रहे हैं या एनडीए पर ही दबाव बना रहे हैं।

दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चिराग की रणनीति और उनके द्वारा उठाए गए कदम दोनों गठबंधनों के लिए जटिल सियासी समीकरण पैदा कर रहे हैं। जाहिर है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और महागठबंधन दोनों के लिए वह एक गंभीर चुनौती के रूप में उभर रहे हैं। यह समझना बाकी है कि चिराग के इस खेल में क्या किसी और की भी भूमिका है या वे खुद सबको चक्कर में डाले हुए हैं।

अभी 2024 के लोकसभा चुनावों तक वो अपने पिता रामविलास पासवान की छाया में ही नजर आते थे। पर अब बिहार की राजनीति में उन्होंने खुद को स्थापित कर लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने बिहार में एनडीए के हिस्से के रूप में पांच सीटों पर शानदार जीत हासिल की, जिसमें हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई शामिल हैं। एनडीए में केवल लोजपा (आर) की स्ट्राइक रेट हंड्रेड परसेंट रही।

इस जीत के बाद चिराग केवल रामविलास पासवान के पुत्र नहीं रह गए हैं ,बल्कि उनका भी अपना एक सियासी कद हो गया है। नालंदा में आयोजित 'बहुजन भीम संकल्प समागम' जैसे कार्यक्रम, जहां हजारों समर्थकों की भीड़ उमड़ी वो चिराग की बढ़ती लोकप्रियता और संगठनात्मक ताकत का प्रतीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग अपनी रणनीति के चलते केवल दलितों के नेता से ऊपर उठ चुके हैं।

अब वे अति पिछड़ा वर्ग, युवा, और अन्य सामाजिक समूहों को भी अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' की विचारधारा और बिहार में सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो लाजिमी है कि खुद एनडीए के दलों की रूह कांप जाती है। तो क्या समझा जाए कि उनका शक्ति प्रदर्शन बिहार की सियासत में एक तीसरे ध्रुव की संभावना को भी जन्म दे रहा है?

नीतीश कुमार के इलाके में चिराग की ऐतिहासिक रैली

नालंदा के राजगीर में 29 जून 2025 को आयोजित 'बहुजन भीम संकल्प समागम' रैली में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की इतनी भारी भीड़ जुटी है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों ही गठबंधन के दलों में चिंता की लकीरें हैं। इस रैली में कितनी भीड़ जुटी उसे लेकर अलग-अलग दावे किए गए हैं। एक राष्ट्रीय चैनल के स्थानीय इकाई के एक्स पोस्ट के अनुसार, रैली में तीन लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया गया है। हालांकि बहुत से अन्य मीडिया संस्थानों ने अपार जनसैलाब और ऐतिहासिक भीड़ शब्दों का प्रयोग किया है।

जाहिर है कि भीड़ ज्यादा ही रही होगी। रैली के दौरान भीड़ के बेकाबू होने की खबरें भी सामने आई हैं। चिराग पासवान अपनी गाड़ी के ऊपर बैठकर समर्थकों का अभिवादन कर रहे थे, जब उत्साहित कार्यकर्ता उनकी गाड़ी पर चढ़ गए, जिससे अफरातफरी मच गई और उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। एक राष्ट्रीय चैनल के रिपोर्ट में भी कहा गया कि हजारों कार्यकर्ताओं के उत्साह के कारण सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा।

हालांकि कितनी भीड़ थी इसके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। पर जनसत्ता की एक रिपोर्ट बताती है कि सीवान में पिछले दिनों हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में करीब डेढ़ लाख लोग जुटे थे।जिसमें यूपी बॉर्डर नजदीक होने के चलते वहां से आने वाले लोगों की संख्या भी बहुत थी। तीन लाख का दावा अतिशयोक्ति हो सकता है पर अगर उसका आधा भी रहा हो कम नहीं है। रैली में भारी भीड़ की उपस्थिति और कार्यकर्ताओं का उत्साह चिराग पासवान की सियासी ताकत और उनकी रणनीति का असर विपक्ष और राजग के सहयोगी दलों ने जरूर महसूस किया होगा।

महागठबंधन के लिए कितनी चुनौती

बिहार में चिराग के पिता राम विलास पासवान ने बहुत कोशिश करके दलितों के बीच अच्छी पैठ बनाई थी। पर कभी भी वो पासवानों के अलावा अन्य दलित जातियों के सर्वमान्य नहीं बन पाए। दलितों के वोट पासवान की पार्टी को मिलते थे पर कांग्रेस और आरजेडी भी उसमें हिस्सेदारी करते थे। हालांकि पासवान वोट पर उनका पूरा नियंत्रण

होता था। पर आज की तारीख में अन्य दलित जातियों में तगड़े नेतृत्व के अभाव और चिराग पासवान की लगातार मेहनत के चलते स्थितियां बदल रही हैं।

चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाते हुए दलित समुदाय में गहरी पैठ बनाई है। उनकी रैलियों और कार्यक्रमों में दलित युवाओं की भारी भागीदारी इस बात का संकेत है कि वे प्रदेश में इस समय दलित समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो रहे हैं। 'बहुजन भीम संकल्प समागम' में बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों को केंद्र में रखकर चिराग ने दलित गौरव और सामाजिक न्याय के मुद्दे को और मजबूती दी है। जाहिर है कि लोजपा (आर) अगर सभी सीटों से चुनाव लड़ती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी के लिए होने वाला है।

महागठबंधन, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस, और वामपंथी दल जैसे प्रमुख सहयोगी शामिल हैं। इस गठबंधन का मुख्य आधार यादव, मुस्लिम, और दलित वोट बैंक रहा है। चिराग की रणनीति इस आधार को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है। अगर चिराग सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो बिहार में त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति पैदा हो सकती है।

जाहिर है कि इससे वोटों का बंटवारा होगा जो महागठबंधन के लिए नुकसानदायक साबित होगा। प्रदेश में बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां जीत का अंतर बहुत मामूली होता है। इन सीटों पर चिराग की पार्टी सीधे-सीधे एनडीए को फायदा पहुंचा सकती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग की बगावत ने जदयू को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस बार उनकी रणनीति महागठबंधन के लिए ज्यादा घातक साबित हो सकती है।

क्या एनडीए के लिए खतरा बन रहे चिराग पासवान

चिराग का शक्ति प्रदर्शन एनडीए के लिए भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग की बगावत ने एनडीए, खासकर नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) (जदयू) को भारी नुकसान पहुंचाया था। इस बार, हालांकि चिराग एनडीए का हिस्सा हैं पर उनकी चाल समझ में नहीं आ रही है। वो एक तरफ वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं दूसरी तरफ वो अपनी रैलियों में पीएम मोदी के कशीदे पढ़ते हैं। उनके निशाने पर तेजस्वी यादव और कांग्रेस होती है। नालंदा की रैली में उनका सारा फोकस कांग्रेस और आरजेडी की नाकामियों पर था। पर उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षा और आक्रामक रणनीति गठबंधन के भीतर तनाव पैदा कर रही है।

नालंदा, जो नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है, में चिराग का शक्तिप्रदर्शन और चिराग की 'नए नेतृत्व' की बात जदयू के लिए असहज स्थिति पैदा कर रही है। चिराग ने अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं, और उनकी मुख्यमंत्री पद की संभावित महत्वाकांक्षा ने जदयू को असहज करती है। 2020 में चिराग की बगावत ने जेडीयू की 43 सीटों पर समेट दिया था। लोग अटकलें लगा रहे हैं कि इस बार भी क्या उनकी रणनीति नीतीश को नियंत्रित करने के लिए हैं?

किसी का नाम लिए बिना चिराग कहते हैं कि, मेरे रास्ते में बाधाएं खड़ी की जा रही हैं, लेकिन मैं निराश नहीं होने वाला हूं। मेरी पार्टी में विभाजन और मेरे परिवार में दरार पैदा करके मुझे तोड़ने के पहले के प्रयास मुझे हतोत्साहित करने में विफल रहे हैं। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि वे सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में फैल जाएं और राजग की जीत के लिए उसी तीव्रता के साथ लड़ें, जैसे चिराग पासवान खुद मैदान में हों। चिराग के भाषण में वो कौन है जिसने उनके परिवार में दरार डालने की कोशिश की। यह बताने की जरूरत नहीं है। हो चाहे कोई भी आम जनता यह मानकर चलती है कि चिराग का तंज नीतीश कुमार पर ही होगा।

चिराग ने 25-35 विधानसभा सीटों की मांग की है। जाहिर है कि एनडीए के लिए यह एक जटिल मुद्दा बन सकता है। बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के सबसे खास दल हैं। दोनों की भूख इतनी ज्यादा है कि चिराग को इतनी सीटें मिलने से रहीं। बीजेपी खुद कोशिश में है कि इस बार पिछली बार से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। जबकि जदयू नीतीश के नेतृत्व में अपनी स्थिति मजबूत रखना चाहती है। इस तरह अगर चिराग की मांग पूरी नहीं होती है तो उनके पास फिर से बगावत का रास्ता चुनने का विकल्प हो सकता है।अब ये समझना मुश्किल हो सकता है कि क्या इसमें बीजेपी की अंदरूनी राजनीति तो नहीं काम कर रही है।

अन्य सहयोगियों का असंतोष

चिराग की रैलियों से एनडीए के अन्य सहयोगी, जैसे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) के उपेंद्र कुशवाहा भी सहमें हुए हैं। यह संयोग है या प्रयोग है कि उपेंद्र कुशवाहा की दो रैलियां चिराग पासवान की रैलियों के दिन ही पड़ी हैं। यह किसकी तरफ से ताकत का प्रदर्शन हो सकता है?

कुशवाहा के अलावा मांझी भी दलित और अति पिछड़ा वोट बैंक पर दावा करते हैं। चिराग की रणनीति से उनकी सियासी जमीन को भी कमजोर कर रही है। इससे गठबंधन के भीतर आंतरिक तनाव बढ़ रहा है।कुछ दिनों पहले जीतनराम मांझी के गढ़ शाहबाद क्षेत्र में लोजपा (रा) का कार्यक्रम हुआ था। इसमें महादलित वर्ग के अलावा सर्वसमाज की भीड़ भी पहुंची थी। कुछ रिपोर्ट में बताया गया कि इससे खफा मांझी ने घबराहट में चिराग को खूब खरी-खोटी सुनाई थी।

सुप्रीम कोर्ट के दो माननीय जजों की बेंच ने तीन जुलाई को सड़क दुर्घटना में बीमा भुगतान को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। दोनों विद्वान जजों ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु गाड़ी चलाते समय अपनी गलती से या लापरवाही से हुई है तो उसका परिवार बीमा की राशि का दावा करने का हकदार नहीं है। इस मामले में पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने यही फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।

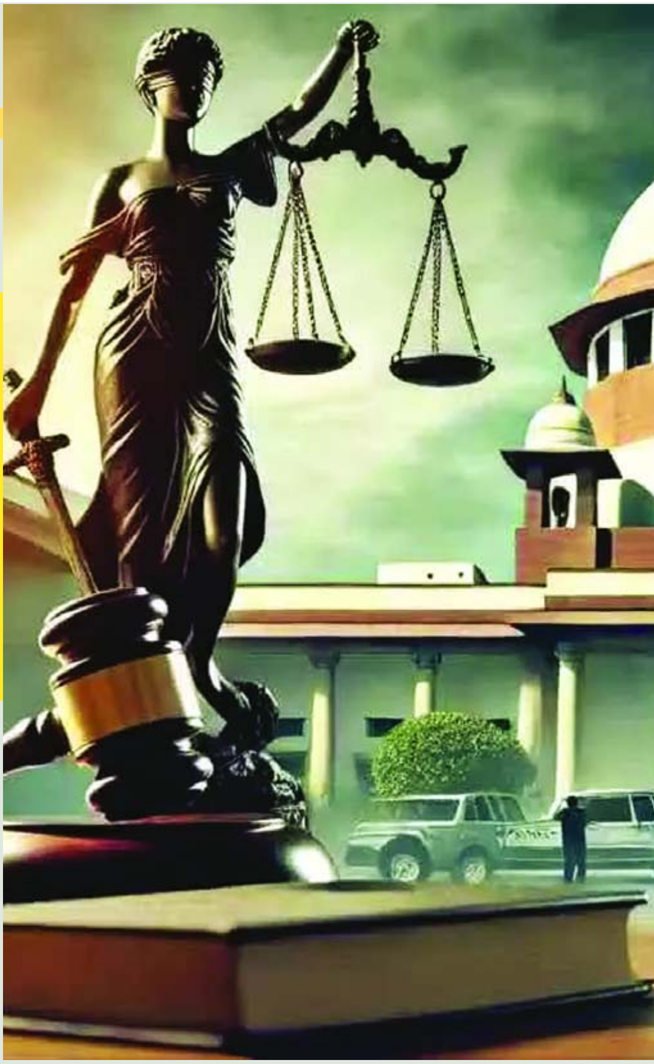

अजीत द्विवेदी

बीमा कंपनियां हो जाएंगी बेलगाम

कर्नाटक हाई कोर्ट ने पिछले साल 23 नवंबर को अपने फैसले में कहा था कि पुलिस के आरोपपत्र में कहा गया है कि हादसा गाड़ी चला रहे व्यक्ति की लापरवाही और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने की वजह से हुई थी, इसलिए बीमा कंपनी उसके परिवार को मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है।

इतना ही नहीं हाई कोर्ट के फैसले में यह भी कहा गया था कि, 'जब मृतक के कानूनी प्रतिनिधि दावा करते हैं, तो उन्हें यह साबित करना होगा कि मृतक खुद अपनी लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं था। उन्हें यह भी साबित करना होगा कि मृतक पॉलिसी के अंतर्गत आता है, ताकि बीमा कंपनी कानूनी उत्तराधिकारियों को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो'। इसका मतलब है कि अगर किसी बीमा कंपनी ने कह दिया कि बीमित व्यक्ति की मौत उसकी अपनी गलती या लापरवाही से हुई है, तो उसे यह साबित करने की जरुरत नहीं होगी। मौत अपनी गलती या लापरवाही से नहीं हुई है यह साबित करने का काम परिवार को करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सही ठहराया और परिवार के दावे को खारिज कर दिया।

यह बहुत बड़ा और अहम फैसला है। ध्यान रहे भारत में पहले ही बीमा कंपनियों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। खास कर जनरल इंश्योरेस, जिसमें स्वास्थ्य, सड़क दुर्घटना, वाहन, मकान और कीमती वस्तुओं का बीमा शामिल है, उनकी कंपनियों का रिकॉर्ड बहुत खराब है। स्वास्थ्य बीमा के मामले में तो कई निजी कंपनियां ऐसी हैं, जिनका बीमा क्लेम निपटाने का औसत 50 फीसदी के करीब है। यानी वे आधे दावे तो कोई न कोई कमी निकाल कर खारिज कर देती हैं। स्वास्थ्य बीमा के मामले में कंपनियों का सामान्य औसत यह है कि वे अगर एक सौ रुपए का प्रीमियम लेती हैं तो दावा करने पर अधिकतम भुगतान 80 रुपए का करती हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बीमा कंपनियों के हाथ में एक बड़ा हथियार थमा देता है। वे इस फैसले के आधार पर जीवन बीमा से लेकर सामान्य बीमा तक के दावों में बीमित व्यक्ति की कमी निकाल कर उसके परिजनों के दावे को खारिज करने की कोशिश कर सकती हैं। अगर बीमित व्यक्ति के परिजनों पर यह सबूत जुटाने का भार डाल दिया जाता है कि वे साबित करें कि बीमित व्यक्ति की मौत उसकी अपनी लापरवाही या उसकी अपनी गलती से नहीं हुई है तो यह और बड़ा अन्याय है। सोच कर देखें कि सर्वोच्च अदालत के इस फैसले का किस तरह से और कितना दुरुपयोग हो सकता है!

कर्नाटक का मामला सड़क दुर्घटना का था, जिसमें रवीशा नाम के व्यक्ति को लापरवाही से और तेज रफ्तार गाड़ी चलाने का दोषी बताया गया और उस आधार पर उनके परिवार को बीमा कंपनी ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया। बीमा कंपनियां किसी भी किस्म के दावे को खारिज करने के लिए इस तरह के उपाय आजमा सकती हैं। मिसाल के तौर पर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा है और वह बीमार पड़ जाता है तो बीमा कंपनियां दावा कर सकती हैं कि वह अपनी गलती या लापरवाही से बीमार पड़ा है तो क्या इस आधार पर बीमा की रकम का दावा खारिज किया जा सकता है? आमतौर पर स्वास्थ्य बीमा करने वाली कंपनियां ऐसा करती हैं। तभी कई निजी कंपनियों का स्वास्थ्य बीमा के दावों का भुगतान करने का औसत 50 से 60 फीसदी का है। ऊपर से अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, जिसका दुरुपयोग बीमा कंपनियां कर सकती हैं।

जीवन बीमा से लेकर स्वास्थ्य बीमा तक कंपनियां बीमित व्यक्तियों का दावा खारिज करने के बहाने खोजती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह बीमा कंपनियों का पसंदीदा बहाना रहा है। वे हर वाहन दुर्घटना में बीमित चालक के ऊपर लापरवाही से गाड़ी चलाने या गलती करने के आरोप लगाती हैं। इसी तरह स्वास्थ्य बीमा के मामले में भी बीमा दस्तावेजों में छोटे छोटे अक्षरों में छपी शर्तों के जरिए क्लेम अटकाया जाता है। बीमा कराते समय कंपनियों के एजेंट कई ऐसी चीजें समझाते हैं, जो उसमें शामिल नहीं होती हैं। बीमा कराने वाले व्यक्ति आमतौर पर एजेंट की बातों पर भरोसा करते हैं। वे बेहद बारीक अक्षरों जटिल कानूनी भाषा में

छपी लंबी चौड़ी शर्तें नहीं पढ़ते हैं। बाद में उनको इसका नुकसान होता है। इसी तरह कंपनियों के एजेंट कई बीमारियों या आदतों की अनदेखी करके बीमा कर देते हैं लेकिन बाद में कंपनियां आरोप लगाती हैं कि बीमित व्यक्ति ने जानकारी छिपाई और इस आधार पर दावा खारिज कर दिया जाता है। इसी तरह जीवन बीमा में भी बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद जांच पड़ताल के नाम पर देरी की जाती है या दावा खारिज करने के उपाय खोजे जाते हैं।

ध्यान रहे भारत में बीमा कराने वाली आबादी बहुत कम है। कोरोना के बाद भी इस मामले में कोई बदलाव नहीं आया। बीमा कंपनियों की नियामक एजेंसी इरेडा के तत्कालीन चेयरमैन देवाशीष पांडा ने 2023 में नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी की एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि भारत में 95 फीसदी लोगों के पास बीमा कवर नहीं है। मध्य वर्ग के 84 फीसदी लोगों के पास बीमा नहीं है। देश के तटीय क्षेत्रों और दूसरे व तीसरे श्रेणी के शहरों में 77 फीसदी लोगों ने बीमा नहीं कराया है।

देश की 73 फीसदी आबादी के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है। यह स्थिति तब है, जब भारत में सामान्य बीमा की 34 और जीवन बीमा की 24 कंपनियां काम कर रही हैं। इतनी कंपनियों के होने के बावजूद बीमा कराने वालों की संख्या बहुत कम है तो कई कारणों में से एक कारण बीमा कंपनियों का व्यवहार और दावों के निपटान में देरी या क्लेम नहीं सेटल किया जाना भी है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर बीमा कंपनियां बेलगाम हो जाएं और हर क्लेम में कमी निकालने लगें तो क्या होगा? कर्नाटक के मामले में पुलिस रिपोर्ट थी कि गाड़ी चला रहा व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और हादसे में उसकी गलती थी। अगर स्वास्थ्य या जीवन बीमा के मामले में इसी तरह की रिपोर्ट डॉक्टर या अस्पताल दे दे और बीमित व्यक्ति की गलती बता दे तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब यह सोच कर देना होगा कि महाशक्तिशाली बीमा कंपनियों के लिए भारत में पुलिस या किसी अस्पताल से मनमाफिक रिपोर्ट लेना कितना आसान होता है!

कंपनियां बड़ी आसानी से पुलिस या अस्पताल से रिपोर्ट ले सकती हैं कि हादसा, बीमारी या मृत्यु बीमित व्यक्ति की गलती या उसकी लापरवाही से हुई है। उसके बाद बीमित व्यक्ति के परिवार की यह जिम्मेदारी हो जाएगी कि वे इस रिपोर्ट को गलत साबित करें। ऐसे में कितने लोग पुलिस, अस्पताल या बीमा कंपनी का मुकाबला कर पाएंगे? ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अदालतों से भी कोई राहत नहीं मिल पाएगी। फ्रं

बीमा कंपनियों की मनमानी पर भी कसेगी नकेल

भारत में स्वास्थ्य सेवाएं महंगी होती जा रही हैं जिस पर सरकार लगाम लगाने की तैयारी में है। सरकार मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम पोर्टल्स को वित्त मंत्रालय के अधीन लाने की योजना बना रही है जिससे हेल्थ इंश्योरेंस और पॉलिसी होल्डर मरीजों के बेहिसाब मेडिकल बिलों पर नियंत्रण किया जा सके। भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण स्वास्थ्य प्रदाताओं की निगरानी करेगा ताकि मरीजों पर अनावश्यक बोझ न पड़े।

भारत सरकार स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा अधिक शुल्क वसूलने पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा स्वास्थ्य बीमा दावा पोर्टल को वित्त मंत्रालय और बीमा नियामक के अधीन लाने की योजना बना रही है। पेशेवर सेवा फर्म एआन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में स्वास्थ्य सेवा की लागत 2025 में 13 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। यह वैश्विक औसत 10 प्रतिशत से अधिक है और एक साल पहले दर्ज 12 प्रतिशत से भी अधिक है।

सूत्रों ने बताया कि सरकार और भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) द्वारा किए गए विश्लेषण में पाया गया है कि अस्पताल मरीजों के इलाज का खर्च बढ़ा रहे हैं और ज्यादा पैसे का बीमा कराने वाले मरीजों से अधिक शुल्क वसूल रहे हैं। इसकी वजह से बीमा कंपनियां ज्यादा प्रीमियम वसूल रही हैं। इससे कुछ लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा कराना आसान नहीं रह गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और मरीजों के बीच गेटवे के रूप में कार्य करता है।

बीमा कंपनियों की शक्ति में होगा सुधार

इसकी सख्त निगरानी से उपचार दरें निर्धारित करने के लिए बीमा कंपनियों की शक्ति में सुधार होगा। वर्तमान में एक्सचेंज की देखरेख स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा की जाती है। प्राधिकरण की वेबसाइट के अनुसार, इसे बीमा नियामक के साथ परामर्श करके विकसित किया गया है।

इरडा स्वास्थ्य एक्सचेंज का विनियमन नहीं करता है, बल्कि इस प्लेटफार्म पर बीमा कंपनियों का विनियमन करता है। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम आय में वार्षिक वृद्धि दर 2024-25 में घटकर नौ प्रतिशत रह गई है, जो एक वर्ष पहले 20 प्रतिशत थी। प्रीमियम कई लोगों के लिए वहन करने योग्य नहीं रह गया है, जिसके कारण पालिसी का नवीनीकरण कम हो रहा है।

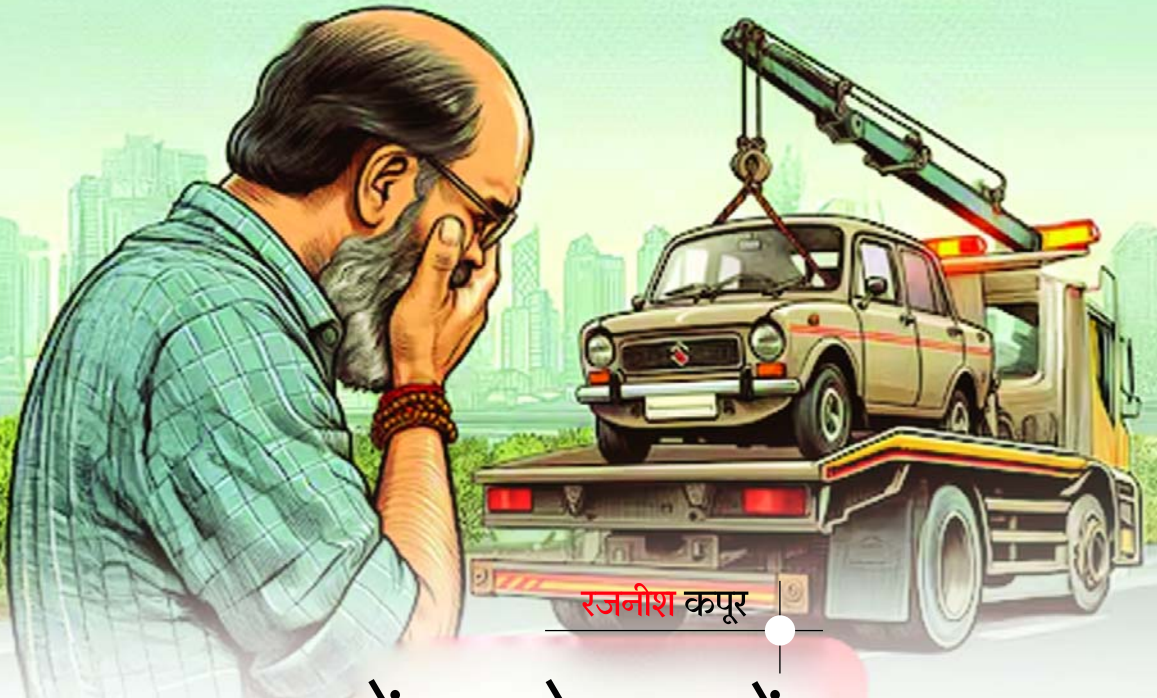

दिल्ली में लगभग 62 लाख वाहन इस नीति से प्रभावित होने वाले थे, जिनमें कार, दोपहिया वाहन, ट्रक और यहां तक कि विंटेज वाहन भी शामिल थे। कई लोगों के लिए, ये वाहन केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिरता का आधार थे। उ दिल्ली की हवा को साफ करने का लक्ष्य तभी सार्थक होगा, जब पर्यावरण और जनता के हितों के बीच संतुलन स्थापित किया जाए।

रजनीश कपूर

भारत में पुराने वाहनों का मसला अलग है!

दिल्ली, भारत की राजधानी, जो अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समृद्धि के साथ-साथ वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या के लिए भी जानी जाती है, एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा का विषय है दिल्ली सरकार का पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर ईंधन आपूर्ति रोकने और उनकी जब्ती का फैसला। इस नीति का उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना था, लेकिन इसके लागू होने और फिर स्थगित होने की प्रक्रिया ने जनता के बीच भ्रम और असंतोष को जन्म दिया।

क्या यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया या जन दबाव का परिणाम था? क्या सरकारें ऐसे फ़ैसले बिना सोचे-समझे लेती हैं?

दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2025 से 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन देने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। यह निर्णय कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (ष्टक्तरू) के निर्देश पर आधारित था, जो 2014 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (हृत्रञ्ज) और 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से प्रेरित था। इन आदेशों में दिल्ली में पुराने वाहनों के उपयोग और सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग पर रोक प्लेट रिकग्निशन कैमरों का उपयोग कर वाहनों की उम्र की पहचान की जानी थी, और जो वाहन 'एंड ऑफ लाइफ' श्रेणी में आते, उन्हें ईंधन देने से मना किया जाता। साथ ही, उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त करने और स्क्रैप करने का भी प्रावधान था।

इस नीति का प्राथमिक उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करना था। आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में वाहनों से होने वाला प्रदूषण स्थानीय प्रदूषण का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा है। पुराने वाहन, जो आधुनिक उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करते, पीएम 2.5 और अन्य हानिकारक प्रदूषकों के प्रमुख स्रोत हैं। इस नीति को लागू करने के पीछे पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार का लक्ष्य था।

हालांकि इस नीति का उद्देश्य सराहनीय था, लेकिन इसके कार्यान्वयन ने जनता के बीच व्यापक भ्रम और असंतोष पैदा किया। 1 जुलाई को नीति लागू होने के कुछ ही दिनों बाद, पेट्रोल पंपों पर पुराने वाहनों को ईंधन देने से मना किया जाने लगा और कुछ मामलों में वाहनों को जब्त भी किया गया। इससे मध्यम वर्ग और निम्न-मध्यम वर्ग के लोगों में खलबली मच गई, जो अपनी आजीविका के लिए इन पुराने वाहनों पर निर्भर हैं।

दिल्ली में लगभग 62 लाख वाहन इस नीति से प्रभावित होने वाले थे, जिनमें कार, दोपहिया वाहन, ट्रक और यहां तक कि विंटेज वाहन भी शामिल थे। कई लोगों के लिए, ये वाहन केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिरता का आधार थे। उदाहरण के लिए, छोटे व्यापारी, डिलीवरी कर्मचारी और ऑटो-रिक्शा चालक जैसे लोग इन वाहनों पर निर्भर हैं। अचानक ईंधन की आपूर्ति बंद होने से उनकी आजीविका पर संकट मंडराने लगा।

इसके अलावा, नीति के कार्यान्वयन में तकनीकी खामियां भी सामने आईं। ह्क्क्क कैमरों की स्थापना और उनके ्लेट्स की पहचान में असमर्थता। इन तकनीकी समस्याओं ने नीति को और जटिल बना दिया।

पर्यावरण के दृष्टिकोण से, पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाना एक तार्किक कदम था। लेकिन इसके साथ ही यह भी तर्क दिया जा रहा था कि यदि कोई पुराना वाहन मौजूदा प्रदूषण के मानकों में 'पास' पाया जाता है, उसके पास वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र है तो वह प्रदूषण नहीं कर रहा। तो ऐसी स्थित में इस श्रेणी की गाड़ी को प्रतिबंधित क्यों किया जाए?

नीति के लागू होने के कुछ ही दिनों बाद, 3 जुलाई को दिल्ली सरकार ने इसे स्थगित कर दिया और इसे 1 नवंबर 2025 तक टाल दिया। इस फैसले के पीछे जनता का तीव्र विरोध और तकनीकी चुनौतियां प्रमुख कारण थे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने सीएक्यूएम को पत्र लिखकर इस नीति को 'समय से पहले और संभावित रूप से प्रतिकूल' बताया, और तकनीकी और बुनियादी ढांचे की कमियों का हवाला दिया। इसके अलावा, एक सर्वेक्षण में 79 प्रतिशत दिल्लीवासियों ने इस नीति का विरोध किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जन दबाव ने सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में इस नीति की व्यवहार्यता को चुनौती दी, जिसने भ्रम को और बढ़ाया।

क्या यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया? निश्चित रूप से, नीति के कार्यान्वयन से पहले पर्याप्त जन जागरूकता अभियान, वैकल्पिक परिवहन समाधान और स्क्रैपिंग सुविधाओं की कमी ने इसे जल्दबाजी का फैसला साबित किया। तकनीकी बुनियादी ढांचे की अपर्याप्तता ने इसकी विफलता को और उजागर किया।

दिल्ली सरकार का पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध और जब्ती का फैसला पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक साहसिक कदम था, लेकिन इसकी खराब योजना और कार्यान्वयन ने इसे जनता के लिए परेशानी का सबब बना दिया।

पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए दीर्घकालिक समाधान जैसे इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देना, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना और उत्सर्जन-आधारित नीतियां अपनाना अधिक प्रभावी हो सकता है।

सरकार ने इस नीति को 1 नवंबर तक स्थगित कर जनता को राहत तो अवश्य दी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि भविष्य में ऐसी नीतियों को लागू करने से पहले बेहतर योजना, जन जागरूकता और बुनियादी ढांचे की जरूरत है। दिल्ली की हवा को साफ करने का लक्ष्य तभी सार्थक होगा, जब पर्यावरण और जनता के हितों के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। फ्रं

अपराधियों से निपटने में विफल नीतीश सरकार देगी हथियार लाइसेंस

योगेंद्र योगी

बिहार सरकार ने यह फैसला राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों पर हमले और हत्याओं की बढ़ती घटनाओं के कारण लिया है। इसके विपरीत सच्चाई यही है कि ऐसा करके नीतिश सरकार ने ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को साधने की कोशिश की है।

राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इससे बेशक राज्य का चाहे कितना ही नुकसान क्यों ना हो। बिहार जैसा प्रदेश जो एक दौर में नस्लवाद और जातीय हिंसा के लिए कुख्यात रहा, अब भी अपराधों के मामले में पीछे नहीं हैं। बिहार में सत्ता में कोई भी राजनीतिक दल रहा हो, अपराधों से सभी का गहरा रिश्ता रहा है। बिहार में कानून-व्यवस्था हमेशा से एक चुनौती रही है। हालात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। इसका सरकार ने आसान विकल्प खोज लिया है। वह यह है कि अब मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य जैसे जनप्रतिनिधि आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार रख सकेंगे। जिससे लगभग ढाई लाख जनप्रतिनिधियों को फायदा मिलेगा।

राज्य के गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में आवेदनों की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश जारी किया है। बिहार में आगामी चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नीतिश सरकार के इस फैसले को चुनाव से जोड़ कर देखा जा रहा है।

बिहार सरकार ने यह फैसला राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों पर हमले और हत्याओं की बढ़ती घटनाओं के कारण लिया है। इसके विपरीत सच्चाई यही है कि ऐसा करके नीतिश सरकार ने ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को साधने की कोशिश की है। यदि नीतिश कुमार के इस फैसले को पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा के हित में भी माना जाए तब यह प्रदेश में अपराध की हालत को दर्शाता है। जिस प्रदेश में जनप्रतिनिधी ही सुरक्षित नहीं हैं, वहां आम अवाम की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। सवाल यह भी है कि लाखों की संख्या में हथियारों के लाइसेंस देने से क्या राज्य में हिंसा में बढ़ोत्तरी नहीं होगी। बिहार में यदि पुलिस तंत्र प्रभावी और मजबूत होता तो यह नौबत नहीं आती कि लाखों जनप्रतिनिधियों को हथियारों के लिए लाइसेंस दिया जाए। इससे जाहिर है कि मुख्यमंत्री नीतिश ने अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के बजाए हथियारों के लाइसेंस देने का आसान विकल्प चुना है। बड़ा सवाल यह भी है कि जनप्रतिनिधी अपनी सुरक्षा हथियारों से कर लेंगे, किन्तु प्रदेश की अवाम का क्या होगा।

मुख्यमंत्री नीतीश का यह फैसला दर्शाता है कि बिहार में कानून-व्यवस्था लगभग ध्वस्त हो चुकी है। बिहार पुलिस हिंसक अपराध के मामलों में आई तेजी है। बिहार में पिछले 10 वर्षों में राज्य में फर्जी शस्त्र लाइसेंस, अवैध बंदूक और गोला व बारूद की अनाधिकृत तौर पर बिक्री बढ़ी है और यह प्रदेश में बढ़ रही हिंसा की बड़ी वजह है। राज्य के अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने इस दिशा में एक अध्ययन भी किया है। बिहार पुलिस ने यह अध्ययन बिहार पुलिस के महानिदेशक विनय कुमार को सुपर्द किया। पुलिस ने राज्य में हिंसक अपराधों में वृद्धि को सीधे तौर पर राज्य में अवैध हथियारों और गोला-बारूद की बढ़ती बिक्री से जोड़ा है और हत्या, फिरौती के लिए अपहरण, डकैती, लूट, बैंक डकैती और सड़क डकैती जैसे अपराधों के लिए इसे जिम्मेदार माना है। एनसीआरबी (राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो) के अनुसार, बिहार 2017 से 2022 के बीच हिंसक अपराधों के मामले में लगातार शीर्ष पांच राज्यों में शुमार रहा है।

इस अध्ययन में यह बात सामने आई कि प्रति वर्ष पटना में 82 हिंसा के मामले औसतन रूप से सामने आए हैं और राज्य की राजधानी हिंसा की राजधानी बन चुकी है। पटना के बाद क्रमशः मोतिहारी में 49.53, सारण 44.08), गया 43.50, मुजफ्फरपुर 39.93 और वैशाली में 37.90 मामले प्रति वर्ष औसतन दर्ज किए जा रहे हैं। हिंसक अपराधों की सबसे अधिक संख्या वाले शीर्ष 10 जिलों में पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, नालंदा और बेगूसराय शामिल हैं। ये उन शीर्ष 10 जिलों में से भी हैं जिनमें सबसे अधिक आर्म्स एक्ट के मामले हैं।

अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अवैध आग्नेयास्त्र और हिंसक अपराध के मामलों के बीच घनिष्ठ संबंध है। एक दशक के अपराधों के अध्ययन के आधार पर विशेष कार्य बल ने बिहार के डीजीपी से सिफारिश की है कि वे व्यक्तिगत गोला-बारूद कोटा को मौजूदा 200 से घटाकर न्यूनतम कर दें। साथ ही यह भी सिफारिश की गई है कि डीजीपी कार्यालय आग्नेयास्त्रों का उपयोग करने में असमर्थ मानता है, उनके लाइसेंस रद्द कर दे। लाइसेंस प्राप्त मिनीगन कारखानों की निगरानी करें। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में भारत में अपराधों के मामलों में शीर्ष पर उत्तर प्रदेश रहा। इसके बाद अपराधों के पायदान पर क्रमशः केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार है।

अपराधों की श्रेणी में चोरी के मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए गए। इसके बाद दूसरे नंबर पर डकैती और उत्पीडन् के मामले सामने आए। अपराधों में आंकड़ों के लिहाज से तीसरे नंबर बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। इस मामले में चिंता की बात यह है कि इसमें वर्ष 2023 के मुकाबले 1.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है जबकि अपहरण के मामलों में पिछले वर्ष के मुकाबले 5.1 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराधों से संबंधित दर्ज और निपटाए गए मामलों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में क्रमशः 13.05 प्रतिशत और 19.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021-22 में दर्ज सभी मामलों में से घरेलू हिंसा के लिए सबसे ज्यादा 4,889 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद दहेज उत्पीडन् (787), यौन उत्पीडन् (116), दूसरी शादी (81), मोबाइल/साइबर से जुड़े अपराध (59), बाल विवाह (24), कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन् (22), मानव तस्करी (12), दहेज हत्या (5) और अन्य (1,297) दर्ज किए गए। 2021-22 में 86 प्रतिशत दर्ज मामलों का निपटारा किया गया, जबकि 2020-21 में यह 82 प्रतिशत था। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने आंकड़े और आबादी के आधार पर दावा किया है कि 2004 के मुकाबले 2025 में अपराध में भारी गिरावट आयी है। लालू सरकार के काल खंड से तुलना करते हुए डीजीपी ने कहा कि 20-21 साल पहले सालाना 500- 1000 फिरौती के लिए अपहरण के मामले दर्ज होते थे।

अब यह आंकड़ा 50 के आसपास है। डकैती के मामलों में भी पहले 1200 से अधिक वार्षिक घटनाएं होती थीं, जो अब घटकर 150 के करीब पहुंच चुकी हैं। गौरतलब है कि बिहार पहले से ही भ्रष्टाचार को लेकर बदनाम रहा है। लालू सरकार के चारा और जमीन के बदले में रेलवे में नौकरी को लेकर लालू यादव जेल में हैं। नीतिश कुमार से उम्मीद थी कि बिहार में भ्रष्टाचार और अपराधों में सुधार होगा। किन्तु जिस तरह हथियारों की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बिहार का भविष्य उज्ज्वल नजर नहीं आता। फ्रं

नीति आयोग ने तेजी से बढ़ती गिग वर्क क्रांति के नए क्षेत्र के रूप में भारत की क्षमता को स्वीकार किया है। फिर भी, गिग वर्कर्स की वास्तविक संख्या का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। नीति आयोग ने 2019-20 में 68 लाख गिग वर्कर्स का अनुमान लगाया था, जिसके 2030 में बढ़कर 2.35 करोड़ हो जाने का अनुमान है।

सौयदीप चटोपध्याय

भारतीय गिग वर्कर्स के लिए नीति जरूरी

उच्च वेतन और कमाई की संभावना, कार्यसूची का व्यवस्थित होना और कौशल व शैक्षिक योग्यता के मामले में प्रवेश में कम बाधा जैसे कई कारकों के संयोजन ने गिग वर्कर्स की संख्या में इस तीव्र वृद्धि में योगदान दिया है।

इनमें से लगभग आधे लोग दो क्षेत्रों, खुदरा व्यापार और परिवहन, में कार्यरत हैं। हालांकि, अत्यधिक परिवर्तनशील कार्य समय, नौकरी की सुरक्षा का लगभग अभाव और कौशल विकास के सीमित अवसर इन गिग वर्कर्स की आजीविका वृद्धि की संभावना को प्रभावित करते हैं।

इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित घटनाओं ने गिग श्रमिकों के कामकाजी माहौल को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। आईएलओ (2024) की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकतर गिग श्रमिकों को प्रति सप्ताह 50-60 घंटे काम करना पड़ता है और डिलीवरी कर्मचारियों को सभ्य कमाई सुनिश्चित करने के लिए प्रति दिन 90-120 किलोमीटर की मोटरसाइकिल चलानी पड़ती है।

इस दौरान श्रमिक सड़कों पर चलते हैं और सीधे चरम मौसम की घटनाओं के संपर्क में आते हैं। इस तरह की घटनाओं की गंभीरता केवल गहरी होने वाली है। जैसा कि भारतीय मौसम विभाग के अधिक लगातार और तीव्र हीटवेव दिनों के अनुमानों से साफ है। अत्यधिक गर्मी की आर्थिक लागत काफी अधिक है।

भारतीय रिजर्व बैंक (2024) की रिपोर्ट में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत के नुकसान के साथ-साथ अत्यधिक गर्मी से प्रेरित स्वास्थ्य समस्याओं और गर्मी के संपर्क में आने वाले श्रमिकों के बीच आजीविका के नुकसान का अनुमान लगाया गया है।

गिग वर्कर्स की कमजोरियां: इस प्रकार, शहरों को कार्यस्थल के रूप में देखना और उनकी सुविधाएं, जलवायु आपदाओं का सामना करने की श्रमिकों की सहनशक्ति को महत्वपूर्ण रूप से आकार देती हैं। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स यूनियन और हैदराबाद में हीटवॉच द्वारा 166 गिग वर्कर्स पर किए गए एक सर्वेक्षण से शहरी परिदृश्य की भयावहता का पता चलता है। लगभग 40 प्रतिशत श्रमिकों के पास स्वच्छ और ठंडे पेयजल की सुविधा नहीं थी, जबकि 60 प्रतिशत से अधिक ने बताया कि उनके पास स्वच्छ शौचालय नहीं हैं। 20 प्रतिशत से भी कम श्रमिक आराम करने के लिए जगह या पंखे जैसी ठंडी सुविधाओं तक पहुंच पा रहे थे।

ऐसे में बुनियादी शहरी सुविधाओं तक सीमित पहुंच काम को और भी कठिन बना देती है। इसके अलावा, केवल शौचालयों तक पहुंच का मतलब यह नहीं है कि वे उपयोग योग्य हैं। कई शहरों में, स्वच्छता और सुरक्षा दो प्रमुख मुद्दे हैं। प्रजा फाउंडेशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुंबई के 6800 सामुदायिक शौचालय ब्लॉकों में से दो-तिहाई से अधिक में पानी और बिजली के कनेक्शन नहीं हैं।

बेंगलुरु के मामले में, आधे से कुछ ज़्यादा सार्वजनिक शौचालय उपयोग योग्य नहीं हैं। यहां तक कि, कई शहरों में बंद शौचालयों की घटनाएं भी असामान्य नहीं हैं। इसके अलावा, शहरों में सार्वजनिक स्थान लगातार बहिष्कृत होते जा रहे हैं। प्रतिदिन औसतन 10 से 12 घंटे काम करने के साथ, शहरों में आराम करने की जगहों या छायादार जगहों की कमी के कारण गिग वर्कर्स की चरम मौसम संबंधी घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

मौसम की मार का महिला गिग वर्कर्स पर असमान रूप से प्रभाव पड़ता है। प्रजा फाउंडेशन (2024) के मुताबिक, मुंबई में प्रति 1,820 महिलाओं पर केवल एक सार्वजनिक शौचालय सीट उपलब्ध है। यह स्वच्छ भारत मिशन द्वारा अनुशंसित प्रति 100-200 महिलाओं पर एक सार्वजनिक शौचालय सीट के मानक की तुलना में बेहद कम है। औसतन 8 से 10 घंटे प्रतिदिन काम करने वाली महिलाओं के लिए, बुनियादी सुविधाओं की ऐसी कमी कार्य वातावरण को अमानवीय बना देती है।

इसके अलावा, असुरक्षित परिवहन सुविधाएं और खराब रोशनी वाली सड़कें महिला श्रमिकों की कमजोरियों को और बढ़ा देती हैं। गिग वर्कर्स में विषम लिंग अनुपात के कारण, ये मुद्दे अक्सर उचित नीतिगत ध्यान आकर्षित करने में विफल रहते हैं।

जलवायु संकट को एक गंभीर दीर्घकालिक खतरे के रूप में स्वीकार करने की तत्काल जरूरत है, जिसके लिए कुछ मूलभूत परिवर्तनों के साथ-साथ लक्षित हस्तक्षेपों की भी आवश्यकता है। एक अनुकूल वातावरण और संसाधन उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, ताकि नगरीय सरकारें गिग वर्कर्स की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप बुनियादी सेवाओं के प्रावधान में सुधार कर सकें।

नगरीय सरकारों को योजनाओं और परियोजनाओं को तैयार करने के लिए गिग वर्कर्स के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। छायादार विश्राम क्षेत्रों या विशिष्ट वितरण मार्गों पर पेयजल और स्वच्छ शौचालय सुविधाओं की व्यवस्था के रूप में लक्षित हस्तक्षेप, गिग वर्कर्स के लिए चरम मौसम की घटनाओं से निपटने में सहायक होंगे। ऐसे हस्तक्षेपों को महिला श्रमिकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कर लिंग-संतुलित होना चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह परामर्शी श्रमिक संगठनों, सामुदायिक समूहों और आरडब्ल्यूए की भागीदारी के साथ जलवायु योजनाएँ तैयार करने के लिए बॉटम-अप दृष्टिकोण के दायरे को विस्तृत करती है।

आंकड़ों की कमी : अंत में, गिग वर्कर्स की भलाई सुनिश्चित करने के लिए किसी भी अच्छी नीति के लिए उनकी संख्या के आंकड़ों की आवश्यकता होती है, जो स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 गिग वर्कर्स के आंकड़ों के डिजिटलीकरण की वकालत करती है और असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 2021 में ई-श्रम पोर्टल भी शुरू किया गया था। हालांकि, राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में सरकारी पोर्टल तो हैं, लेकिन गिग वर्कर्स की पंजीकृत संख्या का सार्वजनिक रूप से सुलभ डेटा उपलब्ध नहीं है। इसलिए, साक्ष्य-आधारित जलवायु कार्य योजनाओं के लिए आवश्यक डेटा प्रबंधन प्रक्रियाओं को मजबूत करना आवश्यक है।

सपा मुखिया अखिलेश यादव यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्तमान समय में बाबा बागेश्वर धाम की लोकप्रियता चरम सीमा पर है। बाबा बागेश्वर के लाखों भक्त तथा प्रशंसक हैं, वे जहां भी कथा सुनाने जाते हैं वहां लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है।

मृत्युंजय दीक्षित

कथावाचक की आड़ में सनातन पर हमला

इटावा के कथावाचक कांड को राजनीतिक रंग देकर उसमें स्वयं फंसते नजर आ रहे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर धाम आचार्य धीरेंद्र शास्त्री पर ही हमला बोल दिया और उन पर कथा करने के लिए अंडर द टेबल 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगाकर नया विवाद उत्पन्न करने का असफल प्रयास किया है।

सपा मुखिया जब इटावा की घटना पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने में सफल नहीं हुए तब उन्होंने हिंदू राष्ट्र का नारा देने वाले धीरेंद्र शास्त्री जी पर बयान देकर सनसनी मचाने का प्रयास किया। वास्तव में अखिलेश यादव धीरेन्द्र शास्त्री जी की आड़ में अपनी पीडीए राजनीति को हवा देने का प्रयास कर रहे हैं।

सपा मुखिया अखिलेश यादव यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्तमान समय में बाबा बागेश्वर धाम की लोकप्रियता चरम सीमा पर है। बाबा बागेश्वर के लाखों भक्त तथा प्रशंसक हैं, वे जहां भी कथा सुनाने जाते हैं वहां लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। उनके ऊपर सपा मुखिया ने सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत आरोप लगाए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव घोर जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं और टीवी चैनलों पर अपने प्रवक्ताओं से बहस करवा रहे हैं कि क्या कथा कहना केवल एक जाति का ही अधिकार है?

जब वह इस बहस में पिछड़ गए और फंसने लगे तब बाबा बागेश्वर पर हमलावर हो गये। बाबा बागेश्वर ने अखिलेश के आरोपों का उत्तर देते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि अगर दक्षिणा नहीं लेंगे तो कैंसर अस्पताल कैसे बनेगा? उसमें गरीबों का निःशुल्क उपचार कैसे होगा? बाबा बागेश्वर धाम गरीब कन्याओं का विवाह कैसे संपन्न करवाएगा? बाबा बागेश्वर यदि हनुमानजी का आशीर्वाद लेकर लोगों की समस्या का समाधान करते हैं तो इससे लोगों को परेशानी क्यों हो रही है?

ज्ञातव्य है कि बाबा बागेश्वर सोशल मीडिया पर भी एक सेलेब्रिटी की तरह हैं। उनके फेसबुक पर साढ़े 8 करोड़ सोशल मीडिया एक्स पर दो लाख तथा इंस्टाग्राम पर भी दो लाख से अधिक फालोअर्स हैं जबकि करोड़ों लोग उनके यूटयूब चैनल को नियमित रूप से देखते हैं। अपनी कथा व उपदेशों के माध्यम से वह जनमानस को हिन्दू एकता और राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं यही कारण है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव अन्य स्वार्थी नेता उनसे उन पर सामूहिक हमले करते हैं। विगत वर्ष जब बाबा बागेश्वर कथा करने के लिए बिहार गये थे तब वहां के विरोधी दलों के नेताओं ने उनको जेल मे डालने की बात तक कही थी।

बाबा बागेश्वर जी से उन सभी राजनैतिक दलों व नेताओं को समस्या उत्पन्न हो रही है जो जातिवाद व मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम जातिवाद को कैंसर के समकक्ष बताते हैं और हिंदू समाज को एक बनाए रखने के लिए काम करते हैं। हिन्दू एकता के लिए की गई उनकी पहली पदयात्रा बहुत सफल व लोकप्रिय रही थी, अब वह एक बार फिर नई दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा पर निकलने वाले हैं।

सच्चाई यह है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव का बाबा पर यह ताजा हमला उनकी हिंदू संत समाज व सनातन विरोधी मानसिकता को ही दर्शाता है। जो लोग अयोध्या, मथुरा व काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के प्रबल विरोधी रहे हों, जिन लोगों ने अयोध्या में निहत्थे कारसेवकों का नरसंहार किया हो, जिन्होंने कुम्भ का उपहास किया हो वो एक हिन्दू राष्ट्र की बात करने वाले युवा संत का विरोध ही करेंगे। जब महाराष्ट्र के पालघर में संतों को मुस्लिम भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला था तब सपा मुखिया मौन हो गए थे।

सपा मुखिया ने केवल बाबा पर हमला नहीं किया है अपितु सभी कथावाचकों और संतों सहित सनातन धर्म व उसकी एकता पर किया है। सपा मुखिया को स्पष्ट रूप से रामायण, महाभारत, भागवत कथा, आरती, मंदिर, गौशालाओं, गीता आदि सभी से नफरत है। सपा मुखिया को हर उस अच्छी चीज से नफरत है जिससे हिन्दू समाज का गौरव बढ़ता है। सपा के लोग प्रायः रामचरित मानस आदि ग्रंथों का अपमान करने से नहीं चूकते कभी फाड़ते हैं कभी जलाते हैं। सपा मुखिया गौशालाओं से बदबू आती है जैसी बातें कहकर भगवान श्रीकृष्ण व समस्त यदुवंशी समाज का अपमान कर चुके हैं।

सपा मुखिया ने पहले कथावाचक घटना को राजनैतिक रंग देकर फिर बाबा बागेश्वर पर हमला करके एक बहुत ही निम्न राजनैतिक चाल चली है। उत्तर प्रदेश और बिहार ही नहीं वरन पूरे देश को यह समझना होगा। यह समय जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठकर स्वार्थी राजनेताओं को पूरी तरह से धूल चटाने का समय आ गया है। फ्रं

2016 में, उज्जैन कुंभ मेले में एक महीने से ज़्यादा समय तक 75 मिलियन लोग आए थे, जबकि 2028 के कुंभ में 50 मिलियन विदेशी पर्यटकों सहित 450 मिलियन लोगों के शामिल होने का अनुमान है, जो इतिहास का सबसे बड़ा कुंभ होगा। अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं, तो यह प्रयागराज कुंभ द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को पार कर जाएगा। यह भव्य समागम क्षिप्रा या क्षिप्रा नदी के किनारे होगा। इस नदी को हिंदू गंगा की तरह ही पवित्र मानते हैं।

सीपी राजेंद्रन

कैसे सफल होगा 2028 का उज्जैन महाकुंभ!

क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के प्राचीन शहर उज्जैन से होकर बहती है, जो कुंभ मेले के चार स्थलों में से एक है। जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है, तब हर 12 साल में यहां सिंहस्थ कुंभ आयोजित होता है। इसमें लाखों लोग आते हैं। संयोग से, क्षिप्रा, जो इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है, अत्यधिक दोहन और बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रही है।

क्षिप्रा नदी, जिसे क्षिप्रा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश की एक नदी है। ये नदी धार जिले के उत्तर में विंध्य रेंज में काकरी बरडी पहाड़ियों से निकलती है। ये मालवा पठार के उत्तर में बहती है।

ये नदी मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश-राजस्थान सीमा के पास चंबल नदी में मिलती है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। 190 किमी की कुल लंबाई के साथ, क्षिप्रा नदी लगभग 5,000 वर्ग किमी क्षेत्र में जल निकासी करती है।

इसकी प्रमुख सहायक नदियों में उज्जैन के पास खान नदी और महिदपुर के पास गंभीर नदी शामिल हैं। कई महत्वपूर्ण शहर और कस्बे जैसे उज्जैन, धार, देवास, महिदपुर, बड़नगर, आलोट, सांवेर, महू और खाचरोद अपनी पानी की जरूरतों के लिए क्षिप्रा पर निर्भर हैं।

कुंभ मेले और अन्य विशेष अवसरों जैसे आयोजनों के दौरान क्षिप्रा नदी में निरंतर प्रवाह बनाए रखना जल संसाधन प्रबंधकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके अतिरिक्त, नदी को सिंचाई, घरेलू उपयोग, औद्योगिक आपूर्ति और मनोरंजन सहित अन्य प्रतिस्पर्धी मांगों को भी पूरा करना होगा।

ऐतिहासिक रूप से, क्षिप्रा नदी 1970 के दशक के अंत तक बारहमासी थी। हालांकि, समय के साथ, यह एक रुक-रुक कर बहने वाली व्यवस्था में बदल गई है, जो संभवतः जलवायु परिवर्तन और मानवजनित गतिविधियों के संयुक्त प्रभावों के कारण है।

क्षेत्र में पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्षिप्रा नदी अत्यधिक दोहन और बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। यहां मुख्य मुद्दों और संभावित चिंताओं का विवरण दिया गया है। नदी कई उद्देश्यों को पूरा करती है। इससे पीने का पानी, औद्योगिक जरूरतें और सिंचाई, इसके किनारों पर कृषि प्रमुख भूमि उपयोग खास है।

तीन छोटे बांध साहिबखेड़ी, काजीखेड़ी और एक अनाम 3,703 वर्ग किमी के सिंचित क्षेत्र के लिए पानी

की जरूरतें पूरी करते हैं। इन बांधों पर इलाके की कृषि निर्भरता है। घटती बारहमासी प्रकृति एक और चुनौती पेश करती है।

क्षिप्रा नदी अब साल में 5-6 महीने सूखी रहती है, जो गंभीर जल संकट का संकेत देती है। यह निम्नलिखित कारणों से हो सकता है। जैसे- सिंचाई और अन्य उपयोगों के लिए अत्यधिक जल निकासी, कम वर्षा या भूजल पुनर्भरण, वनों की कटाई और प्रवाह को प्रभावित करने वाले भूमि-उपयोग परिवर्तन।

हालांकि साहिबखेड़ी बांध 984 वर्ग किमी को कवर करता है। वहीं काजीखेड़ी डैम 1,366 वर्ग किमी क्षेत्र में सिंचाई में मदद करते हैं। लेकिन ये बहाव को भी कम कर सकते हैं। इससे नदी सूख सकती है और बांधों के कारण तलछट फंस सकती है। इससे नदी की पारिस्थितिकी प्रभावित हो सकती है। संभावित परिणाम यह है कि प्रवाह में कमी से पेयजल आपूर्ति प्रभावित होती है। खासकर उज्जैन जैसे शहरों में और जलीय जीवन और नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होता है। और, सूखे महीनों के दौरान पानी की कमी के कारण नदी के सूखने पर किसानों की भूजल पर अत्यधिक निर्भरता होती है।

नर्मदा लिंक परियोजना लंबे समय तक टिकाऊ नहीं- भारत की पहली उच्च-बजट वाली, बिजली से चलने वाली नदी जोड़ने वाली परियोजना, जो नर्मदा नदी से पानी को क्षिप्रा नदी में पंप करती है। इस परियोजना ने 2016 में महाकुंभ में डुबकी लगाने में मदद की। 432 करोड़ रुपये की इस परियोजना ने उज्जैन में लगभग सूख चुकी क्षिप्रा नदी को पुनर्जीवित किया।

इस पहल के तहत, नर्मदा नदी के पानी को बिजली के पंपों का उपयोग करके 350 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया और फिर 50 किलोमीटर दूर क्षिप्रा के उद्गम स्थल की ओर मोड़ दिया गया। इस परियोजना में 1,000 किलोवाट और 9,000 किलोवाट की क्षमता वाले दो पंपिंग स्टेशन स्थापित करना शामिल था।

अगला कुंभ मेला उज्जैन में क्षिप्रा के तट पर अप्रैल और मई 2028 के बीच होने की उम्मीद है। हाल ही में संपन्न प्रयाग महाकुंभ (फरवरी 2025) को लेकर उत्साह ने आगामी आयोजन के लिए उम्मीदों को पहले ही बढ़ा दिया है। इससे तीर्थयात्रियों को पवित्र अनुष्ठान स्नान में भाग लेने का एक और अवसर मिला है।

हालांकि, उत्सव और प्रत्याशा के पीछे, 2016 में उज्जैन में आयोजित कुंभ मेले से उपजी चिंता की धाराएं भी हैं। नर्मदा नदी के पानी को तब क्षिप्रा में मोड़ना पड़ा था, ताकि उसका प्रवाह बना रहे। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सके कि श्रद्धालु नदी के कम होते जल से निराश न हों।

नर्मदा-क्षिप्रा को जोड़ने की परियोजना एक गलत प्राथमिकता को दर्शाती है। ये सूखती हुई शिप्रा को शुद्ध करने और पुनर्जीवित करने के वास्तविक प्रयासों के बजाय कृत्रिम समाधानों को बढ़ावा देती है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत क्षिप्रा नदी के क्षरण पर रिपोर्ट पर्यावरण संबंधी चिंताओं और प्रशासनिक निगरानी तथा प्राकृतिक साधनों द्वारा नदी पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने की तत्काल आवश्यकता के बारे में मुखर है।

रिपोर्ट में नदी बेसिन के भीतर प्रदूषण और खराब होते भूजल प्रवाह पर प्रकाश डाला गया है। प्रदूषण का मुख्य कारण नदी के आसपास के प्रमुख शहरी केंद्रों के सीवरेज नेटवर्क की कमियाँ और नदी में अनुपचारित सीवरेज डाला जाना है।

यह स्थिति अनियंत्रित औद्योगिक गतिविधियों से और भी बदतर हो जाती है जो जल प्रदूषण में योगदान करती हैं। रिपोर्ट में नदी प्रणाली की दीर्घकालिक स्थिरता और नदी के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया गया है।

आगे की चुनौतियां: भारत वर्तमान में अपने सबसे खराब जल संकट का सामना कर रहा है। ये जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के कारण भी है। ग्लेशियर खतरनाक दर से पीछे हट रहे हैं, भूजल स्तर गिर रहा है और गंगा और यमुना जैसी नदियां अभूतपूर्व गति से बर्बाद हो रही हैं। वहीं बढ़ता तापमान एक प्रमुख कारक है।

साथ ही अस्थिर मानवीय प्रथाओं ने संकट को और बढ़ा दिया है। सिंचाई, घरेलू उपयोग और उद्योग के लिए अनियंत्रित भूजल निष्कर्षण ने प्राकृतिक जल चक्रों को बाधित कर दिया है। इससे असंतुलन पैदा हो रहा है, जिसकी कभी उम्मीद नहीं थी। अनियंत्रित प्रथाओं ने भारत की नदियों को एक भयावह स्थिति में धकेल दिया है, जिसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

क्षिप्रा नदी बेसिन में लगभग हर 4 से 5 साल में एक बार सूखे की स्थिति का अनुभव होता है। इसी को लेकर पूरे क्षेत्र को सूखा-प्रवण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्षों में, नदी ने अपना बारहमासी स्वभाव खो दिया है, जो सालाना 5 से 6 महीने तक सूखी रहती है।

क्षेत्र के प्रमुख जलभृत मुख्य रूप से बेसाल्टिक चट्टान संरचनाओं से बने हैं। दक्षिणी देवास को छोड़कर, जहां विंध्य बलुआ पत्थर और आर्कियन ग्रेनाइट पाए जाते हैं। बेसिन के ऊपरी इलाकों में जलभृत की पैदावार उल्लेखनीय रूप से अधिक है। हालांकि, भूजल का अत्यधिक दोहन एक गंभीर मुद्दा बन गया है। खासकर इंदौर और उज्जैन जिलों में, जहां शुद्ध भूजल ड्राफ्ट उपलब्ध आपूर्ति से अधिक है।

गौर करें तो नदी के उद्गम क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय शुष्क और आर्द्र जलवायु होती है, जबकि शेष क्षेत्र अर्ध-शुष्क होते हैं। बेसिन की औसत वार्षिक वर्षा 931 मिमी है। इंदौर के पास ऊपरी इलाकों में भूजल की उच्च क्षमता है, लेकिन बेसिन का अधिकांश हिस्सा कृषि पर आधारित है। यहां वन क्षेत्र न्यूनतम है, जो भूजल उपयोग पर महत्वपूर्ण मानव जनित प्रभाव को दर्शाता है।

मॉनसून से पहले और बाद के भूजल स्तर के विश्लेषण से पूरे क्षिप्रा बेसिन में गिरावट की प्रवृत्ति का पता चलता है। इसके अतिरिक्त, पिछले दो दशकों में औसत वार्षिक वर्षा और नदी अपवाह दोनों में काफी कमी आई है। क्षिप्रा जैसी मॉनसून-पोषित नदियों के लिए, मॉनसून के बाद के मौसम में नदी के प्रवाह को बनाए रखने के लिए इष्टतम भूजल स्तर बनाए रखना महत्वपूर्ण है। मॉनसून के दौरान, जब नदी का जल स्तर आमतौर पर भूजल तालिका से अधिक होता है, तो नदी चैनल से पानी भूजल को रिचार्ज करता है।

इसके विपरीत, मॉनसून के बाद के मौसम में, जब नदी का स्तर भूजल तालिका से नीचे चला जाता है, तो भूजल नदी को फिर से भर देता है, जिससे निरंतर प्रवाह सुनिश्चित होता है। अधिकतर नदी घाटियों में, अत्यधिक दो हन के कारण भूजल स्तर आमतौर पर नदी तल से नीचे रहता है। इस समस्या से निपटने के लिए, प्राकृतिक वनस्पति और वृक्ष आवरण को बढ़ाने के लिए भूमि उपयोग और भूमि आवरण में बदलावों को विनियमित किया जाना चाहिए।

वन क्षेत्रों में घने वृक्षारोपण का विस्तार भूजल संसाधनों को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकता है, साथ ही भूजल उपयोग के वैज्ञानिक प्रबंधन में भी मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त, पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण सीधे भूजल के अत्यधिक दोहन की भरपाई कर सकता है।

स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, नदी संरक्षण कोष की स्थापना करना और विशेषज्ञ मार्गदर्शन के साथ समुदाय के नेतृत्व वाली भूजल पुनर्भरण पहलों को लागू करना आवश्यक है। वैज्ञानिक विशेषज्ञता द्वारा समर्थित स्थानीय समुदाय की भागीदारी इन महत्वपूर्ण जल प्रणालियों को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

डॉ. आशीष वशिष्ठ

अपनी पहचान जाहिर करने में कैसी शर्म !

असल में, मुजफ्फरनगर जिले के बघरा गांव में योग साधना आश्रम के संचालक और सनातन धर्म के प्रचारक स्वामी यशवीर महाराज पिछले कुछ वर्षों से कांवड़ मार्ग पर दुकानों और ढाबों पर नेम प्लेट लगाने की मांग करते रहे हैं। उनका कहना है कि कांवड़ मार्ग पर कुछ लोग हिंदू देवी-देवताओं के नाम पर ढाबे और दुकानें चलाकर शिव भक्तों को धोखा दे रहे हैं। पहचान छुपाकर धोखा देने वाले कई मामले सामने आने के बाद पिछले साल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों ने आदेश जारी किए कि कांवड़-यात्रा के मार्ग के ढाबे, होटल, रेस्तरां, दुकानदार, खोमचेवाले स्पष्ट नाम पट्टिका लगाएंगे।

भगवान शंकर के प्रिय माह सावन की शुरूआत 11 जुलाई से है। सावन की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। कांवड़ यात्रा में शिवभक्त नंगे पांव हाथ में कांवड़ लेकर लंबी दूरी तय करके शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग में जाते हैं और पवित्र नदियों के जल से उनका अभिषेक करते हैं।

उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर कांवड़ यात्रा निकालने की परंपरा है। कांवड़ यात्रा का विराट रूप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखता है। हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकलने वाले कांवड़ यात्री इस मार्ग से निकलते हैं। इस मार्ग में भगवान शिव के कई बड़े प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर हैं। यहां पर श्रद्धालु भगवान का जलाभिषेक करते हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ से लेकर गाजियाबाद, हापड़ तक के शिव मंदिरों में इस मार्ग से गंगाजल लेकर भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर तनाव बढ़ गया है।

असल में, मुजफ्फरनगर जिले के बघरा गांव में योग साधना आश्रम के संचालक और सनातन धर्म के प्रचारक स्वामी यशवीर महाराज पिछले कुछ वर्षों से कांवड़ मार्ग पर दुकानों और ढाबों पर नेम प्लेट लगाने की मांग करते रहे हैं। उनका कहना है कि कांवड़ मार्ग पर कुछ लोग हिंदू देवी-देवताओं के नाम पर ढाबे और दुकानें चलाकर शिव भक्तों को धोखा दे रहे हैं। पहचान छुपाकर धोखा देने वाले कई मामले सामने आने के बाद पिछले साल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों ने आदेश जारी किए कि कांवड़-यात्रा के मार्ग के ढाबे, होटल, रेस्तरां, दुकानदार, खोमचेवाले स्पष्ट नाम पट्टिका लगाएंगे। सरकार का मंतव्य है कि कांवड़ियों की आस्था और श्रद्धा खंडित न हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश इस पर रोक लगा दी थी। हालांकि, इस साल भी उप्र और उत्तराखंड की सरकारों ने पिछले साल की भांति आदेश जारी किए हैं।

ताजा प्रकरण यह है कि, स्वामी यशवीर महाराज और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता कांवड़ मार्ग स्थित दिल्ली-दून हाईवे स्थित पंडित वैष्णो ढाबा पर पहुंचे। वास्तव में, ढाबा मुस्लिम का था, लेकिन बोर्ड पर लिखा था-'पंडित का शुद्ध वैष्णो ढाबा।' यानी पहचान छिपाने का अपराध किया गया था। पंडित वैष्णो ढाबे को सनव्वर नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति चलाता है। इस ढाबे में उसका बेटा आदिल और जुबैर समेत दो अन्य लोग भी काम करते हैं।

कहा जा रहा है कि यशवीर महाराज और अन्य ने ढाबे के मालिक और कर्मचारियों की धार्मिक पहचान जांचने के लिए पैंट उतरवाई। विवाद यहीं

से भड़का। आग में घी डालते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने पहचान वाले मामले को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ने का काम किया। हसन ने कहा कि, 'मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आम नागरिकों को अधिकार है कि वह किसी दुकानदार की पैंट उतरवाकर चेक कर सकते हैं? क्या पहलगाम में आतंकियों ने पैंट नहीं उतरवाई थी? ऐसा करने वाले पहलगाम के आतंकवादियों में क्या अंतर रह गया?

उस ढाबे पर यह घटना हुई अथवा नहीं, पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन प्रकरण को 'सांप्रदायिक मोड़' दे दिया गया। पहलगाम एक सुनियोजित आतंकी कृत्य था। इन दोनों घटनाओं की तुलना करना न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि यह समाज में धार्मिक आधार पर तनाव पैदा करने का प्रयास भी है।

और जहां तक बात पहचान छुपाने या धोखा देने की है तो यह धंधा लंबे समय से चल रहा है। जुलाई, 2021 में गाजियाबाद में दो ऐसे मुसलमान दुकानदारों का पता चला था, जो हिंदू नाम से दुकान चला रहे थे। इनमें एक दुकान पुरानी सब्जी मंडी में है, जिसका नाम है 'न्यू अग्रवाल पनीर भंडार।' इस दुकान का मालिक है मंजूर अली। दूसरी दुकान 'लालाजी पनीर भंडार' के नाम से है। इसका मालिक ताहिर हुसैन है। इन दोनों का कहना था कि हिंदू नाम रखने से ग्राहक कम पूछताछ करते हैं और धंधा अच्छा चलता है। यानी ये धंधे के लिए हिंदुओं के साथ धोखा कर रहे थे। इनकी पोल तब खुली जब कुछ लोगों को पता चला कि इनका जीएसटी नंबर इनके असली नाम से है। स्थानीय दुकानदारों ने इनका विरोध किया तो इन लोगों ने अपनी दुकानों के नाम बदल लिए हैं।

पिछले साल कांवड़ यात्रा के समय जब नेम प्लेट लगाने के आदेश जारी हुए थे, तो खूब हंगामा मचा था। उस समय सोशल मीडिया से लेकर अखबारों और समाचार चैनलों तक में इस बात की बड़ी चर्चा थी कि कैसे एक आदेश के चलते रातों रात मुजफ्फरनगर का 'संगम शुद्ध शाकाहारी होटल' बन गया 'सलीम ढाबा।' 'मां भवानी जूस कार्नर' का नाम हो गया 'फहीम जूस केंद्र।' 'टी प्वाइंट' का नाम हो गया 'अहमद टी स्टाल।' ऐसे ही 'नीलम स्वीट्स' का मालिक निकला मोहम्मद फजल अहमद। 'अनमोल कोल्ड ड्रिंक्स' का मालिक है मोहम्मद कमर आलम। खतौली के 'चीतल ग्रैंड' के बाहर एक बोर्ड लग गया है, जिस पर लिखा गया है- शारिक राणा डायरेक्टर। सहारनपुर में चल रहे 'जनता वैष्णो ढाबा' का मालिक है मोहम्मद अनस सिद्दीकी। मुजफ्फरनगर के बझेड़ी गांव निवासी वसीम अहमद ने पिछले साल पहचान जाहिर होने के बाद अपना 'गणपति' ढाबा बेच दिया।

एक रिपोर्ट के अनुसार देहरादून-नैनीताल राजमार्ग पर 20 से अधिक ढाबे ऐसे हैं, जो हिन्दू देवी-देवताओं के नाम पर हैं, लेकिन इन्हें चलाने वाले मुसलमान हैं। हरिद्वार नजीबाबाद रोड पर चिडियापुर और समीरपुर गंग नहर रोड पर भी ऐसे हिंदू नामधारी ढाबे हैं, जिनके मालिक मुसलमान हैं। मेरठ, गजरौला, गढ़मुक्तेश्वर, मुंडा पांडे हाईवे पर भी दर्जनों ऐसे ढाबे चल रहे हैं, जिनके मालिक मुसलमान हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, धोखा देने के लिए ये लोग होटल के अंदर हिंदू देवी-देवताओं के चित्र भी रखते हैं, ताकि हिंदू यात्रियों को लगे कि वे किसी हिंदू होटल में ही खाना खा रहे हैं। लेकिन जब कोई ग्राहक ऑनलाइन पैसा देता है, तब पता चलता है मालिक मुसलमान है। इन ढाबों और होटलों में काम करने वाले लोगों के नाम राजू, विक्की, गुड्डू, सोनू जैसे होते हैं। ये लोग तिलक भी लगाते हैं और कलावा भी बांधते हैं। यह धोखा नहीं तो क्या है? मुजफ्फरनगर के पंडित वैष्णो ढाबे पर काम करने वाले तजमुल ने खुद को गोपाल बताया था। हरिद्वार में गुप्ता चाट भंडार में स्कैनर से पेमेंट गुलफाम नाम के अकाउंट में जाने का मामला बीते दिनों प्रकाश में आया है।

अहम सवाल यह है कि पहचान छुपाकर व्यापार करने के पीछे कोई मजबूरी है या षडयंत्र? मुस्लिम व्यक्ति को अपने नाम से दुकान या ढाबा खोलने में क्या दिक्कत है? अपने-अपने धर्म के हिसाब से नाम लिखकर लोग दुकान खोलेंगे या व्यापार करेंगे तो ग्राहक अपनी मर्ज़ी से दुकान पर जाएगा और जिसे जहां से जो खरीदना होगा, वो वहां से ख़रीदेगा। लेकिन पहचान छुपाकर व्यापार या कोई अन्य कार्य करना कानून और नैतिक तौर पर गलत और अपराध है। ऐसी घटनाएं और प्रकरण प्रकाश में आने के बाद संदेह और अविश्वास का माहौल बनता है। जो सामाजिक, राजनीतिक और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर दिक्कतें पैदा करता है।

बात जब खाने पीने की हो तो मामला गंभीर और संवेदनशील हो जाता है। खानपान के पीछे व्यक्तिगत रुचि, संस्कार, धर्म-कर्म और आस्था की पृष्ठभूमि और भूमिका होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शासन-प्रशासन के नेम प्लेट के आदेश से किसी की भावनाएं आहत नहीं होतीं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 में स्पष्ट प्रावधान है कि खानपान के दुकानदारों को अपना फूड लाइसेंस ऐसी जगह लगाना होगा, जहां आसानी से उसे देखा जा सके।

वैसे भी ये मसला हिंदू-मुस्लिम, धार्मिक भेदभाव या किसी की आजीविका की बजाय सीधे तौर भावनाओं और ग्राहक के अधिकार से जुड़ा है। जो करोड़ों की संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, उन सबको रास्ते में भोजन कैसा मिले? कैसा भोजन वो खाएं? ये उनकी स्वतंत्रता है। जब मुसलमान हलाल प्रमाणपत्र देखकर ही कोई सामान खरीदता है, तब हिंदू भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता है!

हिंदू संगठनों का मानना है कि मंदिर में सिर्फ हिंदू कर्मचारी होने चाहिए, क्योंकि ये भगवान का घर है। इस मामले ने मंदिर की पवित्रता और कर्मचारी नियुक्ति पर बहस छेड़ दी है।

श्रवण शु ल

तिरुपति से शनि शिंगणापुर तक 'मुस्लिम घुसपैठ'

महाराष्ट्र के अहिल्या नगर (पुराना नाम-अहमदनगर) जिले में शनि शिंगणापुर मंदिर ने शुक्रवार (13 जून 2025) को 167 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, जिनमें 114 मुस्लिम थे। मंदिर में कुल 114 मुस्लिम काम कर रहे थे और वो सभी इस कार्रवाई में निकाल दिए गए। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि ये लोग अनुशासन नहीं मान रहे थे और कई महीनों से काम पर नहीं आ रहे थे।

ये फैसला तब हुआ जब हिंदू संगठन 14 जून 2025 को बड़ा प्रदर्शन करने वाले थे। इसकी वजह एक वीडियो था - जिसमें मुस्लिम कारीगर मंदिर के पवित्र चबूतरे पर काम कर रहे थे।

इस पूरे मामले के बाद सवाल उठते हैं कि आखिर हिंदू मंदिर में 114 मुस्लिम कर्मचारी थे ही क्यों? बतौर हिंदू मेरा मत साफ है कि हिंदू मंदिरों में सिर्फ हिंदू कर्मचारी होने चाहिए। इस लेख में यही बात समझाने की कोशिश की गई है।

शनि शिंगणापुर में क्या हुआ?

शनि शिंगणापुर का मंदिर भगवान शनि का है। ये मंदिर अनोखा है क्योंकि यहाँ कोई दीवार या छत नहीं है, सिर्फ एक काला पत्थर है, जो शनिदेव का प्रतीक है। रोज हजारों लोग दर्शन करने आते हैं, और खास मौकों जैसे अमावस्या पर लाखों लोग पहुँचते हैं। गाँव में घरों के दरवाजे भी नहीं हैं, क्योंकि लोग मानते हैं कि शनिदेव उनकी रक्षा करते हैं।

हाल ही में मंदिर ट्रस्ट ने 167 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। इनमें 114 मुस्लिम थे, जो खेती, कचरा प्रबंधन, और शिक्षा जैसे काम करते थे। ट्रस्ट का कहना है कि ये लोग पाँच महीने से बिना बताए गायब थे और काम में लापरवाही कर रहे थे। लेकिन फैसला 8 और 13 जून 2025 को हुआ, ठीक उस वक्त जब हिंदू संगठन 14 जून को प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे।

बीजेपी के आध्यात्मिक मोर्चे के प्रमुख आचार्य तुषार भोसले ने इसे हिंदुओं की जीत बताया। उन्होंने कहा, ÷हमने मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने के लिए आंदोलन किया। मंदिर प्रशासन को झुकना पड़ा। मैं सभी शनि भक्तों और हिंदू समाज को बधाई देता हूँ।÷ उनका मानना था कि मुस्लिम कर्मचारियों की मौजूदगी मंदिर की पवित्रता को नुकसान पहुँचाती है।

शनि शिंगणापुर मंदिर से जुड़े विवाद की शुरुआत एक वीडियो से हुई, जिसमें मुस्लिम कारीगार शनि शिंगणापुर के पवित्र चबूतरे पर काम कर रहे थे। मंदिर का ये हिस्सा बहुत पवित्र है, और हिंदू भक्तों को लगा कि ऐसा काम सिर्फ हिंदुओं को करना चाहिए।

हिंदू मंदिर में गैर-हिंदू कर्मचारी क्यों नहीं होने चाहिए

एक हिंदू भक्त के लिए मंदिर सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि भगवान का घर है। यहाँ की हर चीज - पूजा, रीति-रिवाज, और माहौल को पवित्र रखना जरूरी है। हिंदू धर्म में मंदिर की पवित्रता बहुत मायने रखती है। अगर कोई गैर-हिंदू जो हिंदू नियमों को न माने, मंदिर के काम में शामिल हो, तो ये भक्तों की आस्था को ठेस पहुँचा सकता है।

उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में कई नियम हैं - जैसे शाकाहारी भोजन, पूजा से पहले स्नान और खास मंत्रों का जाप। मंदिर में काम करने वाले को इनका पालन करना चाहिए। अगर कोई गैर-हिंदू इन नियमों को न माने, तो मंदिर का सात्विक माहौल खराब हो सकता है। शनि शिंगणापुर में जब एक मुस्लिम कर्मचारी मंदिर के चबूतरे पर चढ़ा, तो भक्तों को लगा कि ये गलत है। ऐसे पवित्र काम सिर्फ हिंदुओं को करने चाहिए, जो इन नियमों को समझते हों।

ये सवाल उठता है कि 114 मुस्लिम कर्मचारी वहाँ थे ही क्यों? मंदिर के काम, चाहे वो पूजा हो, रखरखाव हो या कोई और काम.. ये कम हिंदुओं को ही मिलना चाहिए। हिंदू भक्तों का मानना है कि मंदिर की सेवा वही करे, जो उसकी पवित्रता को समझे। गैर-हिंदू कर्मचारी,

सही फैसले का आखिर विरोध किसलिए!

महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट ने 114 मुस्लिमों समेत 167 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है जिससे विवाद खड़ा हो गया है। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार यह फैसला प्रशासनिक है और कर्मचारियों द्वारा नियमों के उल्लंघन के कारण लिया गया। हालांकि यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब हिंदू संगठन मंदिरों में मुस्लिम कर्मचारियों की उपस्थिति का विरोध कर रहे हैं।

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में स्थित शनि शिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट ने 114 मुस्लिमों समेत 167 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इतने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की बर्खास्तगी के कारण मंदिर ट्रस्ट सवालों के घेरे में आ गया है।

मंदिर ट्रस्ट का यह फैसला ऐसे समय सामने आया जब मंदिरों में मुस्लिम कर्मचारियों के होने का विरोध किया जा रहा है। हालांकि शनि शिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह से प्रशासनिक है। मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों के अनुसार, यह एक प्रशासिक निर्णय है। निकाले गए कर्मचारी लगातार कुछ नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। अनुशासनहीनता के कारण उन्हें बरखास्त किया गया है।

बता दें कि कई हिंदू संगठन मंदिर परिसर में मुस्लिम कर्मचारियों की उपस्थित पर आपत्ति दर्ज कर चुके हैं। उनका कहना है कि शनि भगवान के मंदिर में गैर-हिंदू कर्मचारियों का क्या काम है? यही नहीं, हिंदू संगठनों ने मंदिर ट्रस्ट को चेतावनी दी थी अगर उन्होंने मुस्लिमों को मंदिर से बाहर नहीं निकाला तो बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे।

बता दें कि शनि शिंगणापुर मंदिर काफी पुराना है। यहां भगवान शनिदेव की मूर्ति खुले आसमान के नीचे रखी है। वहीं, शनि शिंगणापुर देश का अकेला ऐसा गांव है, जहां किसी भी घर में दरवाजा नहीं है। हाल के समय में मुस्लिम कर्मचारियों के कारण यह मंदिर विवादों में आ गया है।

भले ही वो अच्छे इंसान हों, हिंदू रीति-रिवाजों को पूरी तरह नहीं समझ सकते। इसलिए मंदिरों में सिर्फ हिंदू कर्मचारी रखना सही है।

कानून और परंपरा भी यही कहते हैं

इस सोच को कानूनी समर्थन भी मिला है। जनवरी 2024 में मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि तमिलनाडु के हिंदू मंदिरों में गैर-हिंदू लोग 'कोडिमरम' (झंडे वाले खंभे) से आगे नहीं जा सकते। कोर्ट ने कहा कि मंदिर हिंदुओं की पूजा के लिए हैं, और गैर-हिंदुओं का पवित्र जगहों पर जाना मंदिर की पवित्रता को नुकसान पहुँचा सकता है। ये फैसला साफ बताता है कि मंदिरों में हिंदू परंपराओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

अगर गैर-हिंदुओं को मंदिर के पवित्र हिस्सों में जाने की इजाजत नहीं, तो उन्हें मंदिर के काम में शामिल करने का क्या मतलब? शनि शिंगणापुर में मुस्लिम कर्मचारी भले ही पूजा न करते हों, लेकिन मंदिर की दीवार या शिखर पर काम करना भी पवित्र काम है। ऐसे काम हिंदुओं को ही करने चाहिए, ताकि कोई विवाद न हो।

ऐसे कई मंदिर हैं, जहाँ गैर-हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। जैसे सबरीमाला मंदिर में सख्त नियम हैं। तेलंगाना स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर में ऐसी ही घटना के बाद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केवल हिंदू कर्मचारियों की नियुक्ति का आदेश दिया था। शनि शिंगणापुर में भावना है कि मंदिर का हर काम हिंदू धर्म के हिसाब से हो।

मंदिरों के मैनेजमेंट से खुद को दूर रखें सरकारें

ये विवाद ये भी दिखाता है कि सरकार मंदिरों को अपने कंट्रोल में रखती है। महाराष्ट्र में कई मंदिर ट्रस्ट को सरकारी अधिकारी चलाते हैं। हिंदू संगठन इसका विरोध करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मंदिरों का पैसा धर्म और संस्कृति के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, न कि सरकारी खर्चों में। 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने शनि शिंगणापुर मंदिर को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी, लेकिन हिंदू संगठनों ने इसे रुकवाया।

इस बार आचार्य तुषार भोसले और उनके संगठन ने मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने की माँग की। कुछ लोग इसे राजनीति कह सकते हैं, लेकिन हिंदू भक्तों के लिए ये मंदिर की पवित्रता की लड़ाई है। जैसे अयोध्या के राम मंदिर में हिंदू अधिकारियों को अहम जगह दी गई, वैसे ही शनि शिंगणापुर में भी हिंदू कर्मचारी होने चाहिए।

फैसले पर सवाल उठाने वालों को जवाब

शनि शिंगणापुर देवस्थान के सीईओ गोरक्षनाथ दरंदाले ने बताया कि करीब 2400 कर्मचारी यहाँ काम करते हैं। इनमें से कई काम पर नहीं आते। ऐसे लोगों की सैलरी भी रोकी गई है। इसके बाद ही ये कार्रवाई की गई। कईयों की सैलरी 5-5 माह से रुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि 114 मुस्लिम कर्मचारियों को निकालना भेदभाव है। ट्रस्टी अप्पासाहेब शेटे का कहना है कि धर्म की वजह से नहीं, बल्कि खराब काम और गैर-हाजिरी की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन 167 में से 114 मुस्लिम कर्मचारियों का निकाला जाना और फैसले की टाइमिंग सवाल उठाती है।

हालाँकि हिंदू भक्तों का मानना है कि मंदिर का काम कोई साधारण नौकरी नहीं। ये सेवा है, जो आस्था और परंपरा से जुड़ी है। भले ही कर्मचारी पूजा न करते हों, लेकिन मंदिर के हर काम में पवित्रता का ध्यान रखना जरूरी है। अगर गैर-हिंदू कर्मचारी मंदिर की दीवार पेंट करें या शिखर पर चढ़ें, तो ये भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुँचाता है। इसलिए मंदिर में सिर्फ हिंदू कर्मचारी रखना ही सही है।

मद्रास हाई कोर्ट का फैसला भी यही कहता है कि मंदिरों में हिंदू परंपराओं को प्राथमिकता मिले। गैर-हिंदुओं को दूसरी नौकरियों में मौका मिल सकता है, लेकिन मंदिरों में हिंदुओं को ही काम करना चाहिए।

पहले भी बदले हैं नियम

शनि शिंगणापुर मंदिर पहले भी विवादों में रहा है। 2016 में महिलाओं को मंदिर के गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं थी। तब कार्यकर्ता तृप्ति देसाई ने आंदोलन किया, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि कोई कानून महिलाओं को मंदिर में जाने से नहीं रोक सकता। इस फैसले के बाद 400 साल पुराना नियम टूटा। ये दिखाता है कि समय के साथ मंदिरों के नियम बदल रहे हैं।

हिंदू भक्तों का मानना है कि मंदिरों में गैर-हिंदू कर्मचारियों को रखने का कोई मतलब नहीं। अगर मंदिर हिंदुओं का है, तो उसका हर काम हिंदुओं के हाथ में होना चाहिए। इससे न विवाद होगा, न किसी की भावनाएँ आहत होंगी।

मद्रास हाई कोर्ट का फैसला हर जगह हो लागू

शनि शिंगणापुर का ये मामला साफ करता है कि हिंदू मंदिरों में सिर्फ हिंदू कर्मचारी होने चाहिए। इसके लिए साफ नियम बनने चाहिए। पूजा, रखरखाव या कोई भी काम, जो मंदिर से जुड़ा हो, हिंदुओं को ही करना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट का फैसला इसकी शुरुआत है, लेकिन इसे हर मंदिर में लागू करना होगा।

सरकार को मंदिरों से अपना कंट्रोल हटाना चाहिए। मंदिरों को हिंदू समाज चलाए, ताकि उनकी पवित्रता बनी रहे। हिंदू संगठनों को भी अपनी बात रखते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि कोई तनाव न बढ़े।

एक हिंदू भक्त के लिए मंदिर की पवित्रता सबसे ऊपर है। इसलिए शनि शिंगणापुर में 114 मुस्लिम कर्मचारियों का होना गलत था। ऐसे में मंदिर का हर काम हिंदुओं के हाथ में होना चाहिए, ताकि भक्तों की आस्था बनी रहे। ये फैसला सही दिशा में है और इसे हर हिंदू मंदिर में लागू करना चाहिए। फ्रं

मनोवैज्ञानिक रूप से, रंग हमारे भीतर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं पैदा करते हैं। लाल रंग ऊर्जा, साहस या जल्दी के संकेत देता है। नीला रंग शांति और भरोसे का प्रतीक है। हरा रंग प्रकृति और उपचार से जुड़ा है। पीला खुशी और स्पष्टता लाता है, जबकि बैंगनी सृजनात्मकता और रहस्य की अनुभूति कराता है। ये संबंध केवल फैशन तक सीमित नहीं हैं; ये ब्रांडिंग, इंटीरियर डिज़ाइन और चिकित्सा केंद्रों तक को प्रभावित करते हैं।

डॉ. तनु जैन,
(सिविल सेवक रक्षा मंत्रालय आध्यात्मिक वक्ता)

हम जो रंग पहनते हैं, वही जिंदगी जीते हैं

दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में आईपी कॉलेज के एक फेस्ट के दौरान, मैं कॉलेज के दिनों में एक ऐसी स्थिति से गुज़री, जिसे उस वक़्त मामूली समझा जा सकता था–क्या पहनूं? मैं अलमारी के सामने खड़ी हो गई, एक के बाद एक कपड़े निकालती, बिस्तर पर फेंकती, और यह सोचती कि ऐसा क्या पहनूं जिससे मैं आत्मविश्वासी लगूं, सहज महसूस करूं। पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। न कोई रंग, न कोई कपड़ा 'मैं' जैसा लगा। देर हो गई, मन चिढ़ गया, और मैं सोचने लगी–कपड़े जैसी छोटी सी चीज़ भी ज़िंदगी को इतना प्रभावित कैसे कर सकती है? पर यह सिर्फ़ फैशन की बात नहीं थी; यह मेरी पहचान, मेरी ऊर्जा और मेरे दुनिया के सामने अपने को प्रस्तुत करने के तरीके से जुड़ी बात थी। उसी क्षण एक मौन प्रश्न ने मेरे मन में जन्म लिया- क्या रंग सच में हमारी ज़िंदगी में फर्क डालते हैं?

कुछ समय बाद, मैंने रंग चिकित्सा (Colour Therapy) पर एक किताब पढ़ी। यह विषय मुझे आकर्षित करने लगा। जो शुरुआत में सिर्फ़ जिज्ञासा थी, वह धीरे-धीरे एक गहरी खोज में बदल गई। मैंने और पढ़ना शुरू किया–पुस्तकें, लेख, आध्यात्मिक ग्रंथ–और धीरे-धीरे एक अद्भुत दुनिया खुलने लगी, जहाँ रंग केवल देखने की चीज़ नहीं थे, बल्कि हमारी भावनाओं, संस्कृति, अध्यात्म और ईश्वर से जुड़ाव के प्रतीक थे। रंग सिर्फ़ दृश्य नहीं हैं, वे हमारे अनुभवों को आकार देते हैं।

मनोवैज्ञानिक रूप से, रंग हमारे भीतर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं पैदा करते हैं। लाल रंग ऊर्जा, साहस या जल्दी के संकेत देता है। नीला रंग शांति और भरोसे का प्रतीक है। हरा रंग प्रकृति और उपचार से जुड़ा है। पीला खुशी और स्पष्टता लाता है, जबकि बैंगनी सृजनात्मकता और रहस्य की अनुभूति कराता है। ये संबंध केवल फैशन तक सीमित नहीं हैं; ये ब्रांडिंग, इंटीरियर डिज़ाइन और चिकित्सा केंद्रों तक को प्रभावित करते हैं। जैविक दृष्टिकोण से, हमारी आंखें तीन प्रकार की कोन कोशिकाओं से लाल, हरे और नीले प्रकाश को पहचानती हैं, और उससे हम रंगों को देख पाते हैं। परंतु जो लोग रंगों के अंधत्व (Colour Blindness) से ग्रसित हैं, उनकी दुनिया ही अलग नज़र आती है।

संस्कृतिक रूप से, रंगों का अर्थ देश और समाज के अनुसार बदलता है। पश्चिमी देशों में सफेद रंग को विवाह और पवित्रता से जोड़ा जाता है, जबकि भारत और अन्य पूर्वी संस्कृतियों में सफेद रंग शोक और विदाई का प्रतीक है। आध्यात्मिक रूप से, रंगों का अर्थ और भी गहराई लिए होता है। ईसाई चित्रकला में नीला रंग ईश्वरीय कृपा और वर्जिन मैरी की पोशाक का प्रतीक है। लाल रंग आत्मा और प्रेम का है। हिंदू धर्म में रंग और भी जीवंत हैं–कृष्ण का नीला रंग अनंत आकाश और समुद्र का प्रतीक है; केसरिया त्याग और शुद्धता का; और सोना दिव्यता का। बौद्ध धर्म में रंग मानसिक अवस्थाओं और आत्मज्ञान के चरणों से जुड़े होते हैं।

सबसे अधिक आकर्षक बात मुझे यह लगी कि हिंदू परंपरा में सप्ताह के सातों दिनों को एक रंग, एक ग्रह और एक देवता से जोड़ा गया है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि वैदिक ज्योतिष, ग्रंथों और परंपराओं पर आधारित है।

रविवार : सूर्य देव का दिन, लाल या नारंगी रंग–ऊर्जा और बल का प्रतीक

सोमवार : चंद्रमा और शिव जी का दिन–श्वेत या हल्का नीला रंग–शांति और शुद्धता

मंगलवार : हनुमान जी और मंगल ग्रह–लाल या गुलाबी–शक्ति और साहस

बुधवार : बुध ग्रह और श्रीकृष्ण–हरा रंग–संतुलन और विकास

गुरुवार : बृहस्पति और विष्णु भगवान–पीला रंग–बुद्धि और आशीर्वाद

शुक्रवार : लक्ष्मी जी–सफेद या हल्का नीला–सौंदर्य और समृद्धि

शनिवार : शनि देव–काला या गहरा नीला–अनुशासन और सुरक्षा

मैंने धीरे-धीरे इस पद्धति को अपनाना शुरू किया। अब मेरी सुबहें उलझनभरी नहीं रहीं। बुधवार हो तो हरा पहनना, शुक्रवार हो तो हल्का नीला। ये रंग चुनना सिर्फ़ सौंदर्य की बात नहीं रह गई थी, बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास बन गया था। समय के साथ मेरा वार्डरोब भी साधारण हो गया, मन भी स्थिर और सधा हुआ लगने लगा। मैं अब कम कपड़े खरीदती थी, सोच-समझकर चुनती थी, और हर दिन से एक नया जुड़ाव महसूस करती थी।

जो बात कभी कॉलेज की उलझन थी, वही अब मेरी ज़िंदगी का संतुलन और उद्देश्य बन गई।

रंग अब मेरे लिए सिर्फ़ देखने की चीज़ नहीं थे–वे मेरी अनुभूति, मेरी अभिव्यक्ति और ईश्वर से जुड़ने का माध्यम बन गए।

वे अब मेरे लिए एक तरह का कंपास बन गए–केवल पहनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए।

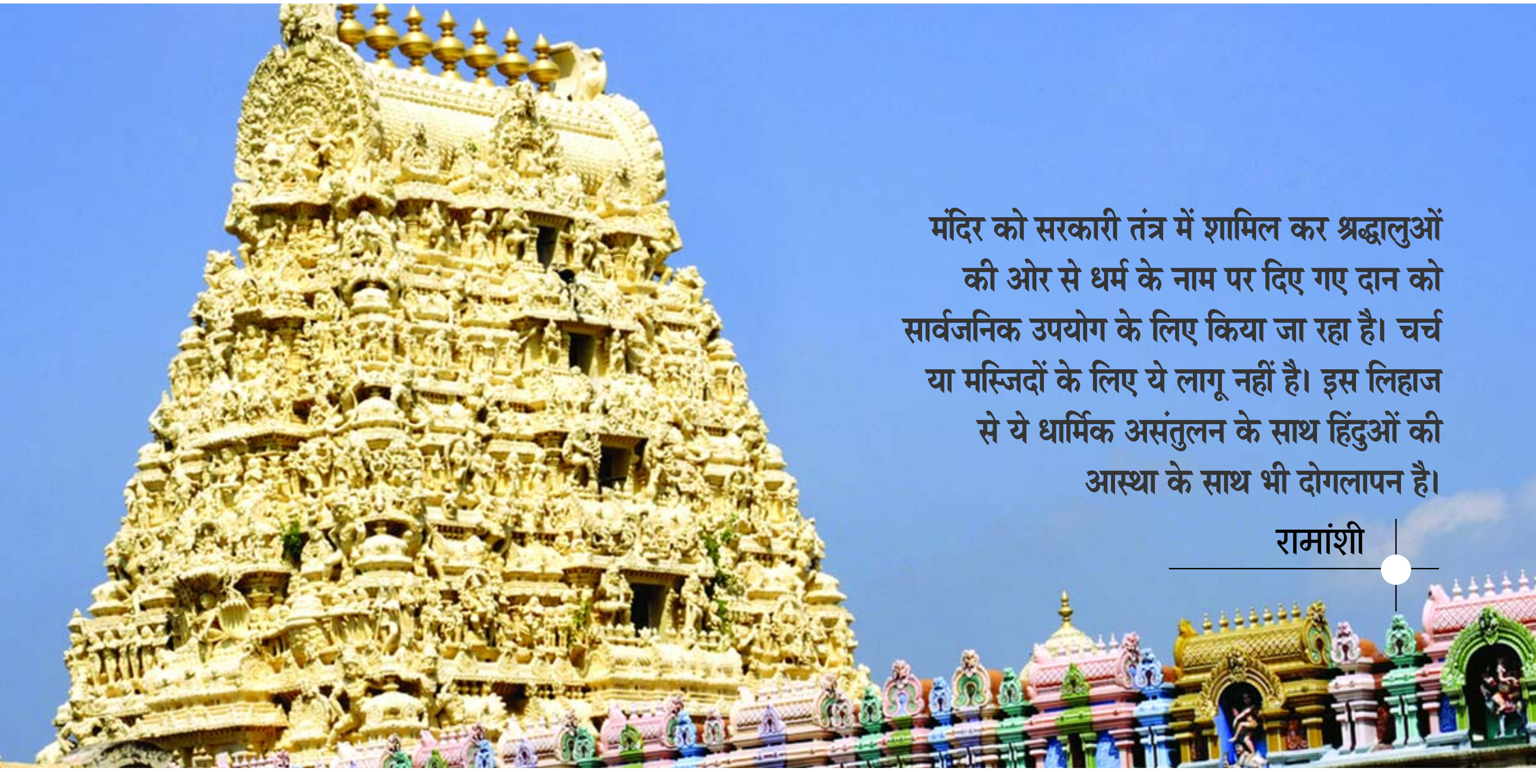

मंदिर को सरकारी तंत्र में शामिल कर श्रद्धालुओं की ओर से धर्म के नाम पर दिए गए दान को सार्वजनिक उपयोग के लिए किया जा रहा है। चर्च या मस्जिदों के लिए ये लागू नहीं है। इस लिहाज से ये धार्मिक असंतुलन के साथ हिंदुओं की आस्था के साथ भी दोगलापन है।

रामांशी

‘विकास’ के नाम पर मंदिर की कमाई पर लूट

तमिलनाडु सरकार के मंदिरों के पैसों से कॉलेज खोलने की योजना पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईडीएमके) के महासचिव एडप्पादी के. पलानिस्वामी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स (Hindu Religious & Charitable Endowments) विभाग की ओर से मंदिरों में आने वाले दान को कॉलेजों के निर्माण में खर्च कर किया जा रहा है।

एआईडीएमके महासचिव ने इसे धार्मिक निधि का दुरुपयोग बताते हुए सवाल किया कि क्या सरकार के पास खुद खर्च के लिए फंड नहीं हैं। इस मामले पर द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके) सरकार का कहना है कि ये कदम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और जनता के हित में उपयोग किया जा रहा है।

इस मामले पर बहस नई नहीं है। मंदिरों के प्रशासन पर सरकार का नियंत्रण और निधि का उपयोग एक लंबे समय से बहस का विषय रहा है। ये मामला नवंबर 2021 से शुरू हुआ था। डीएमके सरकार ने मंदिरों में चढ़ने वाले पैसे और सोना समेत हर तरह के दान की निधि से 4 कला और विज्ञान कॉलेज खोलने की योजना बनाई थी। विपक्षी दलों में तब भी विरोध किया था।

हालाँकि इस पर मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहकर अंतरिम रोक लगा दी थी कि मंदिर का धन श्रद्धालुओं की ओर से धार्मिक आस्था के कारण दिया जाता है। साथ ही इसका उपयोग मंदिर के ट्रस्टियों की अनुमति के बिना भी नहीं किया जा सकता।

इसके बाद ताजा विवाद जुलाई 2025 में फिर सामने आया। एआईएडीएमके ने फिर आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार मंदिरों के चढ़ावे को कालेजों के निर्माण में कर रही है। ये विवाद तब और सुलग गया जब अप्रैल 2025 को करुणानिधि स्मारक पर श्रीविल्लिपुत्तूर मंदिर के गोपुरम (मंदिर का ऊपरी हिस्सा) की छवि बनाई गई। बीजेपी ने इसे हिंदू आस्था पर हमला कहा।

तमिलनाडु भाजपा के उपाध्यक्ष नारायणन तिरुपति ने सोशल मीडिया पर स्मारक की तस्वीर साझा की और लिखा कि यह अहंकार और मूर्खता की पराकाष्ठा है। हालाँकि इस पर भी डीएमके ने सफाई दी कि ये धार्मिक बयान के बजाय तमिलनाडु के राज्य प्रतीक का हिस्सा है। इस प्रतीक को 1949 में तत्कालीन सीएम ओमांदुर रामास्वामी रेड्डी के कार्यकाल में अपनाया गया था।

देश के सिर्फ 10 राज्यों में सरकार के नियंत्रण में 1,10,000 हिंदू मंदिर हैं। तमिलनाडु में मंदिरों के 4.78 लाख एकड़ भूमि, 36,425 मंदिर और 56 मठ सरकार के नियंत्रण में हैं। हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स विभाग 35,000 से अधिक मंदिरों का रखरखाव करता है। इन मंदिरों से मिलने वाली निधि का उपयोग अस्पतालों, अनाथालयों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सामाजिक संस्थाओं के निर्माण और रखरखाव में किया जाता है।

इसी साल अप्रैल में रिपोर्ट्स सामने आई कि सरकार की ओर से तमिलनाडु के 21 मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए सोने को पिघलाकर 24 कैरेट की छड़ों के रूप में बदलकर इन्हें बैंक में जमा कर दिया गया है। इसके जरिए निवेश से मिले ब्याज का उपयोग विकास कार्यों के लिए किया जाता है। इस निवेश से सरकार को हर साल लगभग 17.81 करोड़ रुपए का ब्याज मिल रहा है।

हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स ने विधानसभा में पेश एक नोट में कहा कि सरकार की इस योजना से मंदिरों को आर्थिक लाभ मिला है। इस विभाग को मिले फायदों को इस तरह से भी जाना जा सकता है कि जब जुलाई 2025 में एआईएडीएमके महासचिव ने मंदिर निधि के दुरुपयोग पर सवाल उठाए तो डीएमके के मंत्री पीके शेखरबाबू ने उन पर निशाना तो साधा ही पर साथ में ये भी बताया कि विभाग ने मंदिर धन का उपयोग करके 25 स्कूल, 9 कॉलेज और 1 पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित किया जा चुका है। इसके अलावा 19 अस्पताल भी स्थापित किए गए।

मंदिर और शिक्षण संस्थानों का इतिहास

अगर इतिहास की बात करें तो भारत में मंदिर केवल पूजा के लिहाज से ही अहम नहीं थे बल्कि शिक्षा और चिकित्सा का केंद्र हुआ करते थे। मंदिरों में ही गुरुकुल और शोध केंद्रों की भी स्थापना थी। बदलते समय के साथ मंदिरों का सरकारी नियंत्रण में रखरखाव किया जाने लगा और उनकी संपत्ति, भूमि और आय पर भी आधिपत्य कर दिया। इसके साथ ही मंदिरों को सिर्फ धार्मिक प्रयोजनों तक के लिए सीमित कर दिया गया।

अगर सरकारी तंत्र की बात की जाए तो इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि सिर्फ मंदिर ही सरकार के अधीन रखे गए हैं। किसी मस्जिद या चर्च को या उनकी संपत्ति को सरकार के न तो अधीन रखा गया और न ही सरकार का उन पर किसी भी तरह का नियंत्रण है। मंदिर को ही सरकारी तंत्र में शामिल कर श्रद्धालुओं की ओर से धर्म के नाम पर दिए गए दान को सार्वजनिक उपयोग के लिए किया जा रहा है। इस लिहाज से ये धार्मिक असंतुलन के साथ हिंदुओं की आस्था के साथ भी दोगलापन है।

इस तरह के नीतिगत पक्षपात के लिए न केवल आवाज उठाना सही है बल्कि मंदिर के साथ सभी धार्मिक संस्थाओं के साथ एक जैसा व्यवहार सुनिश्चित करना भी जरूरी है। फ्रं

झारखण्ड और छतीसगढ़ की सीमाओं के जंगलों में वर्षा ऋतु के आरंभ में वनों में, जंगलों में उगने वाले अनेक मशरूमों में से एक ऐसा ही मशरूम है- पुटू, जो वर्षा ऋतु में जंगलों में उगने वाले कई प्रकार के अन्य मशरूमों से अनेक रूपों में भिन्न है। खाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यह मशरूम अपने अनोखे स्वाद और पोषक तत्वों के लिए लोकप्रिय हैं।

रजनीश कपूर

झारखण्ड का अनोखा जंगली मशरूम पुटू

झारखण्ड और छतीसगढ़ की सीमावर्ती जिलों के वनों, जंगलों में वर्षा ऋतु के प्रारम्भिक काल में स्वतः ही उगने, निकलने वाली पुटू नामक मशरूम के इस वर्ष कमोत्पति अर्थात कम उपज के कारण लोग इसके प्राकृतिक, असली और बेहतरीन स्वाद से वंचित होकर रह गए हैं। लोग मजबूरी में घरों में मशरूम की खेती से उत्पादित पुटू के व्यंजनों में उस जानी- पहचानी, सदियों से आनुवंशिकी में बसी पुटू के स्मरणीय स्वाद को ढूँढने को विवश हैं।

विगत वर्षों में पुटू को खोज व उसे पाकर जमीन से खोदकर निकाल, संग्रहण करने के लिए लोग प्रातः काल ब्रह्म बेला में ही घर से पैदल अथवा अपने वाहनों से दूर- दूर के जंगलों तक निकल पड़ते थे, और सुबह से शाम तक इस कार्य में तल्लीन रहते थे, लेकिन इस वर्ष पुटू अर्थात रूगड़ा की अनुपलब्धता के कारण जंगलों में इसको ढूंढने वाले लोग भी विगत वर्षों की अपेक्षा कम ही दिखाई देते हैं, बल्कि दिखलाई ही नहीं दे रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि वर्षा ऋतु में जंगलों में कई प्रकार के मशरूम उगते हैं। इन मशरूमों का उपयोग खाने में किया जाता है और ये अपने अनोखे स्वाद और महत्वपूर्ण खनिज व पोषक तत्वों के लिए जाने जाते हैं।

झारखण्ड और छतीसगढ़ की सीमाओं के जंगलों में वर्षा ऋतु के आरंभ में वनों में, जंगलों में उगने वाले अनेक मशरूमों में से एक ऐसा ही मशरूम है- पुटू, जो वर्षा ऋतु में जंगलों में उगने वाले कई प्रकार के अन्य मशरूमों से अनेक रूपों में भिन्न है। खाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यह मशरूम अपने अनोखे स्वाद और पोषक तत्वों के लिए लोकप्रिय हैं। झारखण्ड के जंगलों में पाया जाने वाला यह वन्य मशरूम पुटू अथवा रुगड़ा एक मौसमी मशरूम है, जो वर्षा ऋतु में उगता है।

रुगड़ा या पुटू का उपयोग स्थानीय व्यंजनों में किया जाता है और यह अपने अनोखे स्वाद और पोषक तत्वों के लिए जाना जाता है। यह चावल और रोटी के साथ ही विभिन्न प्रकार के स्थानीय व्यंजनों के साथ चाव से खाया जाता है। पुटू को स्थानीय भाषा में रुगड़ा भी कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे गुच्छी, मोरछी भी कहा जाता है। क्षेत्रीय भाषा में इसके विभिन्न नाम हैं। झारखण्ड प्रदेश और देश के अन्य क्षेत्रों में वन्य मशरूमों के नाम विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अलग-अलग हैं।

नागपुरी, संथाली, हो, मुंडारी, कुड़ुख आदि झारखण्ड के स्थानीय भाषाओं में पुटू मशरूम के कई नाम हैं। इसे सादरी व नागपुरी में पुटू, रुगड़ा, गुच्छी या गुच्ची, संथाली, मुंडारी व हो भाषा में गुच्ची या गुचुम, कुड़ुख में गुच्ची या खुखुरू (खुखरी) कहा जाता है। पुटू के इन नामों में भिन्नता हो सकती है और विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग नामों का उपयोग किया जा सकता है।

झारखण्ड के जंगलों में पाया जाने वाला यह वन्य मशरूम पुटू अथवा रुगड़ा एक मौसमी मशरूम है जो वर्षा ऋतु में उगता है। वर्षा ऋतु के शुरुआती काल में जंगलों में स्वतः ही उगने वाली इस मशरूम की अनेक विशेषताएं हैं। पुटू का आकार गोलाकार या अंडाकार होता है। इसका रंग सफेद या हल्का भूरा होता है। यह उगने के अंतिम दौर में काला रंग का भी हो जाता है। पुट

का स्वाद अनोखा और स्वादिष्ट होता है। यह एक मौसमी मशरूम है जो वर्षा ऋतु के अतिरक्त अन्य समय में नहीं उगता है। झारखण्ड के आदिवासी- गैर आदिवासी सदान समुदायों में यह मशरूम एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है। इसका उपयोग सब्जी, सूप, और सलाद आदि विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में किया जा सकता है। पुटू का स्वाद अनोखा और स्वादिष्ट होता है, जो इसे स्थानीय व्यंजनों में एक लोकप्रिय घटक बनाता है।

पुटू एक पौष्टिक मशरूम है, जिसमें शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन, पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद फाइबर, विटमिन बी व डी, पोटैशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे महत्वपूर्ण खनिज व पोषक तत्व होते हैं। पुटू में विटामिन और खनिज होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। कुछ अनुसंधानों के अनुसार पुटू में उपलब्ध एंटीऑक्सीडेंट गुण कैंसर से बचाव में मदद करते हैं।

शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं। इन पोषक तत्वों और खनिजों के कारण रुगड़ा एक स्वस्थ और पौष्टिक खाद्य विकल्प हो सकता है। पुटू का स्वाद अनोखा और स्वादिष्ट होता है, जो इसे स्थानीय व्यंजनों में एक लोकप्रिय घटक बनाता है। यह सब्जी व सलाद के रूप में एक स्वादिष्ट और पौष्टिक तथा पेय पदार्थ के रूप में एक आरामदायक और पौष्टिक पेय पदार्थ अर्थात सूप का बेहतर विकल्प हो सकता है।

पुटू अर्थात रूगड़ा के स्वाद के शौकीनों व स्थानीय लोगों के अनुसार इस वर्ष मौसम की अनियमितता, पर्यावरण की परिवर्तनीयता इसके कम उगने का कारण हो सकती है। वर्ष भर समय- समय पर वर्षा होते रहने के कारण क्षेत्र में इस वर्ष गर्मी अपने प्रचंड स्वरूप को कभी दिखला न सकी। सूर्यदेव पृथ्वी को, जंगली धरती को मन भर तपा भी न सके और वर्षा ऋतु की शुरुआत हो गई। वर्षा रानी जमकर बरसने लगी।

घर- आंगन, खेत- खलिहान, तालाब- पोखर, जंगल -पहाड़, नदी-नाले सभी जल से तर बतर हो गए। जब वह बरसी तो लगातार बरसती ही रह गई। वह आज तक भी रूकने का नाम ही नहीं ले रही है। इससे डाड़ व उच्चे जमीन की दलहन, तेलहन, व श्री के नाम से वर्तमान में लोकप्रिय मोटे अनाज की खेती- किसानी भी प्रभावित हो गई। कही- कहीं तो यह कृषि कार्य आज तक रुकी पड़ी है। और खरीफ धान के रोपाई करने का समय भी आ चला है। लेकिन वर्षा रानी के इस अनवरत वर्षण से, प्रकृति के इस चलन से क्षेत्र में, क्षेत्र के जंगलों में तापमान और आर्द्रता की स्थिति में प्राकृतिक बदलाव अवश्यम्भावी था, जो हुआ।

जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जंगलों में तापमान और आर्द्रता की स्थिति में बदलाव जैसे कारणों से पुटू जैसी प्रजातियों की उत्पत्ति प्रभावित हुई। झारखण्ड के गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, रांची आदि जिलों में मानसून की अचानक और तीव्र वर्षा के कारण पुटू मशरूम के उगने के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं बन सका, जिससे इसकी उत्पन्न होने की प्रक्रिया बाधित हुई। फलतः पुटू की उत्पत्ति नहीं हुई अथवा बहुत ही कम हुई। पुटू जैसे मशरूम के उगने के लिए विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि उचित तापमान, आर्द्रता और मिट्टी की स्थिति। पुटू वर्षा ऋतु में उगता है, जब जंगलों में वर्षा होती है और मिट्टी में आर्द्रता बढ़ जाती है। लेकिन वर्षा की तीव्रता और आवृत्ति अधिकाधिक होने से पुटू जैसी मशरूम के उगने की प्रक्रिया प्रभावित हुई।

ग्रीष्म काल में जंगलों में लगने अथवा लगाई जाने वाली आग से वर्षा काल में स्वतः ही उग आने वाली वन्य जन्माओं, बीजों, पौधों, मरुशमोपज संसाधनों के वनाग्नि के भेंट चढ़ जाने के कारण जंगलों में पुटू, रुगडा अथवा अन्यान्य वनोपज सम्बन्धित बीजों, संसाधनों की अनुपलब्धता, अन्य प्रजातियों की अधिकता, जंगल की स्थिति में बदलाव आदि कई अन्य कारण भी पुटू जैसे जंगली मशरूम की उत्पत्ति को प्रभावित करने का कारण बनी।

इसी कारण झारखण्ड, छतीसगढ़ की सीमावर्ती जिलों के वनों में रुगड़ा जैसी प्रजातियों की उत्पत्ति प्रभावित हुई, और लोग इसके चिर- परिचित स्वाद से वंचित हो रहे हैं। राजनीतिकों का कहना है कि आदिवासी हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से प्रस्तावित झारखण्ड में पेसा कानून की राज्य में वास्तविक परिस्थिति तथा अन्य सरकारी कानूनों के कारण जंगलों के उपयोग और प्रबंधन में बदलाव के कारण भी रुगड़ा की उत्पत्ति पर असर पड़ा। वन के प्रति गलत व स्वार्थपरक सोच, जंगलों के उपयोग और प्रबंधन जैसी कारकों का भी रुगड़ा की उत्पत्ति पर सीधा प्रभाव स्पष्ट है। पुटू का आर्थिक महत्व भी है, क्योंकि इसकी बिक्री से स्थानीय लोगों को आय होती है। पुटू की बिक्री से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है।

मशरूम उत्पादन में अव्वल बन सकता है झारखंड

फंक्शनल फूड सेंटर द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट की मानें, तो डायबिटीज के मरीजों के लिए मशरूम आदर्श आहार है। इसमें न फैट होता है, न कोलेस्ट्रॉल। कार्बोहाइड्रेट भी इसमें न के बराबर होता है, जबकि प्रोटीन, विटामिन और खनिज अधिक मात्रा में पाये जाते हैं। यह हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। इसमें प्राकृतिक इंसुलिन है, जो डायबिटीज के रोगियों के लिए वरदान है।

मशरूम में मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट्स हानिकारक रेडिकल्स से बचाते हैं। इसमें एर्गोथायोनीन नामक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में बहुत प्रभावी है। दिल की बीमारी में यह वरदान है, तो कैंसर के रोगियों के लिए यह दैवीय औषधि से कम नहीं है। जापान में किये गये एक शोध के अनुसार, मशरूम के सेवन से प्रॉस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। इधर मशरूम उत्पादन में क्रांति आयी है।

वर्ष 1960 में वैश्विक स्तर पर मशरूम का उत्पादन केवल 1.7 करोड़ टन था, जो वर्तमान में बढ़ कर चार करोड़ टन तक पहुंच गया है। इसका अत्पादन लगातार बढ़ रहा है। पिछले दशक में इसके उत्पादन में 200 गुना से अधिक वृद्धि हुई है और उम्मीद की जा रही है कि 2050 तक इसका उत्पादन 10 करोड़ टन तक पहुंच जायेगा। गुणवत्तापूर्ण मशरूम उत्पादन में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह न केवल गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की समस्या का समाधान करेगा, अपितु ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा।

भारत का वातावरण मशरूम उत्पादन की दृष्टि से बेहद अनुकूल माना जा रहा है। झारखंड की बात करें, तो यहां मशरूम पहले से ही खाद्य शैली का अंग रहा है। झारखंड और अगल-बगल के वन क्षेत्रों में बारिश के दिनों में एक खास प्रकार का जंगली मशरूम मिलता है। इसे स्थानीय भाषा में खुखड़ी कहा जाता है। गुणवत्ता और स्वाद की दृष्टि से खुखड़ी का कोई विकल्प नहीं, लेकिन यह सीमित समय में प्राप्त होता है। झारखंड में यदि मशरूम की व्यावसायिक खेती की जाए, तो यह स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति भी बदल सकता है। हालांकि हाल के दिनों में इस दिशा में थोड़ा काम हुआ है, लेकिन बड़े पैमाने पर व्यापारिक योजना के तहत इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है।

इसके उत्पादन से ग्रामीणों में कुपोषण की समस्या का समाधान तो होगा ही, इसका व्यापार कर लोग बढ़िया आमदनी भी कर सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, फिलहाल झारखंड में सालाना लगभग 50 टन मशरूम का उत्पादन हो रहा है। लेकिन यहां इसके उत्पादन की अपार संभावना है। बिहार की तुलना में झारखंड की जलवायु मशरूम उत्पादन के लिए बेहतर है, लेकिन बिहार देश का प्रथम मशरूम उत्पादक राज्य बन गया है, जबकि झारखंड अभी बहुत पीछे है। इसके लिए यहां बेहतर आधारभूत संरचना की जरूरत है। दूसरी यहां की सबसे बड़ी समस्या चूहा है, जो मशरूम का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। झारखंड के किसान इस दृष्टि से पिछड़ रहे हैं। यदि मशरूम की खेती पर ध्यान दिया जाए, तो झारखंड देश का प्रथम मशरूम उत्पादक राज्य बन सकता है। इसके लिए सरकार को भी इस दिशा में थोड़ा ध्यान देना होगा। फ्रं

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों पर नजर डालें, तो पुरुष चौरानबे प्रतिशत अपराध करते हैं और महिलाएं छह से आठ प्रतिशत, यानी महिला अपराधियों की संख्या बहुत कम है, लेकिन महिलाओं द्वारा किये गये अपराध इसलिए ज्यादा चौंकाते हैं, क्योंकि महिला भी अपराध कर सकती है, इस बात पर विश्वास नहीं होता।

क्षमा शर्मा

अपराध की दुनिया यों लगती है इतनी रोमांचक

इंदौर की सोनम रघुवंशी का मामला चर्चा में है। हर रोज इस मामले में नये रहस्य खुल रहे हैं। हमारी मानसिकता में अपराध की योजनाएं किस तरह से बनती हैं, इसे जानकर हैरत हो रही है। ऐसी-ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि मानवीय संबंधों पर विश्वास न हटे, तो और क्या हो!

एक महिला ने बच्ची गोद ली। वह उसे अपने दम पर पाल रही थी। पढ़ा-लिखा कर वह उसे योग्य बनाना चाहती थी। बच्ची पंद्रह साल की हुई, तो उसके जीवन में एक लड़का आया। मां उससे कहती थी कि पहले पढ़-लिख लो, फिर किसी संबंध में आगे बढ़ना। किशोरी को यह बात बुरी लगी।

उसने मां की हत्या कर दी। दूसरी लड़की को नानी ने किसी लड़के से मिलने पर डांटा, तो उसने उस पर चाकू से इतने वार किये कि नानी ने दम तोड़ दिया। एक दूसरी महिला ने अपने पति को धमकाया कि अगर ज्यादा मुंह खोला, तो राजा रघुवंशी वाला हाल करूंगी। ऐसा नहीं है कि अपराध महिलाएं ही कर रही हैं। पुरुष भी कोई कम नहीं। ऐसी खबरें रोज आती हैं कि लिव इन में रह रही महिला को पुरुष मित्र ने मारा। पत्नी को पहाड़ से धक्का दिया। किसी और से शादी करने के लिए महिला मित्र की सुपारी दी।

यदि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों पर नजर डालें, तो पुरुष चौरानबे प्रतिशत अपराध करते हैं और महिलाएं छह से आठ प्रतिशत, यानी महिला अपराधियों की संख्या बहुत कम है, लेकिन महिलाओं द्वारा किये गये अपराध इसलिए ज्यादा चौंकाते हैं, क्योंकि महिला भी अपराध कर सकती है, इस बात पर विश्वास नहीं होता। यूं बदले वक्त के साथ महिला डॉन भी सामने आने लगी हैं। कुछ दिन पहले एक लड़की को दिल्ली से पकड़ा गया था। उसे जेल भी हुई थी, पर जेल से निकलने के बाद वह फिर से अपराध करने लगी।

हाल ही में ग्रेटर नोएडा से उन्नीस साल की एक लड़की को पकड़ा गया। वह हाइवे पर ट्रकों को पिस्तौल के बल पर लूटती थी। उस घटना के बारे में तो लोगों ने देखा-सुना ही होगा, जहां एक लड़की ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी के सीने पर पिस्तौल तानते हुए कहा था, 'इतनी गोलियां मारूंगी कि कोई पहचान नहीं पायेगा'। अफसोस कि बाद में उस लड़की को कुछ लोग लक्ष्मीबाई कहने लगे।

दरअसल अपराध की दुनिया बड़ी रोमांचक लगती है। इसके पीछे की सोच यह है कि लंबी कानूनी प्रक्रियाओं में पड़ने के मुकाबले क्यों न हाथ के हाथ मामले को निपटाया जाए। इधर एक गोली चलेगी, उधर सब खत्म। हमारे समाज में अपराध को बहुत गौरवान्वित किया जाता है। अमिताभ बच्चन की फिल्मों की कामयाबी और उनकी एंग्री यंगमैन की छवि ने कुछ ऐसा वातावरण बनाया था, जहां न्याय कोई भला आदमी नहीं, कोई अपराधी ही दिलवा सकता है। कोई क्यों अपराधी बनता है, इसके मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारण भी वहां बताये जाते थे।

लेकिन आजकल तो सत्ता और धन बल के नशे में लोग समझते हैं कि एक बार अपराध की दुनिया में जगह बना लें, तो बस पौ बारह है।

पहले यदि कोई पिता अपराधी होता था, तो अपने बेटे को शिक्षा देता था कि वह कभी अपराधी न बने, लेकिन कई साल पहले एक व्यक्ति का इंटरव्यू पढ़ रही थी। उसका कहना था कि उसके पिता ने जीवन में जितने अपराध किये, उसने नहीं किये। इसलिए पिता उससे नाराज होते और कहते थे कि मेरा बेटा कहाना है, तो इस दुनिया में मुझसे ज्यादा नाम कमाना पड़ेगा। इसे पढ़ कर बहुत हैरानी हुई थी, क्योंकि बचपन में सुनी वह कहानी हमेशा याद रही थी कि एक चोर को जब राजा ने फांसी की सजा दी, तो उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गयी। उसने कहा कि वह अपनी मां से कान में कुछ कहना चाहता है। उसने मां के कान काट लिये, फिर कहा कि जब पहले दिन उसने मां को कान में आकर चोरी की बात बतायी थी, यदि वह उसी दिन रोकती, तो वह आगे चोरी न करता।

लेकिन हिंदी फिल्मों, ओटीटी, सोशल मीडिया इन दिनों युवाओं के मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक हैं। अपराध कैसे करें, हथियार कैसे प्राप्त करें, ये सब बातें ऑनलाइन खोजी जा सकती हैं। ऐसे में, नयी पीढ़ी के बच्चों को, जिनमें लड़कियां भी हैं, न्याय करना और बदला लेना बहुत आसान लगता है। वैसे भी कुछ विमर्श ऐसे हैं, जो रात-दिन अन्याय के निराकरण का सही तरीका बदला समझते हैं। अतीत में जिस-जिसने सताया है, उससे बदला लेना चाहते हैं। यह अलग बात है कि बदले की इस सोच के शिकार कई बार निरपराधी भी होते हैं।

जैसे कि राजा रघुवंशी या वह मां, जिसने अनाथ बच्ची को पाला और उसे उज्ज्वल भविष्य देने की कोशिश की। अपराध करते वक्त यह महसूस क्यों नहीं होता कि पकड़े भी जायेंगे? यह क्यों लगता है कि कुछ भी कर लें, बच जायेंगे? वे चित्र भी हम सबने देखे होंगे, जिनमें जब तरह-तरह के अपराधी जेल से बाहर आते हैं, तो विक्ट्री का साइन बनाते हैं। कई किशोर अपराधी तो ऐसे हैं, जो जब जेल जाते हैं, तो धमकी देते हैं कि बाहर आकर देखेंगे। कई मामलों में ऐसा हुआ भी है। इन सब कारणों से भी स्थिति बिगड़ी है।

कोहली की चमक से अलग चमकने वाला कप्तान

अनुपम प्रतिहारी

रजत पाटीदार की स्क्रिप्ट कौन लिखता है? बतौर कप्तान अपने पहले टूर्नामेंट में सबसे महत्वपूर्ण टीमों में से एक, आरसीबी को 18 सालों में अपना पहला आईपीएल खिताब दिलाना एक ऐसी कहानी है जिसे केवल नियति ही लिख सकती थी। 2008 में आईपीएल की शुरुआत से ही, आरसीबी में ट्रॉफ़ी के लिए एक जुनून था, जो ग्लैमर, पॉप और चमक-धमक से लिपटा था। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, अनिल कुंबले, ग्लेन मैक्सवेल, डेल स्टेन, फ़ैफ़ डु प्लेसिस और जोश हेज़लवुड जैसे इसके कुछ सबसे बड़े खिलाड़ियों ने सुनिश्चित किया कि टीम के प्रशंसकों की संख्या लगातार बढ़े।

सीज़न से पहले आरसीबी के लिए खिताब जीतना एक चुनौती थी, जब तक आरसीबी को रजत पाटीदार का नेतृत्व नहीं मिला। 32 वर्षीय पाटीदार मध्य प्रदेश से आने वाले एक मध्य क्रम के बल्लेबाज़ और घरेलू क्रिकेट के पावरहाउस हैं।

शर्मीले और कम बोलने वाले पाटीदार आरसीबी के लिए एक सही पसंद साबित हुए, जिनकी आरसीबी को अपनी चमकदार छवि को बेअसर करने और ट्रॉफ़ी जीतने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ज़रूरत थी।

2024-25 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में मध्य प्रदेश के कप्तान रहे पाटीदार ने अपनी टीम को फ़ाइनल में पहुंचाया था। इस टूर्नामेंट में दिल्ली के खिलाफ सेमीफ़ाइनल में पाटीदार उस समय मैदान में उतरे थे, जब टीम 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 46 रन पर 3 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी।

पाटीदार ने अपनी टीम को धमाकेदार अंदाज़ में जीत दिलाई। उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों पर नाबाद 66 रन बनाए, जिसमें छह छक्के और चार चौके शामिल थे।

इसके बाद आगे आकर नेतृत्व करने की उनकी क्षमता किसी की नज़र से नहीं बची। टूर्नामेंट के दौरान कप्तान के रूप में उनको आरसीबी के मुख्य कोच एंडी फ्लावर और इसके निदेशक मो बोबट ने देखा था।

दोनों इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आईपीएल का सबसे मुश्किल काम, आरसीबी की कप्तानी पाटीदार को सौंपने से पहले विराट कोहली से इस पर चर्चा की।

ये वही पाटीदार थे जो कुछ साल पहले तक मध्य प्रदेश टीम की कप्तानी करने से भी कतरा रहे थे। बतौर कप्तान पाटीदार घरेलू क्रिकेट में तैयार हो गए थे और वह 2025 आईपीएल के लिए तैयार थे।

कोच एंडी फ्लावर की मौजूदगी भी मददगार रही, जिनके साथ उन्होंने मुश्किल वक़्त में धैर्य रखने में महारत हासिल की।

कोच ने कप्तान को आज़ादी दी और इसने पाटीदार को अपने क्रिकेट संबंधी फ़ैसलों के प्रति अधिक आश्वस्त किया। नए कप्तान ने विनम्रता, आत्मविश्वास, रणनीतिक समझ और टीम के हर सदस्य को साथ लेकर चलने की क्षमता दिखाई। उनके इस कैरेक्टर ने टीम को स्पष्ट रूप से बदल दिया।

पाटीदार ने अपने संसाधनों को बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल किया, ख़ासकर अहम मैचों में अपने गेंदबाज़ों सही का इस्तेमाल। पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 190 रनों पर ढेर होने के बाद, अधिकतर जानकारों का मानना था कि यह स्कोर आईपीएल फाइनल में उचित स्कोर से 20 रन कम था।

एक कमज़ोर कप्तान बड़े मैच के दबाव में झुक जाता लेकिन पाटीदार नहीं। पंजाब किंग्स के चतुर कप्तान श्रेयस अय्यर ने बैक ऑफ़ लेंथ गेंदों और धीमी बाउंसरों का जाल बिछाया था, जिसे उनके गेंदबाजों ने प्रभावशाली ढंग से अंज़ाम दिया।

यहां तक कि आरसीबी के करिश्माई बल्लेबाज और शायद आईपीएल के सबसे महान खिलाड़ी विराट कोहली 35 गेंदों पर 43 रनों की अपनी असामान्य रूप से शांत पारी में केवल तीन चौके लगा पाए।

आरसीबी की हर साझेदारी को ख़तरनाक रूप लेने से पहले ही ख़त्म कर दिया गया। साफ़ तौर पर, फ़ाइनल का पहला हाफ़ पंजाब किंग्स के नाम था।

फिर भी, पाटीदार और उनके साथियों ने हार मानने से इनकार कर दिया। जवाब में, पावरप्ले के बाद पंजाब किंग्स एक विकेट पर 52 रन बनाकर आराम से आगे बढ़ रही थी। तब पाटीदार ने अपने टैलेंट का भरपूर इस्तेमाल किया।

फ़ील्डिंग खुलने के बाद कप्तान अपने 'विकेट लेने वाले गेंदबाज़' क्रुणाल पंड्या को लाए। बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर तुरंत एक्शन में आ गए। अपनी बैक ऑफ़ लेंथ फ्लाइटेड डिलीवरी के साथ, उन्होंने प्रभसिमरन सिंह और जॉश इंग्लिस दोनों को बांधे रखा और केवल तीन रन दिए।

यह मैच का निर्णायक पल था क्योंकि विपक्ष के सबसे बड़े बल्लेबाज़ पर घात लगाकर हमला किया गया था। दो ओवर बाद, चतुर आरसीबी कप्तान ने क्रुणाल को वापस बुलाया जिन्होंने इंग्लिस को आउट किया।

इंग्लिस 23 गेंदों पर 39 रन के अपने स्कोर में पहले ही चार छक्के लगा चुके थे और मैच को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे थे। सबसे अनुभवी गेंदबाज़ भुवनेश्वर कुमार को वापस लाया गया। 17वें ओवर में उन्होंने ज़ोरदार गेंदबाज़ी की और उन्होंने नेहाल वढेरा (15) के साथ मार्कस स्टोइनिस (6) को आउट करके दोहरी सफलता हासिल की। यह निर्णायक झटका था क्योंकि पंजाब किंग्स छह रन से हार गई और चमचमाती ट्रॉफ़ी आरसीबी को मिली। टी20 विश्व कप विजेता टीम के कोच रहे फ्लावर ने भी उनकी तारीफ़ की।

उन्होंने कहा, 'आप उनकी उस सहजता को कम नहीं आंक सकते, जो उन्होंने एक बड़ी फ्रेंचाइज़ी के लिए कुछ बड़े खिलाड़ियों की अगुआई करते हुए दिखाई। रजत ने दबाव के बीच अच्छे फ़ैसले लिए। मेरे मन में उनके लिए काफ़ी सम्मान है। जिस तरह से उन्होंने खुद को पेश किया, उस पर मुझे वास्तव में गर्व है।'

मुक़ाबले में जीत सबसे दृढ़ निश्चयी खिलाड़ी की होती है। रजत पाटीदार ने दृढ़ता तो दिखाई ही, साथ ही उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत को टीम के सबसे करिश्माई खिलाड़ी कोहली को समर्पित करते हुए गरिमा भी दिखाई। फ्रं

मील का पत्थर बनेगी नयी खेल नीति

मीर रंजन नेगी

सरकार ने एक और महत्वपूर्ण पहलू को नीति में शामिल किया है और वह है देश में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेलों के आयोजन का प्रयास करना। सरकार के इस कदम से खेलों को देश में खूब उछाल मिलेगा।

भारत को खेलों की महाशक्ति बनाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय खेल नीति (एनएसपी), 2025 को मंजूरी दी है। यह खेल नीति जिन पांच स्तंभों पर आधारित है, वे बेहद महत्वपूर्ण हैं और उन पर बहुत सूक्ष्मता से विचार किया गया है। नयी खेल नीति के जरिये एक तरह से खेलों के महाकुंभ (2036 की ओलिंपिक) की तैयारी का बिगुल फूंका गया है। हमारा देश जब एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में उभर कर आ रहा है, तो अपनी प्रतिष्ठा को और बढ़ाने के लिए ओलिंपिक समेत तमाम अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में अधिक से अधिक पदक लाना बहुत आवश्यक है।

मुझे लगता है कि खेलों में बहुत अच्छा करने के लिए हमें स्कूलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत अधिक खर्च करने की जरूरत है। ओडिशा इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। सबसे जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, तभी आप अच्छे खिलाड़ी तैयार कर पायेंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर कर पायेंगे। हमें प्रतिभा खोज की प्रक्रिया में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज के समय में जो स्पोर्ट्स एकेडमी हैं, वहीं से सारे खिलाड़ी निकलते हैं। तो एकेडमियों की संस्कृति को प्रमोट करने की बहुत जरूरत है, जैसे इन्हें संरक्षण देना, इनकी अच्छी तरह निगरानी करना। इन सबके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। सरकार को खेल बजट बढ़ाने की आवश्यकता है। हालांकि पहले की तुलना में आज खेल बजट कहीं अधिक है। खिलाड़ियों को कई सुविधाएं भी मिल रही हैं। टूर्नामेंट जीतने पर भी पैसे मिल रहे हैं। इन सबके बावजूद खेल बजट में और वृद्धि करनी होगी।

एक और जरूरी बात। देश में बहुत सारे खेल एसोसिएशन हैं, जो खुद को ऑटोनॉमस (स्वायत्त) बॉडी समझते हैं, जबकि पैसा वे सरकार से लेते हैं, जगह सरकार की इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपनी मनमानी चलाते हैं। इन पर सरकार का अंकुश रहना बहुत जरूरी है। नयी राष्ट्रीय खेल नीति के आने से खेलों में पारदर्शिता बढ़ेगी। सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी और कॉरपोरेट-सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी (सीएसआर) के जरिये फंड जुटाने की बात भी कही गयी है।

ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीएसआर के तहत जो फंड खिलाड़ियों पर, खेलों पर खर्च करना है, उनमें किसी तरीके का कोई घालमेल कंपनियां न करें। कई कंपनियां इस फंड में गड़बड़ी करती हैं। ये सारी चीजें बहुत पारदर्शिता लेकर आयेंगी। नीति में स्टार्ट-अप और उद्यमिता को बढ़ाने देने की बात भी सराहनीय है। अपने देश में खेल अब एक ऐसे मुकाम पर आ गया है, जहां पर उसे एक पेशे के रूप में भी लिया जा सकता है। देश में ऐसे बहुत से लोग हैं, जो खेलों में स्टार्ट-अप और उद्यमिता शुरू कर रहे हैं। ऐसा बड़े से लेकर छोटे स्तर तक पर हो रहा है। जब सरकार इस तरह की चीजों को बढ़ावा देगी, तो ऐसे और भी बहुत से लोग आगे आयेंगे। खेलों को लेकर एक बेहतर माहौल तैयार होगा। हालांकि इसके लिए सरकार को लालफीताशाही पर लगाम लगानी होगी।

सरकार ने एक और महत्वपूर्ण पहलू को नीति में शामिल किया है और वह है देश में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेलों के आयोजन का प्रयास करना। सरकार के इस कदम से खेलों को देश में खूब उछाल मिलेगा। जब भी देश में कोई अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन होता है, तो खिलाड़ियों को विश्व स्तर पर कैसे खेलना है, इस तकनीक का पता चलता है। नयी पीढ़ी में खेलों से जुड़ने का उत्साह पैदा होता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए हमारे खिलाड़ियों की तैयारी भी बेहतर होती है, उनके भीतर एक आत्मविश्वास आता है। हॉकी इंडिया लीग जब भारत में शुरू हुई थी, तब उसमें विदेशी खिलाड़ियों ने भी भागीदारी की थी, उन्हीं लीग मैचों ने हमारे लिए ओलिंपिक पदक जीतने का रास्ता तैयार किया था।

नयी नीति में सामाजिक समावेशन पर भी जोर दिया गया है। जब समावेशन होगा, तो सभी वर्गों-क्षेत्रों के लोगों को खेलों में भागीदारी का मौका मिलेगा। यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं। देश में अधिकांश खिलाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों से निकलते हैं

और वे बेहतर करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ कर दिखाने की भूख होती है। उनकी आंखों में एक सपना होता है कि खेल में बेहतर करेंगे, तो उनको अच्छी नौकरी मिल जायेगी और इन्हीं में से कुछ खिलाड़ी जब देश के लिए खेलते हैं, तो उनको जीतने के बाद में ढेर सारे पैसे और अच्छी नौकरी मिलती है। वे देशभर में प्रेरणास्रोत बन जाते हैं और उन्हें देखकर दूसरे लोग भी खेलों से जुड़ते हैं। ऐसी खेल प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की जरूरत है। नयी खेल नीति में यह माद्दा है।

खेलों को शिक्षा से जोड़ने की बात भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब खेल शिक्षा से जुड़ेगा, तो विद्यार्थी न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ व मजबूत बनेंगे। इससे बच्चों का समग्र विकास हो सकेगा, पर इसके लिए जरूरी है कि सरकार की नीति का अच्छी तरह से शिक्षा के साथ समावेशन किया जाए। सरकार को यह नियम सरकारी के साथ-साथ निजी विद्यालयों के लिए भी लागू करना होगा। उन्हीं निजी स्कूलों को खोलने की मान्यता मिलनी चाहिए, जिनके पास खेल के मैदान हों, बेहतर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। खिलाड़ियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी जरूरत है। इसके लिए खेल संस्थाओं, खेल से जुड़े इवेंट आदि में खिलाड़ियों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि हमारा देश आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में ज्यादा से ज्यादा पदक जीते। उसके लिए नयी खेल नीति मील का पत्थर साबित होगी। वर्ष 2047 तक शीर्ष पांच या छह खेल राष्ट्रों में भारत के शामिल होने की राह यहीं से होकर निकलेगी।

इसके लिए सरकार को एक और काम करना होगा। वह है, आलिंपिक में होने वाले अधिक से अधिक खेल और इवेंट में भारत भाग ले। ओलिंपिक में कुल 32 खेल और 329 इवेंट्स होते हैं, जिनमें से भारत केवल 16 खेलों के 69 इवेंट में भाग लेता है। भारत को यदि अपने पदकों की संख्या बढ़ानी है, तो उसे अधिक से अधिक खेल और उसके इवेंट में भाग लेना होगा। इसके लिए सरकार को देश में उन खेलों के प्रमोशन पर भी ध्यान देना होगा, जिनमें भारत शामिल नहीं होता है।

खेलों को जनांदोलन बनाना एक विराट लक्ष्य है, जिसके तहत खेलों में जन भागीदारी और फिटनेस की संस्कृति को बढ़ावा देने तथा स्कूल-कॉलेजों और कार्यस्थलों में फिटनेस सूचकांक शुरू करने की बात कही गयी है।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस राष्ट्रीय खेल नीति (एनएसपी), 2025 को मंजूरी दी है, वह भारत को खेलों में विश्वशक्ति बनाने की एक जरूरी और महत्वाकांक्षी योजना है। केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल महासंघों, खिलाड़ियों, खेल विशेषज्ञों और सार्वजनिक हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार की गयी इस नीति में 2047 तक भारत को खेलों में दुनिया के शीर्ष पांच देशों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2036 के ओलिंपिक खेलों समेत दूसरे वैश्विक खेल आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दूरदर्शी रोडमैप तैयार किया जायेगा।

यह नीति पांच प्रमुख लक्ष्यों पर आधारित है। वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता के तहत जमीनी स्तर से शीर्ष स्तर तक खेल कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खेल का बुनियादी ढांचा विकसित करने, राष्ट्रीय खेल महासंघों की क्षमता और उसका प्रबंधन बढ़ाने तथा ट्रेनिंग, कोचिंग व एथलीट सपोर्ट के लिए विश्वस्तरीय व्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। खेल पर्यटन को बढ़ावा देने, देश में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों का प्रयास करने, इस क्षेत्र में स्टार्ट-अप और उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी, कॉरपोरेट-सामाजिक दायित्व और अभिनव वित्तपोषण पहलों के जरिये निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का भी लक्ष्य है। खेलों के जरिये सामाजिक समावेशन पर भी जोर दिया जाना है।

स्वदेशी और पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने तथा खेलों को एक आकर्षक करियर विकल्प के रूप में स्थापित करने से खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों की दुविधा दूर होगी। खेलों को जनांदोलन बनाना एक विराट लक्ष्य है, जिसके तहत खेलों में जन भागीदारी और फिटनेस की संस्कृति को बढ़ावा देने तथा स्कूल-कॉलेजों और कार्यस्थलों में फिटनेस सूचकांक शुरू करने की बात कही गयी है।

शिक्षा के साथ खेलों को जोड़ने का लक्ष्य भी व्यावहारिक है, जिसमें स्कूली पाठ्यक्रम में खेलों को शामिल करने और खेल, शिक्षा तथा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों और शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देने का उद्देश्य है। राष्ट्रीय खेल नीति, 2025 में एक मजबूत क्रियान्वयन ढांचा भी होगा, जिसमें प्रदर्शन के लिए तय मापदंड और समयसीमा होगी। यह नीति भारत को खेलों में विश्वशक्ति बनाने में तो मदद करेगी ही, फिट, समावेशी और सशक्त नागरिक भी बनायेगी।

संदीप जोशी

जान पर भारी जवानी!

महज़ 42 साल की उम्र में अभिनेत्री शेफ़ाली जरीवाला की अचानक मौत की वजह का अब तक पता नहीं चल सका है। उनकी मौत की जांच में जुटे कुछ पुलिस अधिकारियों ने ये कहा है कि शेफ़ाली एंटी-एजिंग टैबलेट्स समेत कई दवाइयां ले रही थीं। संभवतः ये दवाइयां ख़ाली पेट लेने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया। समाचार एजेंसी ने एक पुलिस अधिकारी के हवाले से ये बताया कि 27 जून की दोपहर शेफ़ाली ने एक इंजेक्शन लिया था, जो संभवतः एंटी-एजिंग इंजेक्शन था।

पुलिस अधिकारी ने कहा, 'उनका ब्लड प्रेशर तेज़ी से गिरा और उन्हें ठिठुरन होने लगी। इसके बाद परिवार वाले उन्हें अस्पताल लेकर गए।' शेफ़ाली जरीवाला को 27 जून की रात अंधेरी के बेलेव्यू मल्टीस्पेशिएलिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। जांच के तहत एक पुलिस टीम फ़ॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ उनके घर गई और कई चीज़ों से सैंपल इकट्ठे किए हैं। इसमें शेफ़ाली की दवाइयां और इंजेक्शन भी शामिल हैं।'

एंटी एजिंग ट्रीटमेंट- कुछ दवाओं या दवा और ऐसे कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से होता है जो बढ़ती उम्र के असर को धीमा करने में मदद करते हैं।

इन सबमें ज़्यादा प्रचलित बोटॉक्स है जो एक ऐसा पावरफुल इंजेक्शन है, जो कि हमारी मांसपेशियों को बहुत ही छोटे हिस्से में रिलैक्स करता है। माथे की लकीरें या आंखों के पास दिखने वाली रेखाएं, नाक के आसपास दिखने वाली रेखाओं को कम करने के लिए बोटॉक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। 20 साल से भी अधिक समय पहले फ़ूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफ़डीए) ने कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं में इसके इस्तेमाल की मंजूरी दे दी थी।

द एस्थेटिक क्लिनिक्स के सीनियर कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर देबराज शोम ने बताया था कि डर्मल फ़िलर्स इंजेक्शन होते हैं जो स्किन के अंदर दिए जाते हैं। ये उसी पदार्थ से बनते हैं, जिससे हमारी त्वचा की कोशिकाएं बनी होती हैं। उन्होंने बताया कि स्किन में उम्र के साथ कोलेजन कम होने लगता है, मगर फ़िलर्स की मदद से कोलेजन वापस डाला जाता है और चेहरा जवान लगने लगता है।

वहीं एंटी एजिंग के लिए कई लोग ग्लूटाथियोन इंजेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को होने वाले डैमेज को रोकने में काम आते हैं। ग्लूटाथियोन अक्सर इंट्रावेनस इंजेक्शन और टैबलेट्स के ज़रिए लिया जाता है। डॉक्टर अंजू झा बताती हैं, 'ग्लूटाथियोन हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद होता है। लेकिन उम्र के साथ-साथ शरीर ग्लूटाथियोन बनाना कम कर देता है। इसलिए इसे बाहर से लिया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि ग्लूटाथियोन लेने वाले लोगों की त्वचा के रंग में थोड़ा निखार आता है। अगर इंट्रावेनस ग्लूटाथियोन लिया जाए तो उसके नतीजे और बेहतर माने जाते हैं। मगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ये एफ़डीए अप्रूव्ड नहीं है।'

बोटॉक्स के जोखिमों पर अप्रैल 2024 में तब चर्चा तेज़ हुई जब यूएस सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) ने एक चेतावनी जारी करते हुए ये कहा कि 25 से 59 साल की 22 महिलाओं में बोटॉक्स के हानिकारक रिएक्शंस देखे गए हैं। इनमें से 11 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और छह लोगों में ऐसी स्थिति पाई गई, जहां बोटॉक्स के ज़रिए दिए गए टॉक्सिन्स फैलकर नर्वस सिस्टम तक पहुंच गए। ये एक ऐसी स्थिति है, जिसमें मौत भी हो सकती है। इस पर डॉक्टर पराशर ने कहा, 'ये साबित हो चुका है कि इन सभी महिलाओं ने बिना लाइसेंस वाले या अप्रशिक्षित लोगों से ऐसी जगह इंजेक्शन लिए, जो हेल्थकेयर सेंटर भी नहीं थे।'

इन दवाओं से होने वाले जोखिम पर डॉक्टर अंजू झा कहती हैं, 'एफ़डीए ने ग्लूटाथियोन को इसलिए अप्रूव नहीं किया क्योंकि देखा गया कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इससे कुछ मरीज़ों को एनाफाईलैक्सिस हो सकता है, इंजेक्टेबल दवाओं से स्टीवन जॉनसन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ये दवाओं के रिएक्शन से पैदा होने वाली स्थितियां हैं, जिसमें मौत की भी आशंका है। हालांकि, ये बहुत दुर्लभ है।' वह कहती हैं कि जो लोग स्किन लाइटनिंग या त्वचा को गोरा करने के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उन पर इसका असर तब तक ही होता है जब तक वो इसे ले रहे हैं। इसका असर, हमेशा नहीं रहता।

डॉक्टर अंजू कहती हैं, 'ये बहुत ज़रूरी है कि आप दवाएं कितनी ले रहे हैं, आपको ये लेनी चाहिए या नहीं। कहीं आपको पहले से कोई दिक्कत तो नहीं, जो इन दवाओं से और बढ़े। इन सबके लिए अच्छे डर्मटोलॉजिस्ट की सलाह चाहिए।' 'इससे (दवाओं से) हार्ट अटैक नहीं हो सकता है। मगर कई बार डोज़ ज़्यादा लेने से ये लिवर, किडनी पर असर डाल सकती हैं। इस तरह के परोक्ष असर हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ये ट्रीटमेंट कोई एक्सपर्ट करे, जिन्हें ये पता हो कि कौन से मसल्स में इंजेक्ट करना है और कितना करना है। ये खुद से न करें, किसी पार्लर में न कराएं, बल्कि किसी ऐसे डॉक्टर से भी न कराएं, जिन्हें जानकारी न हो।'

सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली और खिताब अपने नाम करने वाली तमाम सुंदरियों का सपना अभिनय की दुनिया में नाम कमाने का होता है। ऐसा होता भी आ रहा है।

मिस वर्ल्ड रही हीरोइनों का फिल्मी करियर?

अक्सर कहा जाता है कि फैशन की दुनिया का रास्ता फिल्म इंडस्ट्री में जाकर खुलता है। बात अगर सौंदर्य प्रतियोगिताओं की करें तो इन्हें जीतने वाली सुंदरियां फिल्मों में करियर बनाने का रुख करती हैं और कई पूर्व मिस वर्ल्ड बॉलीवुड में काम कर रही हैं।

सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली और खिताब अपने नाम करने वाली तमाम सुंदरियों का सपना अभिनय की दुनिया में नाम कमाने का होता है। ऐसा होता भी आ रहा है। फिलहाल बात साल 2017 की मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर की करते हैं। फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' से उन्होंने साल 2022 में डेब्यू किया। इन दिनों वे 'मालिक' में नजर आ रही हैं। उनसे पहले और भी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीत चुकीं कई भारतीय सुंदरियों ने सिनेमा की दुनिया में एंट्री ली। जानते हैं किसका करियर कैसा रहा है?

रीता फारिया

रीता फारिया यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और एशियाई मूल की महिला हैं। उन्होंने फिल्म और मॉडलिंग के बजाय अपनी मेडिकल की पढ़ाई पर फोकस करने का फैसला किया। हालांकि, शुरुआती एक साल उन्होंने मॉडलिंग जरूर की, लेकिन फिर पूरा ध्यान अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पर दिया। बता दें कि वे साल 1966 में मिस वर्ल्ड रहीं।

ऐश्वर्या राय बच्चन

ऐश्वर्या राय ने साल 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। उन्होंने इंडस्ट्री में करियर बनाया और उनका करियर सफल रहा है। उन्होंने साउथ फिल्म 'इरुवर' से डेब्यू किया। उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म 'और प्यार हो गया' (1997) है। ऐश्वर्या राय का नाम सिनेमा की दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है। वे बच्चन परिवार की बहू हैं। अभिषेक बच्चन से उन्होंने शादी की है।

डायना हेडन

डायना हेडन ने साल 1997 में मिस वर्ल्ड का ताज पहना। वे बतौर इवेंट मैनेजर काम करती हैं। 2008 में वे रियलिटी शो बिग बॉस में एक सेलिब्रिटी प्रतियोगी के रूप में दिखीं।

युक्ता मुखी

युक्ता मुखी साल 1999 में मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग में भी किस्मत आजमाई। वे कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी हैं। युक्ता मुखी ने साल 2001 में तमिल फिल्म 'पूवेल्लम उन वसम' से डेब्यू किया। साल 2002 में आफताब शिवदासानी के साथ 'प्यासा' के जरिए उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया। साल 2019 में उन्हें फिल्म 'गुड न्यूज' में देखा गया।

प्रियंका चोपड़ा

साल 2000 में प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनीं। सिनेमा की दुनिया में उन्होंने क्या नाम कमाया है, इससे दुनिया वाकिफ है। वे बॉलीवुड की देसी गर्ल हैं। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि हॉलीवुड तक उनका डंका बज रहा है। निक जोनस से शादी के बाद प्रियंका चोपड़ा विदेश में शिफ्ट हो गई हैं।

मानुषी छिल्लर

अब बात करें साल 2017 में मिस वर्ल्ड का ताज पहनने वाली मानुषी छिल्लर की तो उन्होंने साल 2022 में अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' से डेब्यू किया। यह फिल्म फ्लॉप रही। फिर वे द ग्रेट इंडियन फैमिली, बड़े मियां छोटे मियां में नजर आईं और ये दोनों फिल्में भी फ्लॉप रहीं। फिलहाल वे राजकुमार राव के साथ 'मालिक' में नजर आ रही हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है।

मिस यूनिवर्स बनीं भारतीय सुंदरियों का करियर

अब तक तीन भारतीय महिलाओं ने मिस यूनिवर्स खिताब अपने नाम किया है। साल 1994 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनीं। एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने खूब नाम कमाया है। साल 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनीं। उन्होंने भी कई फिल्मों में काम किया। हालांकि, फिलहाल वे इंडस्ट्री से दूर हैं। उन्होंने टेनिस स्टार महेश भूपति से शादी रचाई है। साल 2021 में हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया। वे सिनेमा में एंट्री ले चुकी हैं, मगर अभी पंजाबी इंडस्ट्री तक सीमित हैं। फिल्म 'बागी 4' से वे बॉलीवुड में डेब्यू करने को तैयार हैं। फ्रं

ओटीटी के दीवानों के लिए इस बार जुलाई काफी खास होने वाला है। जुलाई में इस बार बरसते सावन के बीच एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस और रोमांटिक फिल्मों और सीरीज अलग-अलग प्लेटफार्म्स पर दस्तक देने जा रही हैं। 4 से लेकर 6 जुलाई तक कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रोमांच, सस्पेंस और एक्शन से भरपूर फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं, जो आपके बिंज-वॉचिंग प्लान को पूरी तरह कम्पलीट कर देंगी।

एक्शन, रोमांच और कॉमेडी का मसालेदार का तड़का

मोनिका गुप्ता

इंटरटेनमेंट का बूस्टर डोज

सिनेमा लवर्स के लिए जुलाई 2025 एंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाली है। बॉक्स ऑफिस पर पूरे महीने एक के बाद एक कई फिल्में रिलीज होगी। जुलाई के महीने में रिलीज होने वाली 8 हिंदी फिल्मों में 7 साथ सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जबकि एक ओटीटी प्लेटफार्म पर रिलीज होगी। आइए जानते हैं इन फिल्मों के नाम और रिलीज डेट। जुलाई के महीने में मेट्रो इन दिनों फिल्म से खाता खुलेगा, तो वहीं सन ऑफ सरदार 2 इस महीने की रिलीज होने वाली आखिरी फिल्म होगी, इसके बीच में तन्वी द ग्रेट, मालिक, आप जैसा कोई, सैयारा, आंखों की गुस्ताखियां और परम सुंदरी जैसी फिल्में रिलीज होगी।

4 जुलाई को रिलीज होगी मेट्रो इन दिनों

4 जुलाई को इस महीने की पहली फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। मेट्रो इन दिनों फिल्म में आदित्य रॉय कपूर और सारा अली खान मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कैसा प्रदर्शन होगा यह आने वाले वक्त में पता चलेगा।

11 जुलाई को रिलीज होगी तीन फिल्में

आंखों की गुस्ताखियां और मालिक फिल्म 11 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे के आमने-सामने होगी। 11 जुलाई को यह दो फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसके अलावा आर माधवन और फातिमा सना शेख की फिल्म आप जैसा कोई फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। आंखों की गुस्ताखियां में विक्रांत मैसी शनाया कपूर के साथ नजर आने वाले हैं। तो वहीं मालिक फिल्म में राजकुमार राव हुमा कुरैशी के साथ नजर आएंगे।

18 जुलाई को रिलीज होगी 2 फिल्में

अनुपम खेर की तन्वी द ग्रेट और अहान पांडे की डेब्यू फिल्म सैयारा 18 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे के सामने होगी। दोनों ही फिल्मों के ट्रेलर को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिला है।

25 जुलाई को सन ऑफ सरदार और परम सुंदरी की होगी टक्कर

अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म परम सुंदरी 25 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर आमने-सामने होंगे। कौन सी फिल्म तगड़ा प्रदर्शन करेगी या आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि जुलाई के महीने में फिल्मों का क्लैश बहुत अधिक देखने को मिल रहा है।

'गुड वाइफ'

लंबे वक्त से बड़े पर्दे से गायब रहीं अभिनेत्री प्रियामणि अब डिजिटल स्क्रीन पर 'गुड वाइफ' के जरिए वापसी कर रही हैं। ये सीरीज एक ऐसी महिला की कहानी है, जो कभी एक वकील थी और अब गृहिणी बन चुकी है। लेकिन जब उसका पति एक बड़े स्कैंडल में फंस जाता है, तो उसे फिर से अदालत की लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसमें आपको रिश्तों की उलझन और न्याय के लिए संघर्ष देखने को मिलेगा। निर्देशक रेवती के लिए भी ये डिजिटल डेब्यू है, जिससे दर्शकों को इस शो से काफी उम्मीदें हैं।

द हंट

सोनी लिव पर रिलीज होने जा रही 'द हंट' भारत के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या पर आधारित है। ये शो 1991 के उस आत्मघाती हमले और उसके बाद सीबीआई द्वारा की गई 90 दिन की तफ्तीश को बारीकी से दर्शाता है। इस सीरीज में अमित सियाल, साहिल वैद और बगवती पेरुमल जैसे दमदार कलाकार नजर आएंगे।

कालीधर लापता

अभिषेक बच्चन एक बार फिर दर्शकों को इमोशनल सफर पर ले जाने को तैयार हैं। 'कालिधर लापता' एक वृद्ध व्यक्ति की कहानी है, जिसे लगता है कि उसका परिवार उसे छोड़ना चाहता है। वो तय करता है कि अब वह अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएगा। इस सफर में उसकी मुलाकात होती है एक 8 साल के अनाथ बच्चे बल्लू से। दोनों के बीच बनती अनोखी दोस्ती इस फिल्म की आत्मा है।

उप्पू कपुरंबु

तेलुगु दर्शकों के लिए 'उप्पू कपुरंबु' एक हल्की-फुल्की लेकिन गहरी बात कहने वाली कॉमेडी फिल्म है। गांव की नई महिला सरपंच बनी अपूर्वा (कीर्ति सुरेश) कब्रिस्तान में जगह की समस्या से जूझती है। इसमें उनका साथ देता है अजीबोगरीब कब्र रक्षक 'चिन्ना'। ये फिल्म गांव की राजनीति, पागलपन और व्यंग्य से भरी है जो दर्शकों को हंसी के साथ काफी चीजें सोचने पर मजबूर कर देगी।

इन द लॉस्ट लैंड्स

अगर आप फैंटेसी और ऐक्शन के फैन हैं तो 'इन द लॉस्ट लैंड्स' आपके लिए है। हॉलीवुड एक्ट्रेस मिला जोवोविच एक रहस्यमयी जादूगरनी के रोल में नजर आएंगी जो एक रानी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए खतरनाक यात्रा पर निकलती है। उनके साथ डेव बटिस्टा भी अहम भूमिका में हैं। जॉर्ज आर.आर. मार्टिन की कहानी पर आधारित ये फिल्म विजुअल्स, जादू और रहस्यों से भरपूर है।

'ब्रिक'

नेटफ्लिक्स पर इस थ्रिलर फिल्म को 10 जुलाई को रिलीज होगी। इसकी कहानी एक ऐसे अपार्टमेंट के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अचानक एक रहस्यमयी ईंट की दीवार से घिर जाता है। टिम और ओलिविया जैसे किरदारों को अब न सिर्फ इस घुटन भरे माहौल से जूझना है, बल्कि अपने अतीत और पड़ोसियों के खतरनाक राजों से भी सामना करना है। ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो सस्पेंस और साइकोलॉजिकल हॉरर का मजा लेना चाहते हैं।

'आप जैसा कोई'

आर माधवन और फातिमा सना शेख की ये लवस्टोरी नेटफ्लिक्स पर 11 जुलाई स्ट्रीम होगी। झारखंड के जमशेदपुर से ताल्लुक रखने वाले शांत स्वभाव के प्रोफेसर श्रीरेणु त्रिपाठी को जब एक फ्रेंच टीचर मधु बोस से प्यार होता है, तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। पारिवारिक दबाव, सामाजिक सीमाएं और प्यार के जज्बातों से भरी ये फिल्म दर्शकों को एक इमोशनल सफर पर ले जाएगी।

'ऑलमोस्ट कॉप्स'

डच कॉमेडी सीरीज 'ऑलमोस्ट कॉप्स' नेटफ्लिक्स पर 11 जुलाई रिलीज होगी। इस सीरीज में एक अफसर और एक बदनाम पूर्व जासूस की कहानी दिखाई गई है जो लोगों की सुरक्षा से ज्यादा खुद की उलझनों में फंसी दिखाई देती है।

'नारीवेट्टा'

2003 के मुथंगा आदिवासी आंदोलन से प्रेरित मलयालम फिल्म 'नारीवेट्टा' सोनी लिव पर 11 जुलाई से स्ट्रीम होगी। टोविनो थॉमस, सूरज वेंजारामूड और चेरन जैसे कलाकारों के साथ ये फिल्म समाज में न्याय और बदले की कहानी कहती है। ये उन दर्शकों के लिए है जो थ्रिलर कंटेंट देखना पसंद करते हैं।

'फोर इयर्स लेटर'

शादी के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए यश और इंडिया में रह गई श्रीदेवी, अब चार साल बाद जब दोनों दोबारा मिलते हैं, तो प्यार, नाराजगी और सवालों की एक नई कहानी शुरू होती है। शहाना गोस्वामी और अक्षय अजित सिंह की ये इमोशनल ड्रामा फिल्म लायंसगेट प्ले पर 11 जुलाई से रिलीज होगी।

'मेडियाज डेस्टिनेशन वेडिंग'

'मेडियाज डेस्टिनेशन वेडिंग' टायलर पेरी द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी फिल्म है जो 11 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। ये फिल्म मेडिया की कहानी है, जो अपनी पोती की अचानक शादी के लिए बहामास जाती है। फिल्म में पेरी एक बार फिर मेडिया की भूमिका निभाएंगे।

सकामोटो डेज सीजन 1

हफ्ते की शुरुआत इस एनिमेशन सीरीज से हो रही है। इस हफ्ते इस सीरीज के पहले सीजन का दूसरा पार्ट आ रहा है। बता दें कि यह एक एनिमेशन सीरीज है और 14 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

स्पेशल ऑप्स 2

चर्चित सीरीज 'स्पेशल ऑप्स' का दूसरा सीजन यूं तो बीते हफ्ते रिलीज होना था और तारीख थी 11 जुलाई। मगर, यह तय तारीख पर रिलीज नहीं हो सकी। मगर, इस हफ्ते यह सीरीज आपका मनोरंजन करने आ रही है। के के मेनन हिम्मत सिंह के रूप में वापसी कर रहे हैं। 18 जुलाई से 'स्पेशल ऑप्स 2' जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी।

10 जुलाई से कांवरयात्रा पर निकलने वालों का रेला भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों की ओर उमड़ेगा, इस क्रम में बाबा नगरी देवघर में भी शिवभक्त अपनी मनोकामना के साथ पहुंचेंगे और उनका जलाभिषेक करेंगे। देवघर के बाबा वैद्यनाथ हैं जो भक्तों को शारीरिक कष्टों से मुक्ति देते हैं, सावन के महीने से उनका अटूट संबंध है। चूंकि चातुर्मास की शुरुआत के साथ ही भगवान विष्णु शयन के लिए जा चुके हैं, इसलिए इस महीने में भगवान शिव पर सृष्टि की पूरी जिम्मेदारी होती है, इसलिए भी उनका महत्व काफी बढ़ जाता है।

स्मिता साबत

भगवान शंकर की पूजा का खास महीना

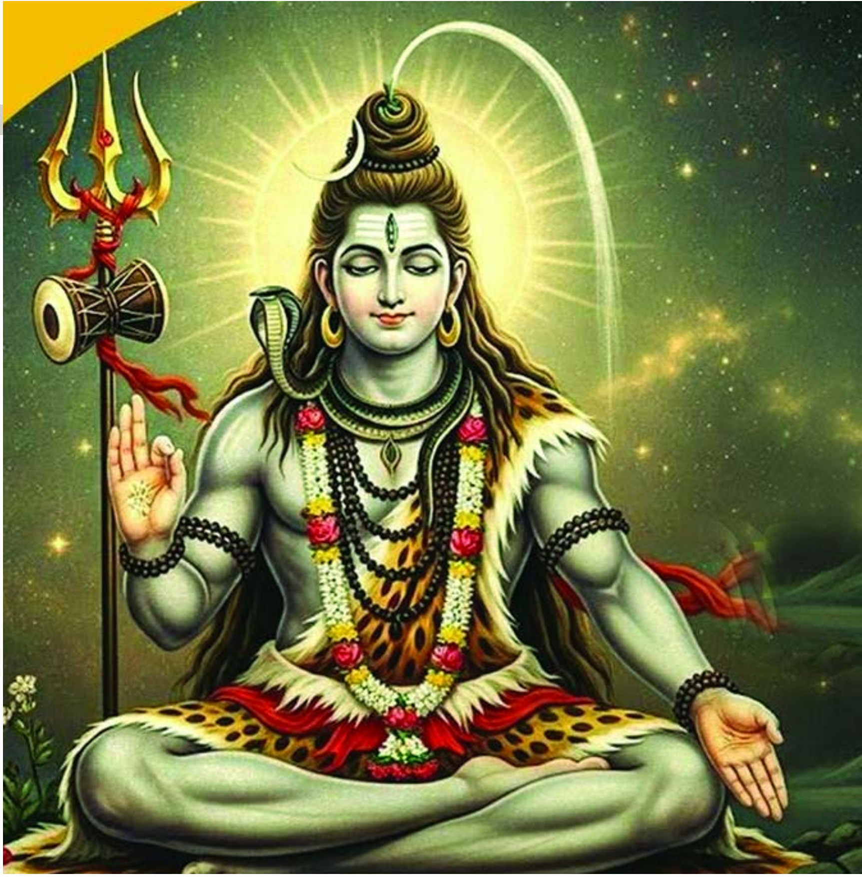

सावन का पवित्र महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यह महीना बहुत ही खास है और यह भगवान शंकर का सबसे प्रिय महीना है। सावन के महीने में भगवान शंकर पर जलाभिषेक की परंपरा है। यही वजह है कि सावन के महीने में शिवालयों में भीड़ उमड़ पड़ती है। जिन राज्यों में भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग हैं वहां तो एक दिन में लाखों श्रद्धालु भगवान का जलाभिषेक करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। झारखंड की बाबा नगरी देवघर में हर साल लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं। यहां का शिवलिंग रावण द्वारा स्थापित है और भगवान शंकर के वैद्यनाथ स्वरूप की पूजा होती है, जिसका रावण से गहरा संबंध है। इस मौके पर देवघर के बाबा मंदिर में पूरे एक माह का मेला लगता है जिसकी शुरुआत 10 जुलाई को हो जाएगी।

क्या है देवघर के बाबा मंदिर का महत्व

पौराणिक कथाओं के अनुसार देवघर में भगवान शिव का लिंग रावण ने स्थापित किया था। एक बार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और अपना एक-एक सिर काट कर भगवान के सामने अर्पित कर दिया। जब उसने अपना दसवां सिर भगवान के सामने अर्पित करना चाहा तो भगवान ने प्रकट होकर उसे वरदान दिया। तब रावण ने उन्हें अपने साथ लंका चलने को कहा, तब वरदान स्वरूप भगवान ने अपना स्वरूप शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग के रूप में उन्हें दिया और शर्त रखी कि तू शिवलिंग को धरती पर जहां कहीं भी रखेगा मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने खुश होकर सहमति दी और लंका की ओर चल पड़ा।रावण की इस सफलता पर देवता भयभीत हो गए और उन्हें लगा कि अगर रावण भगवान को अपने साथ ले गया तो वह और ताकतवर हो जाएगा, तब सबसे भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने वरुण देव से कहा कि रावण के पेट में जल भर दें, ताकि उसे लघुशंका लग जाए। जब रावण को तीव्र लघुशंका महसूस हुई, तो उसने देवघर में एक बच्चे को जो ग्वाले के भेष में भगवान विष्णु थे, देकर लघुशंका के लिए चला गया। रावण के जाते ही भगवान विष्णु ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और वहां से चले गए। रावण जब आया तो उसने शिवलिंग को जमीन पर पाया, उससे उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह वहां से हिला नहीं। तब आकाशवाणी हुई कि अब शिवलिंग वहीं पर रहेगा। चूंकि भगवान शंकर ने रावण के कटे हुए सिर की चिकित्सा की थी जिससे रावण को कष्ट से मुक्ति मिली थी इसलिए देवघर के भगवान शिव को वैद्यनाथ कहा जाता है और इस ज्योतिर्लिंग की पूजा शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति के लिए की जाती है।

मनोकामना देव हैं बाबा

देवघर के बाबा मंदिर की विशेषता यह है कि यहां स्थापित बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसलिए यहां मन्नत मांगने वालों की भीड़ उमड़ती है और भक्त अपनी मनोकामना सिद्धि पर यहां विशेष पूजा भी करते हैं। देवघर के बाबा ने रावण की भी मनोकामना पूर्ण की थी और उसके साथ ज्योतिर्लिंग के रूप में लंका जा रहे थे, लेकिन अहंकार की वजह से उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई।

सावन में क्यों होती है भगवान शिव की पूजा

पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर सावन के महीने में ही समुद्र मंथन किया था, जिससे सबसे पहले हलाहल विष निकला। हलाहल विष को अत्यंत भयंकर विष माना जाता है, जिसके प्रभाव से लोगों की तुरंत मृत्यु संभव है। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, तो उसके प्रभाव से देवता और दानव जलने लगे तब सृष्टि के संहारकर्ता, आदिदेव शिव ने उस जहर का पान कर लिया और उसे अपने कंठ में रख लिया। विष के प्रभाव से उसके शरीर में तीव्र ताप उत्पन्न हो गया, जिसे शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शंकर पर जल अर्पित किया, उसी वक्त से सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है।

सावन का महीना भगवान शिव को है प्रिय

माता पार्वती ने सावन के महीने में ही भगवान शिव को पाने के लिए कठिन व्रत किया था। माता पार्वती ने सोमवार को कठिन व्रत भी किया था। इसी वजह से भगवान शंकर को सोमवार का दिन और सावन का महीना बहुत प्रिय है। सावन में सोमवार के व्रत का भी विधान है और कहते हैं कि सोमवार का व्रत करने से भगवान शंकर मन वांछित फल देते हैं। लड़कियां अगर सोमवार का व्रत करें, तो उन्हें इच्छित वर की प्राप्ति होती है।

सावन के महीने में कांवर यात्रा और जलाभिषेक

सावन के महीने में बिहार-झारखंड के लोग कांवर यात्रा पर जाते हैं, जिसमें वे बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरते हैं और 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद देवघर पहुंचकर उनका जलाभिषेक करते हैं। यह यात्रा कठिन है, लेकिन भक्तिभाव से भक्त इसे पूरा करते हैं और पूरे रास्ते बोलबम का नारा लगाते हुए जाते हैं। भगवान शिव आशुतोष हैं वो अपने भक्त के इतने समर्पण भाव ने तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कामनापूर्ति करते हैं।

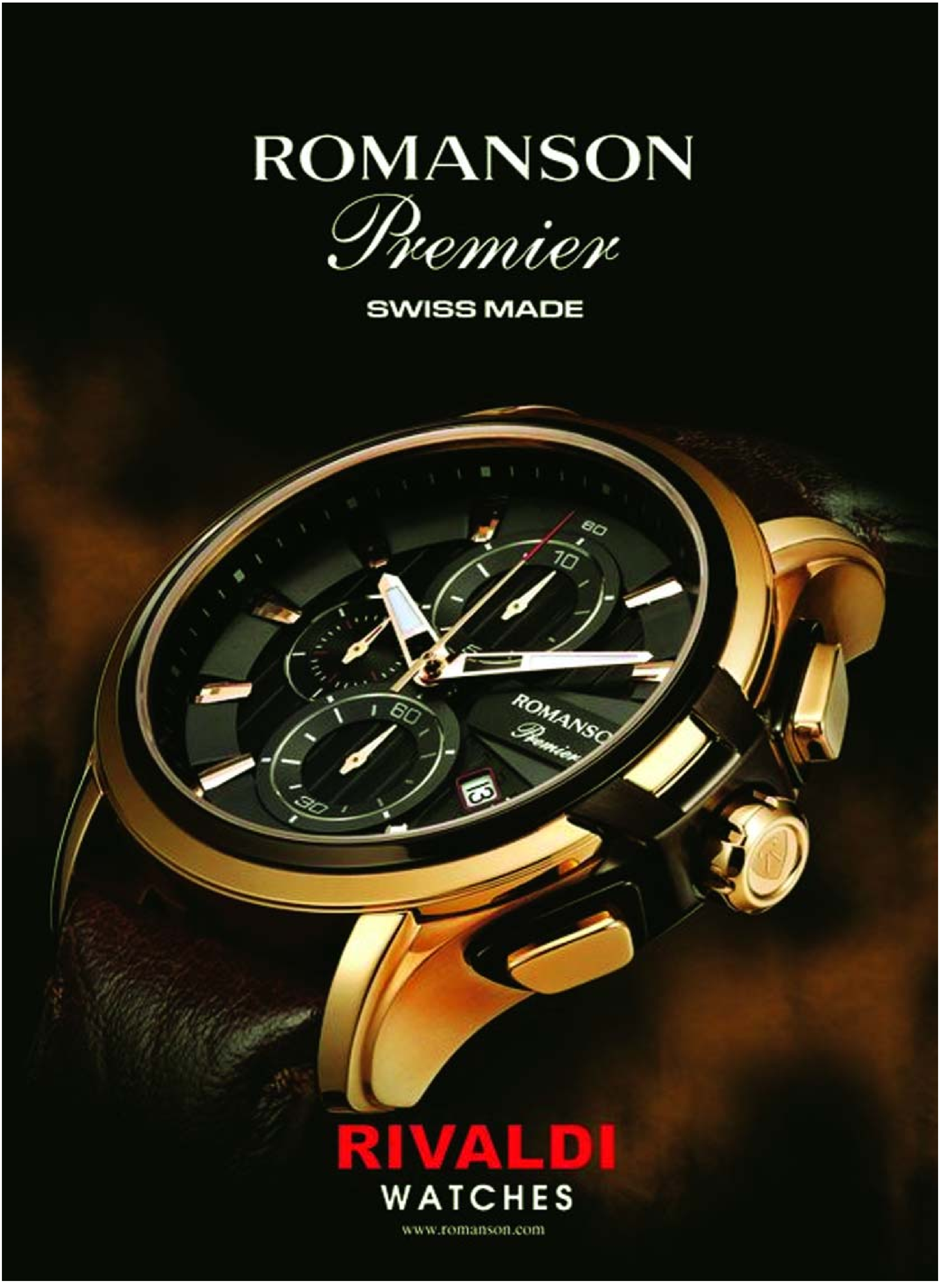
ROMANSON
Premier
SWISS MADE
ROMANSON
Premier
RIVALDI
WATCHES
www.romanson.com

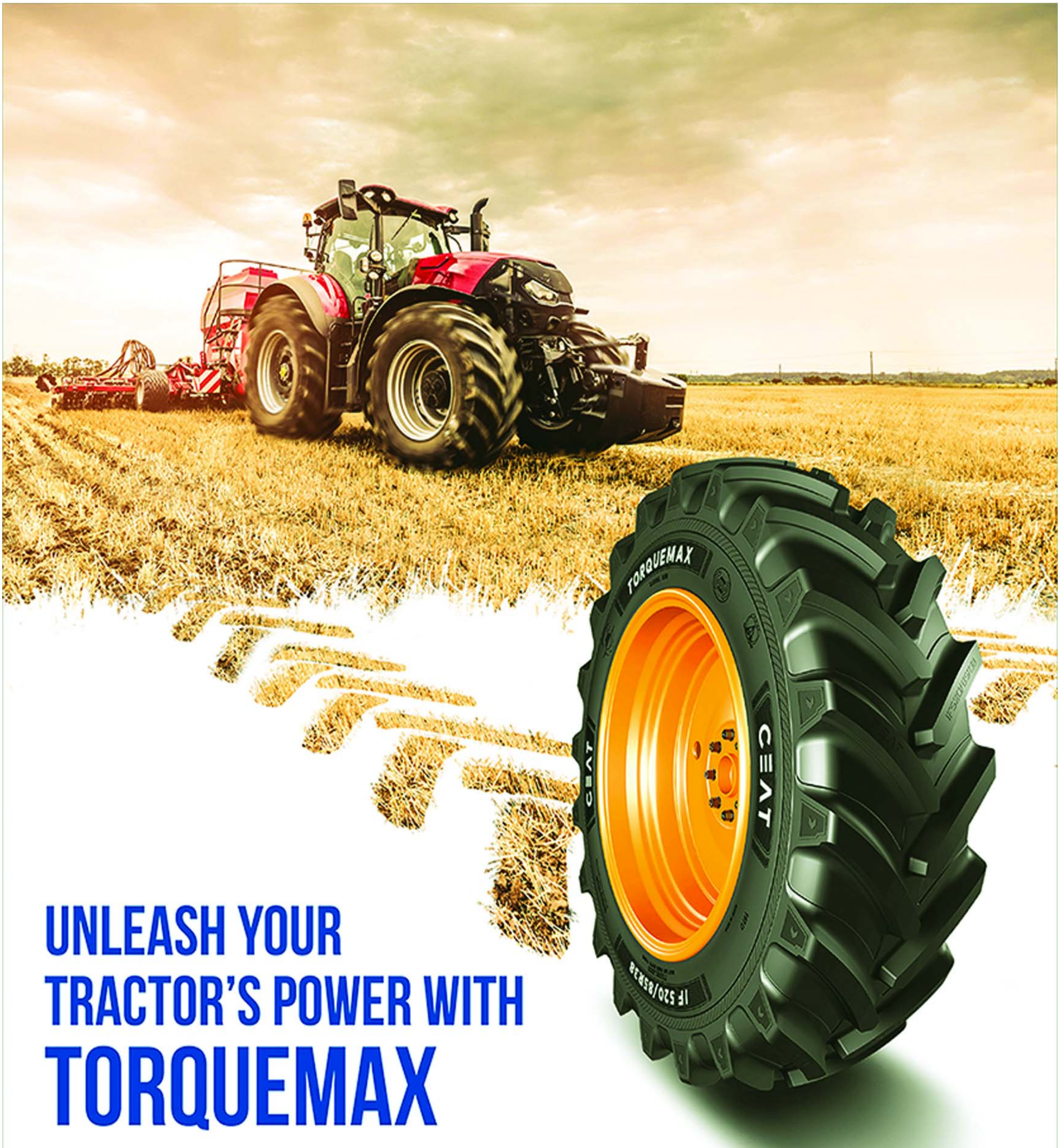

UNLEASH YOUR TRACTOR'S POWER WITH TORQUEMAX

Engineered to undertake all demands of the field and road with ease.

- Low soil compaction
- High traction
- Superior grip

Also, launching in **IF** (Increased Flexion) Technology

CEAT SPECIALTY